● वर्ष-3
● अंक-305
रायपुर, शनिवार
03 अगस्त 2024
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.
samacharpacheesa@gmail.com

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-6›› किडनी की बीमारी में आपका शरीर...

भारतीय हॉकी टीम ने रचा इतिहास

52 साल बाद ऑस्ट्रेलिया को ओलंपिक में हराया

पेरिस। पेरिस ओलंपिक 2024 के 7वें दिन भारतीय हॉकी टीम ने इतिहास रच दिया है। दरअसल, हरमनप्रीत सिंह की कप्तानी में टीम ने 52 साल बाद ऑस्ट्रेलियाई हॉकी टीम को 3-2 से मात दी है। इससे पहले भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 1972 में आखिरी बार हराया था। साथ ही टीम ने क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत इस जीत के साथ ग्रुप बी में दूसरे नंबर पर पहुंच गई है। वहीं भारतीय टीम पेरिस ओलंपिक के ग्रुप बी में है, बेल्जियम इस ग्रुप में चारों मैच जीतकर टॉप पर हैं। ऑस्ट्रेलिया 9 अंक के साथ तीसरे और भारत 10 अंकों के साथ दूसरे नंबर है। भारत इससे पहले बेल्जियम से हार गए लेकिन उन्होंने इस कड़ी में न्यूजीलैंड और आयरलैंड को हराया है। जबकि अर्जेंटीना के साथ 1-1 से ड्रॉ किया। भारत की तरफ से अभिषेक ने 1 तो कप्तान हरमप्रीत सिंह ने 2 गोल दागे। ऑस्ट्रेलिया के लिए थॉमस क्रेग और ब्लेक गोवर्स ने गोल किए। पहले क्वार्टर फाइनल की शुरुआत में भारत ने ऑस्ट्रेलिया पर दबाव बनाया और इसके चलते मैच के 12वें मिनट में अभिषेक ने शानदार काउंटर अटैक कर फील्ड गोल मार दिया। गोल के तुरंत बाद भारतीय टीम को पेनल्टी कॉर्नर भी मिला। इस मौके को कप्तान हरमनप्रीत ने नहीं गंवाया और अगले ही मिनट में गोल दागकर स्कोर 2-0 कर दिया। पहले हाफ की समाप्ति तक स्कोर 2-0 से भारत के पक्ष में रहा। दूसरे क्वार्टर में ऑस्ट्रेलिया के थॉमस क्रेग ने शानदार फील्ड गोल दागा और स्कोर 2-1 पर ला दिया। इसके बावजूद भारत दबाव में नहीं आया और 32वें मिनट में टीम को एक पेनल्टी स्ट्रोक मिला और कप्तान हरमनप्रीत ने 1 और गोल दाग दिया। हरमप्रीत सिंह ने पेरिस ओलंपिक 2024 में 6 गोल ला चुके हैं।

शाह के खिलाफ कांग्रेस ने की विशेषाधिकार हनन की शिकायत

वायनाड हादसे में झूठे दावे का आरोप

नई दिल्ली। केरल के वायनाड में भूस्खलन पर उनके दावे को लेकर कांग्रेस द्वारा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ शुक्रवार को एक विशेषाधिकार शिकायत दायर की गई। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने अमित शाह के खिलाफ विशेषाधिकार नोटिस पेश किया। विशेषाधिकार नोटिस में अमित शाह के इस दावे पर आपत्ति जताई गई है कि वायनाड में भूस्खलन से पहले केरल सरकार को शुरुआती चेतावनी दी गई थी।

शाह ने यह भी दावा किया था कि केरल सरकार ने चेतावनियों पर कार्रवाई नहीं की, विशेषाधिकार नोटिस में जयराम रमेश ने इस दावे का खंडन किया था। विशेषधिकार नोटिस में कहा गया कि यह स्पष्ट है कि केंद्रीय गृह मंत्री ने केंद्र सरकार द्वारा जारी प्रारंभिक चेतावनियों पर अपने जोरदार बयानों से राज्यसभा को गुमराह किया जो कि झूठी साबित हुई हैं।

31 जुलाई को राज्यसभा में एक संबोधन के दौरान गृह मंत्री ने दावा किया था कि भूस्खलन के बारे में केरल सरकार को 23 जुलाई को पूर्व चेतावनी दी गई थी। उन्होंने कहा कि मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि घटना से सात दिन पहले 23 जुलाई को केंद्र ने केरल सरकार को प्रारंभिक चेतावनी दी थी और फिर 24 और 25 जुलाई को हमने उन्हें फिर से चेतावनी दी थी। 26 जुलाई को एक चेतावनी दी गई थी कि 20 सेमी से अधिक भारी वर्षा होने की संभावना थी और भूस्खलन की भी संभावना थी। वायनाड में हुए कई भूस्खलनों में 300 से अधिक लोगों की मौत हो गई है और ढही इमारतों और मलबे के नीचे फंसे बचे लोगों की तलाश जारी है।

200 से अधिक लोगों को चोटें आईं क्योंकि बचाव कार्य विभिन्न चुनौतियों के कारण बाधित हुए, जिनमें नष्ट हुई सड़कों और पुलों के कारण खतरनाक इलाके और उपकरणों की कमी

और भारी उपकरणों की कमी शामिल थी। ऐसी स्थितियों में आपातकालीन कर्मियों के लिए घरों और अन्य इमारतों पर गिरे कीचड़ और उखड़े पेड़ों को हटाना मुश्किल हो गया।

मुझे मनमोहन सिंह जैसा नहीं होनाः सीतारमण

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को देश में शिक्षा और असमानता पर अपनी टिप्पणियों के लिए टीएमसी के सौगत रॉय की आलोचना की। उन्होंने लोकसभा में रॉय की टिप्पणी का हवाला दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुझे उम्मीद नहीं है

कि वित्त मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह जैसे होंगे। उन्होंने ऑक्सफोर्ड से पीएचडी नहीं की है। चिदम्बरम की तरह भी नहीं, जिनके पास हार्वर्ड से प्रबंधन की डिग्री है। वह हमारे ही जेएनयू से है। लेकिन समस्या यह है कि वह नए विचारों से वंचित है।

सीतारमण ने कहा, निश्चित रूप से, मैं भी मनमोहन सिंह की तरह नहीं बनना चाहती,%% लेकिन उन्होंने टीएमसी के दिग्गज नेता से पूछा कि क्या भारत में पढ़ाई करने वाली पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री भी विचारों से रहित हैं। उन्होंने बजट 2024 पर चर्चा का जवाब देते हुए रॉय से पूछा कि पश्चिम बंगाल की वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने कलकत्ता विश्वविद्यालय से पढ़ाई की है। क्या वह भी नए विचारों से वंचित हैं? सीतारमण ने कहा कि भट्टाचार्य जीएसटी परिषद में अद्भुत योगदान देती हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि बंगाल की मुख्यमंत्री भी कलकत्ता विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेज से थीं। उन्होंने पूछा, वह एक लड़ाकू हैं जो इतने सालों तक राज्य का नेतृत्व कर रही हैं। क्या इसका मतलब यह है कि यदि आप भारतीय विश्वविद्यालयों में पढ़ते हैं, तो आप विचारों से रहित हैं? उन्होंने कहा कि चाहे वह बंगाल की मुख्यमंत्री हों या मैं, हम भारतीय विश्वविद्यालयों से हैं। किस तरह से, हम दुनिया के हार्वर्ड और दुनिया के ऑक्सफ़ोर्ड से कमतर हैं?

उन्होंने कहा कि मैं यह उस पुरुष अंधराष्ट्रवादी प्रोफेसर से पूछना चाहता हूं, जो महिलाओं पर हमला करता नजर आता है। इससे भी बुरी बात यह है कि वह भारतीय कॉलेजों में से एक में प्रोफेसर हैं। वह हार्वर्ड में नहीं पढ़ा रहे हैं। वह ऑक्सफोर्ड में नहीं पढ़ा रहे हैं। क्या वह भी उतना योग्य नहीं है? भारतीय विश्वविद्यालय का एक प्रोफेसर उन लोगों को अपमानित करता है जिन्होंने भारतीय विश्वविद्यालय से योग्यता प्राप्त की है। प्रोफेसर सौगत रॉय, कृपया खुद पर शर्म करें।

घुसपैठ रोकना सिर्फ केंद्र की नहीं, सभी की जिम्मेदारी : मुख्यमंत्री हिमंत

नई दिल्ली। असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने शुक्रवार को कहा कि घुसपैठ रोकना केवल केंद्र सरकार की नहीं बल्कि सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए राहुल गांधी से वह ''फॉर्मूला'' भी जानना चाहा कि ''अपनी जाति बताए बिना जाति सर्वेक्षण कैसे किया जाए।''

भाजपा के झारखंड चुनाव सह-प्रभारी शर्मा ने यहां संवाददाताओं से बातचीत में कहा, ''झारखंड का संथाल परगना घुसपैठ से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। पिछले 20 वर्षों में इस क्षेत्र के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में घुसपैठियों की आबादी 50-60 प्रतिशत बढ़ गई है और स्थिति असम जैसी हो सकती है।'' उन्होंने दावा

किया कि असम में मुस्लिम आबादी 1952 के 12 प्रतिशत से बढ़कर वर्तमान में 40-42 प्रतिशत हो गई है, जिसका मुख्य कारण घुसपैठ है। शर्मा ने कहा, ''अगर घुसपैठ जारी रही तो वह दिन दूर नहीं जब मुख्यमंत्री को उनके (घुसपैठियों के) सामने आत्मसमर्पण करना पड़ेगा। यह कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बल्कि राज्य को बचाना सभी की जिम्मेदारी है।

बैडमिंटन पुरुष एकल क्वार्टर फाइनल में लक्ष्य सेन की जीत

लक्ष्य सेन बैडमिंटन में पुरुष एकल सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं, ऐसा करने वाले वे पहले भारतीय हैं। लक्ष्य ने ताइवान के चू टिन चेन को 19-21, 21-15, 21-12 से हराया। लक्ष्य सेन ने भारतीय बैडमिंटन में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे के चू टिन चेन के खिलाफ तीन गेम की रोमांचक जीत के साथ सेन उस मुकाम पर पहुंच गए हैं, जहां कोई भी भारतीय पुरुष शटलर पहले नहीं पहुंच पाया है। लक्ष्य अब ओलंपिक में बैडमिंटन पुरुष एकल के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय पुरुष शटलर बन गए। अब वह पदक से सिर्फ एक जीत दूर हैं। लक्ष्य से पहले किदांबी श्रीकांत (2016) और पारुपल्ली कश्यप (2012) क्वार्टर फाइनल में पहुंचे थे।

2027 तक 42 अरब डॉलर के निवेश का लक्ष्य, भारत और जापान ट्रेड पर जयशंकर ने कहा

नई दिल्ली। सेंटर फॉर एयर पावर स्टडीज में 7वें जसजीत सिंह मेमोरियल लेक्चर में विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कहा कि विश्व मामलों को आकार देने में बढ़ते राष्ट्रवाद की भूमिका को भी पहचाना जाना चाहिए। दुनिया के उन हिस्सों में जहां पुराना वैश्वीकरण मंत्र अभी भी प्रचलित है। सच्चाई यह है कि यह कई विकसित समाजों में निराशा को दर्शाता है जहां खराब भू-राजनीतिक और भू-आर्थिक विकल्पों के कारण जीवन की गुणवत्ता खराब हो गई है। चाहे आप इसे पसंद करें या न करें लेकिन निकट भविष्य में दुनिया में राष्ट्रवादी काफी बढ़ जाएगा।

प्रमुख समाचार

अब तीन छात्रों की हुई मौतों की जांच सीबीआई करेगी

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने राजेंद्र नगर में तीन यूपीएससी अभ्यर्थियों की मौत की जांच सीबीआई को सौंप दी। अदालत ने इस निर्णय के कारणों के रूप में घटनाओं की गंभीरता और लोक सेवकों द्वारा भ्रष्टाचार में संभावित संलिप्तता का हवाला दिया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) को सिविल सेवा अभ्यर्थियों की मौत की सीबीआई जांच की निगरानी के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी को नामित करने का निर्देश दिया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को यूपीएससी अभ्यर्थियों की डूबने से हुई मौत पर अविश्वास जताया और कहा कि उसे समझ नहीं आ रहा कि छात्र कैसे बाहर नहीं आ सके। पीठ ने पूछा कि दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के अधिकारियों ने क्षेत्र में काम नहीं कर रहे बरसाती पानी के नालों के बारे में आयुक्त को सूचित क्यों नहीं किया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने कहा कि एमसीडी अधिकारियों को कोई परेशानी नहीं है और यह एक आदर्श बन गया है।

उत्तराखंड में आपदाः अब तक 6,980 लोगों का रेस्क्यू

रुद्रप्रयाग। गौरीकुंड-केदारनाथ पैदल मार्ग पर अतिवृष्टि के बाद से रेस्क्यू जारी है। करीब 150 लोगों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। अब तक 6,980 लोगों का रेस्क्यू हो चुका है। शुक्रवार को 2980 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। 599 को हेलिकॉप्टर से लाया गया है। जबकि 1500 से अधिक लोग अभी भी फंसे होने की सूचना है। एसपी डॉ. विशाखा अशोक भदाणे ने बताया कि इन लोगों को शनिवार को रेस्क्यू किया जाएगा। 150 से अधिक लोगों के परिजनों ने पुलिस को बताया है कि उनका अपने लोगों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। ये सभी केदारनाथ गए थे। इनमें कई स्थानीय भी हैं। इन्हें शनिवार को निकाला जाएगा। एसपी का कहना है कि क्षेत्र में मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं होने से भी लोगों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। इसलिए कितने लोग लापता हैं, सीधे तौर पर नहीं बताया जा सकता है, रेस्क्यू पूरा होने पर स्थिति साफ होगी। कई लोग शुक्रवार को घर पहुंच गए हैं।

ट्रेन में मिली बेबी बर्थ की सुविधा, रेल मंत्री ने दी जानकारी

नई दिल्ली। भारतीय रेलवे के उत्तर रेलवे (एनआर) जोन ने ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए एक और कदम उठाया है। उत्तर रेलवे ज़ोन के लखनऊ मंडल ने एक विशेष व्यवस्था की है और विशेष रूप से निचली बर्थ में बच्चों के लिए एक निचली बर्थ जोड़ी है। लखनऊ मंडल ने एक अतिरिक्त छोटी बर्थ जोड़ी है। इस बर्थ को %बेबी बर्थ% भी कहा जा रहा है। यह बेबी बर्थ छोटे बच्चों के लिए है। यह बर्थ उन महिला यात्रियों के लिए फायदेमंद साबित होगी जो अपने बच्चों के साथ बाहर जाती हैं और अपने साथ यात्रा कर रहे बच्चों को अतिरिक्त बर्थ पर बिठाकर इसका लाभ उठा सकती हैं। रेलवे सुरक्षा उपाय के तौर पर बर्थ के बगल में एक स्टॉपर भी उपलब्ध कराएगा ताकि छोटा बच्चा सोने के दौरान नीचे न गिरे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि भारतीय रेलवे ने शिशुओं के साथ माताओं की यात्रा को आसान बनाने के लिए लखनऊ मेल में प्रायोगिक तौर पर दो बेबी बर्थ उपलब्ध कराए हैं।

शुभांशु शुक्ला जाएंगे अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन

नई दिल्ली। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने शुक्रवार को घोषणा की कि ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) के लिए आगामी भारत-अमेरिका मिशन के लिए चुना गया है। इसरो के सूत्रों ने बताया कि ऐसा नासा द्वारा मान्यता प्राप्त सेवा प्रदाता एक्सिओम स्पेस इंक की सिफारिश पर किया गया है। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में इसरो ने कहा कि उसके मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र ने आईएसएस के लिए अपने चौथे मिशन के लिए अमेरिका के एक्सिओम स्पेस इंक के साथ अंतरिक्ष उड़ान समझौता किया है और 'नेशनल मिशन असाइनमेंट बोर्ड' ने दो गगनयात्रियों (अंतरिक्ष यात्रियों) - ग्रुप कैप्टन शुक्ला (प्रधान) और ग्रुप कैप्टन नायर के नाम की सिफारिश की है। इसरो ने कहा, ''नियुक्त चालक दल के सदस्यों को बहुपक्षीय चालक दल संचालन पैनल (एमसीओपी) द्वारा अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर उड़ान भरने की मंजूरी दी जाएगी। ये गगनयात्री अगस्त, 2024 के पहले सप्ताह से मिशन के लिए अपना प्रशिक्षण शुरू करेंगे।''

आशा किरण शेल्टर होम केसः मौत के लिए 'आप' जिम्मेदार

नई दिल्ली। राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) की प्रमुख रेखा शर्मा ने शुक्रवार को दिल्ली के आशा किरण आश्रय गृह का दौरा किया, जिसमें वहां रहने वालों की मौत की कई रिपोर्टें सामने आईं। उन्होंने आरोप लगाया कि वहां फंगस-संक्रमित भोजन, दूषित पानी और अनुचित दवाएँ परोसी गईं। शर्मा ने दावा किया कि आशा किरण आश्रय गृह अव्यवस्थित हो गया है, जिसमें 450 लोग बिना उचित भोजन, पानी और दवा के रह रहे हैं। आशा किरण मानसिक रूप से विकलांगों के लिए दिल्ली सरकार द्वारा संचालित सुविधा है और इसके समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत आती है। इससे पहले शुक्रवार को दिल्ली की मंत्री आतिशी ने जुलाई में आशा किरण में 14 महिलाओं की मौत की मजिस्ट्रेट जांच की मांग की थी। उन्होंने कहा कि जनवरी से घर में मौतों की रिपोर्ट आवश्यक सुविधाओं की कमी, कुपोषण और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का संकेत देती है। एनसीडब्ल्यू प्रमुख रेखा शर्मा ने कहा कि 250 लोगों की क्षमता वाले आश्रय गृह में 495 लोग रह रहे थे और उस पर अत्यधिक बोझ था। उन्होंने आश्रय गृह की लापरवाही के लिए आप के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार को भी दोषी ठहराया.

राहुल ही नहीं, कोई भी अपनी जाति बताने में शर्मसार क्यों हो

अजय कुमार

हिन्दुस्तान की राजनीति में क्या राहुल गांधी होना ही काफी है। वह जो सवाल सबसे पूछते हैं,वही सवाल जब उनसे कोई पूछ लेता है तो इसमें उनकी इनसर्ट कैसे हो जाती हैं। कहीं ऐसा तो नहीं वह अभी भी मध्यकालीन सामंतवादी सोच से बाहर नहीं निकल पाये हैं। यह सच है कि राहुल ऐसे परिवार से आते हैं जिसने आजादी के बाद दशकों तक सामंतवादी सोच के साथ देश पर राज किया है, जिनकी ताकत इतनी हुआ करती थी कि देश में इनकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता था। इनके एक इशारे पर प्रदेश की सरकारों की तकदीर बनती बिगड़ती थी। मुख्यमंत्री और सरकारें रातोंरात बदल और गिरा दी जाती थीं। इनके द्वारा राजशाही तरीके से देश को आपातकाल में झोंक दिया जाता था,जिनके द्वारा अपने हिसाब से देश की आजादी का इतिहास लिखवाया गया,जिसको चाहा अपमानित किया गया और जिसे चाह सिर आंखों पर बैठा दिया गया। इसी लिये वीर सावरकर जैसे स्वतंत्र सेनानी को यह लोग अपमानित करते हैं। सुभाष चन्द्र बोस को परेशान किया गया।

कांग्रेस आज भी इसी सोच के साथ जी रही है कि जो वह कहें वही पत्थर की लकीर है,उसे कोई काट नहीं सकता है। इससे ज्यादा दुख की बात यह है कि इंडिया गठबंधन के कुछ सहयोगी भी इससे इतिफाक रखते हैं, जिसमें आजकल समाजवादी पार्टी के दूसरी पीढ़ी के नेता पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव का नाम भी भी शीर्ष पर मौजूद है। मुलायम सिंह यादव जो ताउम्र कांग्रेस के खिलाफ लड़ते रहे,आपातकाल में जेल गये,उन्हीं के बेटे अखिलेश यादव तब उतेजित हो जाते हैं जब बीजेपी के नेता राहुल गांधी से उनकी जाति पूछ लेते हैं। वह सदन में चिल्लाने लगते हैं कि राहुल गांधी की जाति कैसे पूछी,जबकि राहुल-अखिलेश की जोड़ी अपनी राजनीति चमकाने के लिये समय-बेसमय किसी की भी जाति पूछकर उसका उपहास उड़ाने या उसके सहारे अपनी राजनीति चमकाने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं।

बहुत दिन नहीं हुए, जब यह दोनों नेता लोगों और विशेषकर अधिकारियों एवं मीडिया वालों की जाति पूछते थे, लेकिन जब लोकसभा में बीजेपी के एक नेता ने गोलमोल शब्दों में उनकी जाति पूछ ली तो वह उछल पड़े, जबकि राहुल का नाम लिये बिना बीजेपी के मंत्री अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में तंज कसा था कि जिन्हें अपनी जाति का पता नहीं, वे उसके गणना की मांग कर रहे है। यह बात राहुल और उनकी टीम के सदस्यों को इनती बुरी लगी कि इन्होंने हंगाम खड़ा कर दिया। कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के नेता संसद के भीतर और बाहर आपे से बाहर हो गए। इनमें कांग्रेस के वे नेता भी है, जो लोगों की जाति जानने की राहुल गांधी की अपरिपक्त राजनीति को उनका मास्टर स्ट्रोक बताया करते थे। सवाल यही है कि कोई अपरिक्त नेता जब हर तफर घूम-घूमकर सबकी जाति जानने की कोशिश करेगा तो फिर उसे अपनी भी जाति बताने के लिए तैयार रहना चाहिए,जैसा भाजपा नेता अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी की जाति के बारे में पूछा था। राहुल गांधी इस कटाक्ष को अपना अपमान बता रहे है। यह वही राहुल हैं, जो चंद दिन पहले लोकसभा में भाजपा नेताओं को दुर्योधन, शकुनी आदि बताते में लगे हुए थे। इसके पहले वह एक जनसभा में यह कह चुके हैं कि प्रधानमंत्री मोदी तो ओबीसी हैं ही नहीं,जबकि इसके उलट तमाम लोग राहुल गांधी को तो हिन्दू ही नहीं मानते हैं।

यह एक सामान्य बात है कि किसी को भी दूसरों के साथ वैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, जैसा उसे अपने लिए पसंद न हो,लेकिन राहुल गांधी हों या फिर अन्य कुछ नेता इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। अनुराग ठाकुर के बयान पर संसद में जो हंगामा हुआ, वह केवल राहुल गांधी का अपनी खीझ मिटाने और जनता का इस मुद्दें से ध्यान हटाने के अलावा कुछ नहीं था। यह हास्यास्पद ही है कि अनुराग ठाकुर के बयान का समर्थन करने के कारण कांग्रेस प्रधानमंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस देने पर विचार ले आई क्योंकि मोदी ने अनुराग के भाषण वाला वीडियो फारवर्ड कर दिया था। बहरहाल, संसद में आज जाति के नाम पर जो घमासान हो रहा है,उसकी नींव कांग्रेस ने बहुत पहले ही रख दी थी। आजादी के बाद कांग्रेस ही तो थी,जिसने अंग्रेजों के डिवाइड एंड रूल वाले फार्मूले को जिंदा रखा था।

जातिवादी राजनीति का ही नतीजा है कि समाज बंटता जा रहा है। जब नेताओं को देश को जाति की राजनीति से बाहर लाने की कोशिश की जानी चाहिए, तब कुछ दलों और विशेष रूप से कांग्रेस के नेता जाति की राजनीति को तूल देकर समाज में विभाजन और वैमनस्य पैदा करने में लगे हुए हैं। वे यह कहकर जाति की गणना की मांग करने में लगे हुए हैं कि इससे ही समस्त समस्याओं का समाधान होगा और सामाजिक न्याय का लक्ष्य हासिल होगा। यदि जाति गणना इतनी ही आवश्यक थी तो दशकों का लक्ष्य हासिल होगा। यदि जाति गणना आवश्यक थी तो दशकों तक केंद्र की सत्ता में रही कांग्रेस ने ऐसा क्यों नहीं किया? प्रश्न यह भी है कि क्या लोगों की जाति जाने बिना उन्हें गरीबी से बाहर निकालने और शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के प्रश्न हल करना संभव नहीं? हर कोई इससे अच्छी तरह परिचित है कि जाति की राजनीति ने समाज को विभाजित करने के साथ सामाजिक न्याय की राह में मुश्किल पैदा की है, फिर भी कुछ नेता अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने के लिए समाज को जातियों में बांटने में लगे हुए हैं।

जातीय वैमनस्य के रूप में इसके दुष्परिणाम सामने है, लेकिन जातिवादी नेता यह देखने-समझने को तैयार नहीं। हमारे समाज में तो केवल दो ही जातियां होनी चाहिए- अमीर एवं गरीब और उनका ही पता लगाया जाना चाहिए।

राशन की कालाबाजारी में बड़ी कार्रवाई, 900 बोरियां जब्त

सुकमा। सुकमा जिले में राशन माफियाओं पर जिला प्रशासन की अब तक की सबसे बड़ी कार्यवाही देखने को मिली है। जहां नक्सल प्रभावित चिंतलनार के गांव में कार्यवाही में अब तक 900 बोरे चावल बरामद हुए हैं। लगभग 200 बोरा चना और बड़ी मात्रा में शक्कर अलग अलग गोदाम से बरामद किया गया है।

चिंतलनार इलाका लंबे समय से राशन की कालाबाजारी को लेकर चर्चा में रहा है। जहां अंदरूनी इलाकों में रह रहे अशिक्षित ग्रामीणों के राशन पर डाका डालने का मामला कई बार विधानसभा में भी गूंज चुका है। एक बार फिर से चिंतलनार चर्चा में आया। लेकिन यह कार्यवाही अब तक की सबसे बड़ी कार्यवाही बताई जा रही है।

मिली जानकारी के अनुसार, विशेष गुप्त सूत्रों के हवाले से गरीबों में बांटे जाने वाले राशन के अवैध रूप से लगाए गए स्टॉक की जानकारी जिला प्रशासन को लगी। जिसके बाद सुकमा कलेक्टर हरीश के निर्देश पर एसडीएम तहसीलदार खाद्य विभाग के द्वारा दो दिनों तक कार्यवाही की गई पहले दिन मौके से एक निजी मकान में 43 बोरा चावल 18 बोरा शक्कर और एक

बड़ा चना बरामद किया गया था।

जिसके बाद टीम वापस मुख्यालय लौट आई थी। इस कार्यवाही के बाद एक और विशेष सूचना प्रशासन को मिली। जिसके बाद कलेक्टर के निर्देश पर टीम वापस चिंतलनार में छापे मार कार्यवाही करने के लिए पहुंची। इस दौरान बताए गए जगह पर प्रशासन की टीम ने कार्यवाही की कार्यवाही के दौरान अलग-अलग गोदाम से 500 से ज्यादा बोरा चावल लगभग 200 बोरा चना और बड़ी मात्रा में शक्कर बरामद किया गया।

खबर लिखे जाने तक पीडीएस की कालाबाजारी पर कार्यवाही जारी रही। मौके पर एसडीएम तहसीलदार खाद्य अधिकारी खाद्य निरीक्षक समेत आल्हा अधिकारी मौजूद है। इस मामले पर सुकमा कलेक्टर हरीश एस ने फोन पर चर्चा के दौरान बताया कि सूचना के आधार पर टीम को चिंतलनार भेजा गया। जहां दो दिनों में दो अलग कार्यवाही की गई है। भारी मात्रा में राशन के बरामद होने की जानकारी मिली है । फिलहाल, टीम कार्यवाही कर रही है। कार्यवाही पूरी होने के बाद विस्तार से जानकारी दे दी जाएगी।

कई बार कालाबाजारी को लेकर चर्चा में रह चुका है चिंतलनार

गौरतलब है कि चिंतलनार वह इलाका है जहां पीडीएस की कालाबाजारी आम बात हो चली है, क्योंकि इलाका अशिक्षित है और अंदरूनी इलाकों में भवन न होने की वजह से आधा दर्जन से ज्यादा राशन की दुकान चिंतलनार में ही संचालित है और दूर दराज के इलाकों से आने वाले ग्रामीण की शिकायत जिला मुख्यालय तक नहीं पहुंच पाती है। इसी का फायदा राशन दुकान के संचालक उठाते हैं। इससे पहले भी पोटाकेबिन के राशन की हेरा फेरी का मामला उजागर हुआ था। जहां 300 से ज्यादा बोरे राशन की कालाबाजारी मामले में एक सरपंच के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया था। वहीं कई बार यहां राशन की कालाबाजारी के मामले विधानसभा में भी गूंजे हैं।

कैसे चलता है कालाबाजारी का चैन

गौरतलब है कि खाद्यसुरक्षा अधिनियम के नए कानून आने के बावजूद कालाबाजारी पर लगाम नहीं लग पाया है, क्योंकि यह काम अकेले के दम पर किया जा पाना संभव नहीं है। इस सिस्टम को एक बड़े चैन के जरिए चलाया जाता है। दंतेवाड़ा मार्ग खुलने के बाद पीडीएस की कालाबाजारी पालनार के रास्ते खुल गए। स्थानीय सूत्रों का कहना है कि जगरगुंडा होते हुए पालनार के रास्ते जिले का शासकीय राशन अवैध रूप से दंतेवाड़ा जिले में दाखिल होता है। इस रास्ते में प्रशासन का हस्तक्षेप नहीं होता है और रास्ते में पुलिस थाने भी बेहद कम होते हैं। जिस वजह से इन पर दबिश नहीं हो पाती। स्थानीय सूत्र यह तक कहते हैं कि चिंतलनार और जगरगुंडा की राशन दुकानों की सिरे से जांच की जाए और गोश्वरा की जानकारी के साथ ग्रामीणों से पूछताछ की जाए तो कई दुकान प्रशासन की कार्यवाही की भेंट चढ़ेंगे।

अब समझा कर नहीं लाठी से उतारा जाएगा नशा, साड़ी में महिला कमांडो देंगी पहरा

धमतरी। गुरुवार को धमतरी शहर के आमापारा स्थित सिंधी समाज भवन में महिला कमांडो का गठन किया गया। शहर में बढ़ते अपराध और नशाखोरी के चलते पुलिस अधीक्षक की पहल पर महिलाओं का समूह बनाया गया है। महिलाओं की इस समूह को महिला कमांडों का नाम दिया गया है। महिलाओं के लिए ड्रेस कोड रखा गया है। एसपी आंजनेय वार्ष्णेय और कलेक्टर नम्रता गांधी की उपस्थिति में महिलाओं को एक ही रंग की साड़ी, टोपी, सीटी और लाठी दी गई। जो फिलहाल धमतरी के 40 वार्ड में से 5 वार्ड पर तैनात रहेंगी।

धमतरी में इससे पहले भी महिला कमांडो का गठन किया गया था। महिला कमांडो का नाम सुनते ही नशेड़ी भाग खड़े होते थे। अपराधिक काम करने वाले भी सकते में आ जाते थे। लेकिन बाद

में किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। महिला कमांडो का काम थम गया। बीते दिनों धमतरी में शांति समिति और कुछ वार्ड पार्षदों की मीटिंग हुई।इस दौरान एक बार फिर महिला कमांडो को याद किया गया। ये चर्चा हुई कि अपराधों की रोकथाम और नशे की बढ़ती रफ्तार को धीमा करने में उनका योगदान सराहनीय था।

गुरुवार को इसी प्रयास के तहत आमापारा सिंधी धर्मशाला में जिला और पुलिस प्रशासन की पहल पर शहर की पांच वार्डो की महिलाओं को महिला कमांडो की तरह दायित्व दिया गया। जो कि अपराधो की रोकथाम में जिला और पुलिस प्रशासन का सहयोग करेंगी। इस कार्यक्रम में कलेक्टर नम्रता गांधी, एसपी आंजनेय वार्ष्णेय, डीएसपी नेहा पवार, कोतवाली प्रभारी राजेश मरई समेत भाजपा नेता राजेंद्र शर्मा, नरेंद्र रोहरा,विजय मोटवानी, प्रकाश सिन्हा कामिनी कौशिक समेत अन्य समाजसेवी लोग भी उपस्थित हुए और महिलाओं से सहयोग की अपेक्षा की गई। एसपी आंजनेय वार्ष्णेय ने कहा नशा को कम करने के लिए नारी शक्तियों के साथ मिलकर एक अभियान की शुरुआत की गई है। पांच वार्डों में सामाजिक संस्थाओं को जोड़कर महिला कमांडो का गठन किया गया है।

लाखों की चोरी करने वाले एक चोर को पुलिस ने किया गिरफ्तार

■ फरार साथी की तलाश में पुलिस

भाटापारा। भाटापारा शहर थाना पुलिस ने टेउराम कॉलोनी भाटापारा में चोरी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी बिलासपुर से आकर अपने एक साथी के साथ चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। आरोपियों ने घर का ताला तोड़कर अलमारी में रखे सोने चांदी के आभूषण एवं नकदी सहित कुल एक लाख पचास हजार रूपए का माल पार कर दिया था।

28 जुलाई को विजय सबलानी निवासी टेउराम कॉलोनी हेमू कल्याणी वार्ड भाटापारा द्वारा थाना भाटापारा शहर में रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि दिनांक 27. जुलाई 2024 को मैं पारिवारिक काम से रायपुर गया था। कि दिनांक 27-28.जुलाई .2024 की रात्रि बड़े भाई द्वारा फोन कर बताया गया कि मेरे घर का ताला तोड़कर, घर अंदर प्रवेश कर किसी अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर लिया गया है। कि सूचना पर मैं सुबह साढे 7 बजे लगभग अपने घर आया, तो देखा, कि घर का ताला टूटा था, अंदर सभी सामान अस्त व्यस्त पड़ा था। किसी अज्ञात चोर द्वारा घर का ताला तोड़कर घर मे रखे अलमारी को खोलते हुए उसमें अंदर रखा सोना चांदी के आभूषण एवं नगदी पचास हजार रूपए ?50,000 सहित कुल ?1,50,000 का चोरी कर लिया गया है। रिपोर्ट पर थाना भाटापारा शहर में अपराध दर्ज कर धारा 331(4),305(।) बीएनएस पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया

गया।

प्रकरण में भाटापारा शहर पुलिस द्वारा चोरी करने वाले अज्ञात आरोपियों की पतासाजी, प्रक्रिया प्रारंभ किया गया। पुलिस की एक टीम द्वारा घटनास्थल के आसपास एवं भाटापारा शहर के विभिन्न स्थानों में लगे लगभग 500 से अधिक सी सी कैमरा फुटेज का जॉच किया गया। साथ ही साइबर सेल की टीम द्वारा तकनीकी विश्लेषण के आधार पर भी आरोपियों की पहचान का प्रयास किया जा रहा था, जिसमें पुलिस टीम को आरोपी के बिलासपुर तरफ भागने के संबंध में पता चला। तत्पश्चात पुलिस टीम द्वारा लगातार तीन दिनों तक सर्च अभियान चलाते हुए आरोपी का खोजबीन किया जा रहा था, इस दौरान पुलिस टीम द्वारा प्रकरण में शामिल एक आरोपी सेंडी उर्फ संतोष को पकड़ा गया।

आरोपी से पूछताछ करने एवं कथन पर उसके द्वारा अपने एक साथी के साथ मिलकर बाइक के माध्यम से आकर टेउराम कॉलोनी स्थित प्रार्थी के मकान में चोरी की घटना करना स्वीकार किया गया। प्रकरण में आरोपी से चोरी का नगद बीस हजार रूपए ?20,000 जप्त किया गया है तथा चोरी में शामिल एक अन्य आरोपी का पता तलाश मे जुटी पुलिस,आरोपी सेंडी उर्फ संतोष उम्र का 21 वर्ष निवासी ग्राम देवरीडीह तोरवा बिलासपुर जिला बिलासपुर को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए जेल भेजने की प्रक्रिया की गई।

बाप-बेटे ने मिलकर की दो करोड़ की धोखाधड़ी, भतीजा गिरफ्तार

बिलासपुर। बिसालपुर में एक भतीजे

ने पिता के साथ मिलकर अपने सजे चाचा से ही धोखाधड़ी कर ली। पुलिस ने फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। छत्तीसगढ़ में बिलासपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में बाप-बेटे ने मिलकर अपने सगे चाचा से करीब दो करोड़ रुपये की धोखाधड़ी कर ली। मामले में पुलिस ने बेटे को गिरफ्तार कर लिया। वहीं आरोपी पिता अभी भी फरार है। दरअसल, थाना क्षेत्र के आरोपी नवीन बजाज को सिविल पुलिस ने झारसुगुड़ा से घेराबंदी कर पकड़ लिया।

सिंधी कॉलोनी बलराम टॉकीज के पास रहने वाले परसराम बजाज पिता स्वर्गीय दौलत राम बजाज और उसका बड़ा भाई रमेश कुमार बजाज साथ मिलकर दो फर्म खोली थी। जिसमें नयन फैशन को रमेश कुमार बजाज और उसका बेटा नवीन बजाज मिलकर चलाता था। उनके द्वारा महाराष्ट्र बैंक से एक करोड़ और इंडियन ओवरसीज बैंक से 70 लाख क्रेडिट लिमिट से रुपये लिए थे। इस दौरान आरोपी ने परसराम बजाज और विजय बजाज का फर्जी हस्ताक्षर किया गया।

इसी तरह नयन फैशन को दिखाकर अन्य कंपनियों से भी आरोपी ने रुपये लिए। यहां तक बैंक में रुपये जमा करने की बात कहकर 18 लाख रुपये परशराम बजाज से ले लिए थे। वहीं रुपये का गबन कर आरोपियों ने बैंक की फर्जी जमा पर्ची थमा दी थी। भाई और भतीजे द्वारा करोड़ों की घोटाला की जानकारी परसराम बजाज को मिली। इस पर उन्होंने अपनी मौसी को आगे कर दिया। कुछ दिनों में दो करोड़ रुपये लौटाने का लिखित में वादा किया। उनके द्वारा दो चेक भी दिए।

पुलिस ने चोरी का किया खुलासा, गहने और नकदी समेत लाखों रुपये का माल बरामद, एक गिरफ्तार

कोंडागांव। कोंडागांव पुलिस ने चोरी के एक मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी समेत लगभग 20 लाख के सोने चांदी के गहने और नगद बरामद किया है। सभी आरोपी भीमखोज महासमुंद जिले के निवासी हैं। घटना 11 जून 2024 की है, जब कोंडागांव जिले के बयानार थाना क्षेत्र के साप्ताहिक बाजार में व्यापार करने गए ज्वेलरी व्यापारी राकेश जैन जब शाम लगभग 4 बजे अपना सामान समेट कर गाड़ी में रख रहे थे। तभी 3 चोर मौका पाकर सोने-चांदी से भरी पेटी उठाकर फरार हो गए। व्यापारी ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद से पुलिस लगातार चोरों की तलाश कर रही थी। पुलिस को मिले इनपुट के आधार पर उन्होंने भीमखोज जिला महासमुंद में छापामारी की और सचिन ध्रुव को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में 1 अन्य फरार आरोपी की तलाश जारी है। पुलिस अधीक्षक कोंडागांव वाय अक्षय कुमार ने बताया कि इन तीनों आरोपियों पर रायपुर और आसपास चोरी के कई मामले दर्ज हैं। बयानार के साप्ताहिक बाजार से चोरी के मामले में सचिन ध्रुव की गिरफ्तारी के साथ 20 लाख रुपए जुमले का सोना-चांदी, नगद और एक बाइक बरामद की गई है। दूसरा आरोपी उड़ीसा के टिटलागढ़ जेल में बंद है, जिसे जल्द ही बयानार चोरी के मामले में कोर्ट में पेश किया जाएगा। तीसरा साथी राकेश फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी है।

भ्रष्टाचार में दोषी सरपंच-सचिव को अब अधिकारियों ने दिया क्लीन चिट

सक्ती। सक्ती में पंचायत विभाग के अधिकारियों के अजब-गजब कारनामे सामने आ रहे हैं। लाखों के भ्रष्टाचार में दो साल पहले दोषी करार सरपंच-सचिव को अधिकारियों ने क्लीन चिट दे दिया है। यहां तक मामले में सरपंच-सचिव को दोषी बताने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की बात कही जा रही है। मामला सक्ती के ग्राम पंचायत पोरथा का है। ग्राम सरपंच मधु राठौर और सचिव के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत हुई थी। मामले की जांच के लिए 6 अधिकारियों की टीम गठित की गई थी, जिन्होंने जांच में लाखों की गड़बड़ी पाई थी। रिपोर्ट दो साल तक धूल फांकती रही। शिकायतकर्ता ग्रामीण कार्रवाई के लिए कार्यालयों के चक्कर काटते रहे, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई।

दो साल बाद मामले में फिर से जांच की गई। इस बार जनपद पंचायत के अधिकारी ने सरपंच-सचिव को भ्रष्टाचार के आरोपों से बरी कर क्लीन चिट दे दिया। वहीं इससे पूर्व जांच करने वाले 6 अधिकारियों को भी गलत साबित कर दिया। जनपद पंचायत सक्ती में अधिकारियों के इस अजब-गजब कारनामे ने अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़ा कर दिया है।

अब ग्रामीण सवाल कर रहे हैं कि आखिर क्या कारण था कि दो साल पहले जिस सरपंच-सचिव को भ्रष्टाचार में दोषी बताया गया था, उन पर कार्रवाई नहीं की गई, और आज उन्हें क्लीन चिट देकर अपने ही अधिकारियों को गलत साबित कर दिया गया।

मामले में जनपद पंचायत सीईओ प्रीति पवार का कहना है कि कलेक्टर कार्यालय से शिकायत मिलने पर जांच कराई गई है, जिसमें राशि का आहरण नहीं हुआ पाया गया है। पूर्व में गलत जांच हुई थी, जिसके लिए संबंधित सभी 6 अधिकारियों को नोटिस जारी किया जाएगा।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

विधायक उसेंडी ने दिव्यांगजनों को किया उपकरण वितरण

कोंडागांव। कलेक्टर कोण्डागांव के निर्देशानुसार जनपद पंचायत कोण्डागांव जिला कोण्डागांव में दिव्यांग प्रमाणीकरण सह सहायक उपकरण प्रदाय शिविर का आयोजन बुधवार को किया गया। इसमें विधायक सुश्री लता उसेंडी ने 142 दिव्यांगजनों को उपकरणों का वितरण किया। शिविर में 649 दिव्यांगजनों ने पंजीयन करवाया, जिसमें 297 दिव्यांगजन 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग पाए गए। कार्यक्रम में जनपद पंचायत अध्यक्ष श्री शिवलाल मंडावी, नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती वर्षा यादव, समाज कल्याण विभाग की उप संचालक श्रीमती ललिता लकड़ा, वरिष्ठ करारोपण अधिकारी श्री आर एस कोर्राम, समाज शिक्षा संगठक श्री मेघनाथ मरकाम जनपद पंचायत कोण्डागांव के सरपंच, सचिव, स्वास्थ्य विभाग के मेडिकल बोर्ड, मितानीन एवं युवोदय की टीम, समाज कल्याण विभाग के समस्त कर्मचारी उपस्थित थे।

पूरे गांव को लगेगी रेबीज की वैक्सीन, टीम पहुंची

कांकेर। कांकेर में कोयलीबेड़ा ब्लॉक के ग्राम विवेकानंदनगर में पूजा का प्रसाद खाने के बाद ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ गयी हैं। दरअसल 01 जून को विवेकानंदनगर गाव में एक ग्रामीण के घर सत्यनारायण पूजा का आयोजन होता है जिसमें गाय के कच्चे दूध से सिन्नी प्रसाद बनाया जाता है। उस पूजा में ग्रामीण पहुँचते हैं और प्रसाद खाते हैं पर सिन्नी प्रसाद बनाने में जिन दो गायों के दूध का उपयोग होता हैं उन दोनों गायों को गाँव के पागल कुत्ता काट चुका होता है। सत्यनारायण पूजा के लगभग 90 दिन बाद जब उन दोनों गायों की मौत हो जाती है तो गायों के मालिक अस्पताल जाकर चोरी-छुपे रेबीस का वैक्सीन लगा लेते हैं। परन्तु जब ये बात धीरे-धीरे पूरे गांव में फैलती है तो ग्रामीणों द्वारा उन गायों के दूध से बने प्रसाद के खाने से रेबीस के संक्रमण का अंदेशा के चलते स्वास्थ्य विभाग को पूरी घटना की सुचना देते हुए गाँव में रेबीस वैक्सीनेशन की मांग की। जिसके बाद स्वस्थ विभाग द्वारा मामले की गंभीरता देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की एक टीम विवेकानंद नगर गांव में वैक्सीनेशन के लिए भेजी गयी है।

तीरंदाजी प्रशिक्षण संस्थान में किया गया वृक्षारोपण

कोंडागांव। तीरंदाजी प्रशिक्षण संस्थान में गुरुवार को एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण किया गया। इस अवसर पर सद्गुरु सदाफल देव विहंगम योग संस्थान के संत श्री विज्ञानदेव, विधायक सुश्री लता उसेंडी, कलेक्टर श्री कुणाल दुदावत, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अविनाश भोई सहित उपस्थित अधिकारी-कर्मचारी एवं तीरंदाजी के प्रशिक्षुओं ने वृक्षारोपण किया। इसके साथ ही यहां तीरंदाजी के प्रशिक्षुओं को खेल सामग्री का वितरण भी किया गया। इस अवसर पर संत श्री विज्ञानदेव ने कहा कि इस परिसर में वृक्षारोपण के कार्य को आगे बढ़ाते हुए पौधे लगाए गए हैं। उन्होंने वृक्षों को अनिवार्य बताते हुए कहा कि पर्यावरण के ठीक रहने पर ही जीवन का विकास होगा। उन्होंने कहा कि हम प्रकृति पूजक हैं तथा नदी, पहाड़, वृक्षों के महत्व को समझते हुए उनकी पूजा करते हैं। प्रकृति में संतुलन के लिए वृक्षों की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है।

कवर्धा में नाबालिग लड़की का कंकाल मिलने से हड़कंप

कवर्धा। पंडरिया विकासखंड में एक नाबालिग लड़की का कंगाल मिला है। लड़की का कंकाल मिलने की सूचना के बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि लड़की पिछले 3 माह से लापता थी। आशंका जताई जा रही है कि उसने खुदकुशी की होगी। फिलहाल पुलिस मामले में जांच कर रही है। ये पूरी घटना कवर्धा जिले के कुकदूर थाना क्षेत्र की है। यहां 13 साल की बच्ची का कंकाल मिला है। जानकारी के मुताबिक बच्ची पिछले 3 माह से लापता थी। कंकाल को लेकर आशंका जताई जा रही है कि नाबालिक ने खुदकुशी की होगी। कंकाल मिलने की जानकारी के बाद कुकदूर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की गई है। एसडीओपी पंकज पटेल ने कहा मृत बच्ची के परिजनों ने जानकारी दी कि 3 महीने पहले घर से बच्ची कहीं चली गई थी, जिसका बोहिल के जंगल में पेड़ के नीचे शव मिला है। थाना कुकदूर की ओर से घटना स्थल पर पहुंचकर विधिवत कार्रवाई की गई। फिलहाल जांच की जा रही है।

मिलेट्स की राखियों से सरगुजा का बाजार गुलजार

सरगुजा। रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा है। सरगुजा की महिलाएं राखी बनाने में नवाचार कर रहीं हैं। यहां की महिलाएं चावल, गेहूं, धान, जौ, मिलेट्स और इमली से राखियां बना रहीं हैं। इन महिलाओं की मानें तो इस राखी में अपनापन दर्शाने के उद्देश्य से महिलाएं ये खास राखी तैयार कर रही हैं। ये राखी पूरी तरह से इको फ्रेंडली है। इसमें इस्तेमाल किया गया हर चीज प्राकृतिक है। प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर सरगुजा की महिलाओं ने राखी निर्माण में नवाचार किया है। इन महिलाओं ने ऐसी राखियां तैयार की है, जिसमें अपनापन लगे। यहां के अधिकतर लोग खेती-किसानी पर निर्भर हैं। ये वनांचल क्षेत्रों में रहते हैं। यही कारण है कि प्रकृति को जोड़ते हुए इन महिलाओं ने राखी तैयार किया है। चावल, गेंहू, धान, जौ, मिलेट्स और इमली की राखियां इन महिलाओं ने बनाई गई हैं। राखी बनाने वाली महिलाओं का कहना है कि स्टोन और जड़ी की राखी तो हमेशा ही बाजार में मिलती है, लेकिन इन राखियों में अपनापन है।

कोल खदान की जनसुनवाई से विरोधियों को दूर रहने लगाया बैनर-पोस्टर

सरगुजा। केते एक्सटेंशन कोयला खदान के समर्थन में ग्रामीणों ने विरोधियों को भागने के लिए पोस्टर और बैनर लगाए हैं। उनका मानना है कि खदान से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और क्षेत्र का विकास होगा। ग्रामीणों का कहना है कि विरोध करने वाले बाहरी लोग हैं जो इलाके की प्रगति को रोकना चाहते हैं। उनके अनुसार, खदान से शिक्षा, स्वास्थ्य, और बुनियादी ढांचे में सुधार होगा। पोस्टरों पर लिखा है, फर्जी आंदोलन बंद करो, आलोक का आना मना है। %आलोक शुक्ला हमारे गाँव में आना बंद करो।% %आलोक शुक्ला इनाम के 1.8 करोड़ से कितने गाँव वालो का भला किया?% कितने पेड़ लगाये? ग्रामीणों ने बताया कि आलोक शुक्ला भोले-भले आदिवासियों को पैसा देकर जनसुनवाई में विरोध के रूप में आंदोलन करने बाहर से लाते है और क्षेत्र की जनता को भड़काते है। क्षेत्र के ग्रामीणों ने आलोक शुक्ला पर आदिवासियों के नाम से मिले पुरस्कार पर भी सवाल किया और कहा कि आलोक शुक्ला

को करोड़ों में इनाम मिला लेकिन किसी भी गाँव में उन्होंने एक पैसा नहीं दिया क्यों? ग्रामीणों का कहना है आलोक शुक्ला ने लोगो को ठगा है। विरोध करने वाले लोग समझें कि यह परियोजना उनके भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। वे सरकार और कंपनियों से भी अपील कर रहे हैं कि खदान का काम जल्द शुरू हो ताकि उनकी स्थिति में सुधार हो सके। ग्रामीणों ने अपने समर्थन को स्पष्ट करने के लिए गांव के मुख्य चौक, स्कूल, पंचायत भवन और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर बैनर और पोस्टर लगाए हैं। उनका तर्क है कि कोल खदान से आने वाली राजस्व राशि से गांव में बिजली, पानी, और सड़कों जैसी मूलभूत सुविधाओं का विकास होगा। इसके अलावा, ग्रामीणों ने पंचायत बैठकों में भी इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया है और स्थानीय से अनुरोध किया है कि वे खदान परियोजना का समर्थन करें। उन्होंने यह भी कहा है कि विरोध करने वाले लोगों का उद्देश्य राजनीतिक है और वे स्थानीय हितों की परवाह नहीं करते। ग्रामीणों का यह भी मानना है कि कोल खदान से पर्यावरण को होने वाले नुकसान को कम करने के लिए उचित प्रबंधन और सावधानी बरती जा रही है। ग्रामीण अपनी प्रगति और भलाई के लिए एकजुट हो गए हैं और अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए विभिन्न माध्यमों का उपयोग कर रहे हैं। वही खदान से मिलने वाले रोजगार से युवाओं को अपने गांव में ही काम करने का मौका मिलेगा, जिससे पलायन की समस्या भी कम होगी। महिलाओं ने भी खदान के समर्थन में अपनी आवाज उठाई है। उन्होंने कहा कि खदान से मिलने वाले लाभ से उनके बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार होगा। ग्रामीणों ने पोस्टरों और बैनरों में अपने संदेश लिखकर विरोधियों को यह स्पष्ट कर दिया है कि वे अपने और अपने परिवार के उज्ज्वल भविष्य के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। ग्रामीणों ने अपने समर्थन को दिखाने के लिए एकजुट होकर विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया है और अपने अधिकारों और भविष्य के लिए मजबूत कदम उठाए हैं।

प्राथमिक शाला बाला के प्रधान पाठक पारसराम वर्मा निलंबित

एमसीबी। जिला शिक्षा अधिकारी से प्राप्त जानकारी अनुसार कलेक्टर डी.राहुल वेंकट के निर्देशानुसार तहसीलदार केल्हारी द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर श्री पारसराम वर्मा, प्रधान पाठक प्राथमिक शाला बाला विकासखण्ड मनेन्द्रगढ़ को निलंबित कर दिया गया है। वर्मा पर आरोप है कि उन्होंने 27 जुलाई 2024 को विद्यालय में शराब के नशे में अधिकारी और कर्मचारियों के साथ अभद्रता की थी। उनका यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 23 और 3 का

उल्लंघन माना गया है, जिसके कारण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 उपनियम 1 (क) के तहत उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में वर्मा का मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी भरतपुर जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर नियत किया गया है, और उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।

संक्षिप्त समाचार

पूर्व मंत्री लखमा के बयान पर मुख्यमंत्री साय का पलटवार

रायपुर। पूर्व मंत्री कवासी लखमा के बयान पर सीएम विष्णु देव साय ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा, राम मंदिर का निमंत्रण अस्वीकार करके कांग्रेस ने बड़ा पाप किया है। किसी का निमंत्रण नहीं ठुकराना चाहिए। कार्यक्रम में जाए, नहीं जाए ये व्यक्ति पर निर्भर करता है। यह बहुत गलत बात है, हम इसकी निंदा करते हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के एक्स पोस्ट पर सीएम साय ने कहा, जो भी दोषीदार हैं, जो भी अपराधी है, उन पर कार्रवाई तो निश्चित होगी। श्वस्त्र व अन्य जांच एजेंसियों की कार्रवाई होगी। छत्तीसगढ़ में भी लगातार कार्रवाई हो रही है, दोषीदार कितने भी बड़े हो, बख्से नहीं जाएंगे। मिनी उद्योग को लेकर होनी वाली मीटिंग को लेकर सीएम साय ने कहा, लगातार संपर्क में हैं, जल्द सामाधान निकलेगा।

रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने आज स्वर्णप्राशन कराया जाएगा

रायपुर। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने 3 अगस्त को रायपुर के शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय चिकित्सालय में बच्चों को स्वर्णप्राशन कराया जाएगा। आयुर्वेद महाविद्यालय चिकित्सालय में हर पुष्य नक्षत्र तिथि में शून्य से 16 वर्ष के बच्चों को स्वर्णप्राशन कराया जाता है। चिकित्सालय के कौमारभृत्य बाल रोग विभाग में सवेरे नौ बजे से दोपहर दो बजे तक इसका सेवन कराया जाता है। यह औषधि बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने, श्वसन संबंधी एवं अन्य रोगों से रक्षा करने के साथ ही एकाग्रता और स्मरण शक्ति बढ़ाने में अत्यंत लाभकारी है। यह बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास में भी मदद करता है। शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय चिकित्सालय में हर पुष्य नक्षत्र तिथि में बच्चों के लिए स्वर्णप्राशन का आयोजन किया जाता है। स्वर्णप्राशन हर महीने की पुष्य नक्षत्र तिथि में शून्य से 16 वर्ष के बच्चों को पिलाई जाने वाली औषधि है। इस साल 3 अगस्त के साथ ही अन्य पुष्य नक्षत्र तिथियों 30 अगस्त, 26 सितम्बर, 24 अक्टूबर, 20 नवम्बर और 18 दिसम्बर को भी स्वर्णप्राशन कराया जाएगा।

मंत्रियों और विधायकों के वेतन में वृद्धि नहीं, अफवाह का सरकार ने किया खंडन

रायपुर। सोशल मीडिया में आज मंत्रियों और विधायकों के वेतन से जुड़ी एक भ्रामक खबर चल रही है, बाकायदा एक चार्ट भी शेयर किया जा रहा है जिसमें मंत्रियों और विधायकों के वेतन-भत्ते को दर्शाया गया है। सरकारी सूत्र का कहना है कि वर्तमान राज्य सरकार ने मंत्रियों और विधायकों के वेतन मे कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है, जो चार्ट सोशल मीडिया मे शेयर किया जा रहा है, वह पूर्ववर्ती सरकार का है।

विचक्षण जैन विद्यापीठ के प्राचार्या को मिला बेस्ट प्रिंसिपल अवार्ड

रायपुर। विचक्षण जैन विद्यापीठ, वर्धमान नगर, रायपुर स्कूल की प्राचार्या श्रीमती नीतू जैन का चयन नेशन नंबर वन इंडियन टैलेंट ऑलंपियाड द्वारा बेस्ट प्रिंसिपल अवार्ड के लिए हुआ है । यह चयन इंडिया के 1.5 लाख स्कूलों में से एक हज़ार स्कूलों की प्रिंसिपल को चुना गया है। विचक्षण जैन विद्यापीठ के ट्रस्टियों ने भारतीय प्रतिभा ऑलंपियाड पुरस्कार प्राप्त करने पर असाधारण प्रतिभाशाली श्रीमती नीतू जैन एवं विजेता बच्चों को बधाईंया प्रेषित की । विचक्षण जैन विद्यापीठ के ट्रस्टी सी ए विजय मालू ने बताया कि श्रीमती नीतू जैन के नेतृत्व क्षमता, कड़ी मेहनत, और समर्पण के कारण विचक्षण जैन विद्यापीठ के 63 प्रतिभाशाली छात्रों ने एसओएफ ऑलंपियाड में भाग लेकर स्कूल, ज़ोनल, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शानदार स्थान प्राप्त किया। इस सफलता पर इन सभी छात्रों को नगद पुरुस्कार एवं अवार्ड से ऑलंपियाड द्वारा सम्मानित किया गया।

मुख्यमंत्री साय के नाम से बनी फर्जी फेसबुक आईडी, पुलिस ने कराया ब्लॉक

रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नाम से आम लोगों को फेसबुक में फ्रेंड रेकुएस्ट आ रहे हैं, लोग आश्चर्यचकित हो रहे हैं। दरअसल, यह सीएम विष्णुदेव साय का फेसबुक अकाउंट नहीं है, बल्कि साइबर ठगों ने फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाया है। बता दें कि प्रदेश में साइबर क्राइम के रोजाना अलग-अलग मामले सामने आते रहते हैं। वहीं अब साइबर ठगी का नया मामला सामने आया है, जिसमें साइबर ठग ने सीएम विष्णुदेव साय के नाम से एक फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाया है। साइबर ठग मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नाम से एक फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाकर अधिकारियों और अन्य लोगों को रिक्वेस्ट भी भेजा जा रहा था। साथ ही लोगों को मैसेज भी भेज रहे थे। वहीं अब फर्जी फेसबुक अकाउंट शिकायत पर साइबर रेंज थाना में आईटी एक्ट के तहत अज्ञात आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है। साइबर ठगों ने ठगी के लिए यह फर्जी अकाउंट बनाई है, लेकिन अब तक किसी से ठगी की कोशिश का पता नहीं चला सका है। मामले में पुलिस छानबीन कर रही है कि फर्जी फेसबुक अकाउंट के पीछे किसका हाथ है। मामले में पुलिस ने बताया कि इस फर्जी फेसबुक अकाउंट से कई पोस्ट की गई है। ठगों ने फर्जी आईडी में सीएम साय को फोटो लगाई है। इतना ही नहीं अपनी परिचय में ठग ने खुद को मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन बताया है। साइबर सेल पुलिस जांच कर रही है कि आईडी कहां से बनाई गई।

हड़ताल करके अराजकता फैला रहे हैं स्टील उद्योग के मालिक : पीएन सिंह

रायपुर। अखिल भारतीय विद्युत अभियंता संघ के संरक्षक, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत विनियामक आयोग के पूर्व सचिव श्री पी.एन. सिंह ने उच्चदाब स्टील निर्माताओं द्वारा विद्युत दरों को लेकर की जा रही मांग पर विस्तार से तकनीकी पक्ष तथा अपने विचार प्रस्तुत किये है। श्री सिंह ने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय तथा सचिव ऊर्जा श्री पी. दयानंद को पत्र प्रेषित करते हुए कहा है कि- छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिये विद्युत दरों के निर्धारण की प्रक्रिया अन्तर्गत समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर सभी पक्षों को अपनी सुझाव एवं आपत्ति कहने की बात कही। जिस पर कोई भी चाहे तो वह अपना लिखित आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

नियामक आयोग का यह फैसला अर्द्धन्यायिक फैसला है यदि कोई इस फैसले से असहमत है तो वह अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपना पक्ष रखकर वहां से न्याय प्राप्त करने को स्वतंत्र है। भारत सरकार द्वारा पूरे देश मे यह व्यवस्था कायम की गई है। फिर भी यदि कोई दूसरा रास्ता अपनाता है तो वह अराजकता फैलाने का दोषी है। यदि किसी अदालती कार्यवाही में किसी को न्याय नहीं मिलता है तो उसे उच्च अदालत में अपील करने का अधिकार है। यही व्यवस्था विद्युत नियामक आयोग के प्रकरण में भी है। यदि किसी अदालत के फैसले के खिलाफ अपील करने के बजाय सड़कों पर हुडदंग करते चला जाता है तो कानूनी कार्यवाही एवं सजा का हकदार है।

विद्युत नियामक आयोग के आदेश से स्टील उद्योग का एक वर्ग यह महसूस करता है कि उसे नुकसान हो रहा है, तो उसके पास अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाने का रास्ता है और अभी भी अपील करने का समय है यदि अपीलेट ट्रिब्यूनल से उन्हें न्याय मिलता है तो उन्हें वहां जाना चाहिये। हड़ताल करके प्रदेश में माहौल को खराब करने का प्रयास होता है। किसी भी अपीलीय फैसले के विरूद्ध कोई राज्य सरकार कदम नहीं उठा सकती है। स्टील उद्योग से संबंधित लोग यह चाहते हैं कि शासन

की तरफ से कुछ अलग से राहत मिल जाये। बिजली की दरे तो सभी उद्योगों के लिये बढ़ी हैं. सभी छूट की मांग करेंगे। सभी को राज्य सरकार नहीं दे सकती हैं क्योंकि वर्तमान वित्तीय वर्ष के बजट में इसका कोई प्रावधान नहीं किया गया है। बजट में प्रावधान करने के लिये सरकार को विशेष विधान सभा सत्र आयोजित करना होगा जो कि वर्तमान में उचित नहीं दिखाई पड़ता है।

स्टील उद्योगों से जुड़ें लोगों का कहना है कि पूरे प्रदेश में सात लाख रोजगार प्रदाय किये गये हैं, यह बहुत बड़ी अतिरेक है। लोहे के उद्योगों में उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग काम कर रहे हैं और इनकी कुल संख्या 50 हजार के आसपास है। छत्तीसगढ़ में 30 प्रतिशत आदिवासी रहते हैं जबकि एक प्रतिशत 'आदिवासियों को भी लोहे के धन्धे में काम नहीं मिला है।

आरोप है कि छत्तीसगढ़ में लोहे के उद्योगों में लगे हुये जो लोग हैं उन लोगों के साथ में है जो स्पंज आयरन बनाते हैं और जो 33 के.वी. पर केवल 577 उद्योग बिजली पाते हैं शेष मात्र 26 स्पंज आयरन बनाने वाले हैं जब भी बिजली की दरें घटती हैं उसी अनुपात में स्पंज आयरन बनाने वाले अपने सामान की कीमत बढ़ा देते हैं जिसकी वजह से एमएसपी वाले बडी संख्या में नुकसान में रहते हैं। घटी हुई बिजली की दरों का कोई लाभ फरनेश वालों को नहीं मिलता है, सारा मुनाफा स्पंज आयरन इकाईयां चट कर जाती हैं।

उच्च दाब स्टील उद्योगों की तर्ज पर व्यवसायिक और घरेलू उपभोक्ताओं को अधिक सस्ती बिजली दें : मोहन एंटी

अरबों रूपये की छूट के षडयंत्र व हिस्सेदारों का खुलासा हो

रायपुर। छत्तीसगढ़ में उच्चदाब स्टील उद्योगों के लिए बिजली दरों के पुनरीक्षण का निर्णय जून 2024 में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत विनियामक आयोग द्वारा लिया गया थ। इस निर्णय के खिलाफ स्टील उद्योग संगठन द्वारा आंदोलन किया जा रहा हैं। इस विषय पर छत्तीसगढ़ प्रदेश उपभोक्ता संरक्षण परिषद के अध्यक्ष श्री मोहन एंटी ने कहा है कि स्टील उद्योगपतियों को विद्युत दरों में राहत देने का विचार करने के पहले प्रदेश के लाखों घरेलू उपभोक्ताओं और छोटे व्यापारियों-व्यवसायियों को राहत देने पर विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सिर्फ एक वर्ग के उपभोक्ता समूह को इस तरह अचानक और रहस्यमय ढंग से तीन गुना छूट देना इस समूह के प्रति विशेष कृपा को इंगित करता हैं, अतः इससे यह सवाल उठता है कि अरबों रूपये की छूट की राशि का बंटवारा किनके बीच हुआ।

श्री मोहन एंटी ने कहा है कि वैसे भी विद्युत विनियामक आयोग एक संवैधानिक संस्था है। उसकी कार्यप्रणाली न्यायिक प्रक्रिया की तरह संचालित होती है। उपभोक्ताओं के किसी वर्ग को यदि शिकायत होती है तो उनके पास न्यायिक प्रक्रिया के तहत यह अधिकार होता है कि उच्च न्यायिक संस्थाओं में अपील कर सके। उन्होंने कहा कि सामान्यतः गृहस्थ और सामान्य व्यापारी वर्ग नियामक आयोग जैसी संस्था के निर्णय को मानता है और विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण करने वाली संस्थाओं के साथ ही राज्य शासन से मिलने वाली मदद का सम्मान करता है। विगत वर्षों में बड़ी मंहगाई की तुलना में वैसे भी प्रदेश में बिजली ज्यादा महंगी न हो, इसका ध्यान स्वयं मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी ने रखा है और राज्य शासन की ओर से 1000 करोड़ रूपये का विशेष अनुदान देकर मदद की है। उल्लेखनीय है कि स्टील उत्पादकों को विगत चार वर्षों में जो अतिरिक्त सुविधा दी गई है, उसका भार कहीं न कहीं घरेलू तथा छोटे व्यापारी तथा व्यवसायी लोगों पर पड़ता है। इसलिए एक तो स्टील उत्पादकों की दी जा रही छूट का युक्तियुक्तकरण करते हुए उसे 25ः से 10ः किया जाना स्वागत योग्य है, वहीं यह गौरतलब है कि इस कमी के बावजूद भी उन्हें वर्ष 2021-22 की तुलना में दो प्रतिशत अधिक छूट मिल रही है।

विभिन्न अध्ययनों से पता चला है कि स्टील उत्पादक विगत वर्षों में शासन से तीन गुना से अधिक छूट का लाभ भी लेते रहे और लोहे का दाम भी डेढ़ गुना से अधिक बढ़ा दिया, जिससे पुनः मध्यम वर्ग, सामान्य उपभोक्ता, घरेलू उपभोक्ता, छोटे व्यापारियों को दोहरी हानि हुई हैं। इसलिए यदि उच्च दाब स्टील उद्योंगों की मांगों पर गौर किया जाता हैं तो घरेलू उपभोक्ताओं तथा छोटे व्यापारियों को बिजली दरों में राहत देने पर विचार करना न्यायोचित होगा।

आवास योजना के तहत निर्माण कार्यों को दें सर्वोच्च प्राथमिकता : सीईओ आलोक

महासमुंद। कलेक्टर श्री प्रभात मलिक के निर्देशन में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री एस. आलोक ने गुरुवार को जिला पंचायत के सभाकक्ष में बैठक लेकर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। सीईओ जिला पंचायत ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत निर्माण कार्यों को पूर्ण करने में सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के पूर्णता हेतु शेष रह गए जिले में कुल अपूर्ण 3782 आवासों के निर्माण की प्रगति की समीक्षा करते हुए शीघ्र ही उसे पूरा कराने के निर्देश दिए। सीईओ जिला पंचायत श्री आलोक ने बताया कि जिले को कुल 73 हजार 266 प्रधानमंत्री आवास निर्माण का लक्ष्य प्रदान किया गया है। जिसके अंतर्गत 94 फीसदी से अधिक पूर्ण कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि अब तक 69 हजार 484 हितग्राहियों के निर्माणाधीन आवासों को पूर्ण कर पक्का मकान उपलब्ध कराया गया है। सीईओ श्री एस. आलोक ने नोडल अधिकारी सहित जनपद पंचायत के सभी मुख्य कार्यपालन अधिकारियों एवं विकासखण्ड समन्वयक और तकनीकी सहायकों को लगातार हितग्राहियों से संपर्क स्थापित कर अपूर्ण आवासों को जल्द से जल्द पूर्ण कराने के निर्देश दिए। बैठक में जिला एवं जनपद स्तर के सभी अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

महादेव कावरे ने रायपुर संभागायुक्त का किया पदभार ग्रहण

रायपुर। आईएएस श्री महादेव कावरे ने रायपुर संभाग आयुक्त कार्यालय में आज पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करने के बाद संभागायुक्त श्री कावरे ने अधिकारियों से परिचयात्मक चर्चा की। साथ ही संभाग में चल रहे कार्यो की सामान्य जानकारी ली। साथ ही नव नियुक्त संभागायुक्त ने कोर्ट व कार्यालय का निरीक्षण किया। इस अवसर पर संभागायुक्त कार्यालय के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। साथ ही संभाग में चल रहे कार्यो की सामान्य जानकारी ली।उल्लेखनीय है कि श्री कावरे वर्ष 2008 बैच के आईएएस है।

नव नियुक्त संभागायुक्त महादेव कावरे से कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने की सौजन्य मुलाकात

रायपुर। नव नियुक्त संभागायुक्त श्री महादेव कावरे से कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने की सौजन्य मुलाकात की। संभागायुक्त श्री कावरे को कलेक्टर डॉ. सिंह ने पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया और शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर अपर कलेक्टर द्वय श्री देवेंद्र पटेल, श्री कीर्तिमान सिंह राठौर भी उपस्थित थे।

प्रदेश में नवीन औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने पर जोर : उद्योग मंत्री

■ सीएसआईडीसी के संचालक मण्डल की बैठक सम्पन्न

रायपुर। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री लखनलाल देवांगन ने सीएसआईडीसी की बैठक में कहा है कि प्रदेश की नई औद्योगिक नीति 1 नवम्बर 2024 से लागू होगी। नई औद्योगिक नीति के आधार पर यहां निवेश करने का एक बड़ा आकर्षण होगा, जो न केवल राज्य के विकास को तेजी से आगे बढ़ाने में मदद करेगा, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को और मजबूती प्रदान करेगा। इससे प्रदेश में बेहतर औद्योगिक वातावरण का निर्माण होगा और प्रदेश के निवासियों को रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खनिज संसाधनों से भरपूर छत्तीसगढ़ में उद्योग धंधे स्थापित करने की भरपूर संभावनाएं हैं।

छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम (सीएसआईडीसी) के संचालक मण्डल की 152वीं बैठक वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री सह अध्यक्ष सीएसआईडीसी श्री लखन लाल देवांगन की अध्यक्षता में उद्योग भवन में संपन्न हुई। बैठक में सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग श्री अंकित आनंद, संचालक नगर तथा ग्राम निवेश श्री सौरभ कुमार, सीएसआईडीसी के प्रबंध संचालक श्री पी. अरूण

प्रसाद, वित्त विभाग के उप सचिव श्रीमती पूजा शुक्ला मिश्रा उपस्थित थे। बैठक में निम्नानुसार महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये।

नवा रायपुर, अटल नगर सेक्टर-22 में मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा की गई घोषणा के अनुरूप 141.84 एकड़ में फार्मास्युटिकल पार्क की स्थापना किये जाने की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई। पार्क की स्थापना से नवीन निवेश के साथ - साथ स्थानीय रोजगार को बढावा मिलेगा। जिला जांजगीर-चांपा के ग्राम गतवा, बिर्रा एवं सिलादेही में निगम के आधिपत्य की 881.60 एकड भूमि पर आदर्श औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई। जिला जांजगीर-चांपा के ग्राम भागोडीह, ग्राम मुक्ताराजा, ग्राम सरहर एवं ग्राम रिस्दा में निगम के आधिपत्य की भूमि में 245.29 एकड़ में आदर्श औद्योगिक क्षेत्र एवं 111.02 एकड में टैक्सटाईल पार्क की स्थापना हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई। जिला-राजनांदगांव के ग्राम बिजेतला की 421.9 एकड़ भूमि में नवीन आदर्श औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई। भारत सरकार की एमएसई-सीडीपी योजनांतर्गत छत्तीसगढ राज्य में सीएसआईडीसी के अधीनस्थ स्थापित 13 औद्योगिक क्षेत्रों के उन्नयन कार्यों हेतु परियोजना प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया।

राज्य के समस्त एच.ओ.डी एवं अन्य कार्यालयो का संचालन अटल नगर, नवा रायपुर में किया जाना प्रारंभ हो गया है। इस अनुक्रम में सीएसआईडीसी के नवा रायपुर स्थित भूमि पर उद्योग भवन का निर्माण किये जाने की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई। उपरोक्त निर्णय छत्तीसगढ़ राज्य में औद्योगिक निवेश को बढ़ाने, फलस्वरूप औद्योगिकीकरण को बढ़ाने तथा नवीन निवेश आकर्षित करने एवं स्थानीय रोजगार को बढ़ावा प्रदान किये जाने की दिशा में बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है जो कि विकसित भारत, विकसित छत्तीसगढ़ की परिकल्पना को साकार किये जाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगे।

छत्तीसगढ़ रोजगार ऐप से हो सकेगा रोजगार पंजीयन और नवीनीकरण

रायपुर। संचालनालय रोजगार विभाग रायपुर की ओर से जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र जगदलपुर में छत्तीसगढ़ रोजगार ऐप विकसित किया गया है। इच्छुक शिक्षित आवेदक छत्तीसगढ़ रोजगार ऐप के माध्यम से स्वयं अपने मोबाइल के माध्यम से रोजगार पंजीयन और नवीनीकरण कर सकते हैं। प्रदेश के युवाओं को अब घर बैठे रोजगार पंजीयन की सुविधा मिल रही है। साथ ही रोजगारपरक सुविधाओं का लाभ भी मिल रहा है। युवाओं को रोगजार की जानकारी अब छत्तीसगढ़ रोजगार एप पर मिलेगी। बेरोजगार युवाओं को मोबाइल एप के माध्यम से रोजगार के लिए पंजीयन की व्यवस्था, पहले से हो चुके पंजीयन का नवीनीकरण और नवीन सुविधाएं प्राप्त करने के लिए छत्तीसगढ रोजगार एप बनाया गया है। इससे छत्तीसगढ़ के लाखों युवाओं को जिला रोजगार और स्व-रोजगार मार्गदर्शन केन्द्र जाने की आवश्यकता नहीं है। पंजीयन के भौतिक सत्यापन के लिए जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र में जाने की आवश्यकता नहीं है। सत्यापन आधार आधारित ओटीपी के माध्यम से किया जाता है। इसके साथ ही रोजगार पंजीयन पत्रक एप के माध्यम से डाउनलोड किया जा सकता है। इस एप पर शासकीय-अर्धशासकीय विभागों की रिक्तियां, विभाग द्वारा आयोजित किए जाने वाले रोजगार मेला-प्लेसमेंट कैंप की अद्यतन जानकारी भी उपलब्ध कराई जाती है। रोजगार सहायता की प्रक्रिया अब और अधिक सरल एवं सुलभ हो गई है, जिससे प्रदेश के युवाओं को रोजगार प्राप्त करने में अत्यधिक सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार की पहल से https://erojgar.cg.gov.in पर उपलब्ध कराया गया है।

आदिवासियों को फिर मिलेंगे चरण पादुका, साइकिल चलायेंगी छात्राएं

■ साय सरकार फिर शुरू करेगी योजना

रायपुर। छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार तेंदूपत्ता तोड़ाई के लिए आदवासियों को फिर चरण पादुका बांटेंगी। वहीं नोनी (छात्रायें) साइकिल पर सवार होकर स्कूल जा सकेंगी। दरअसल, प्रदेश की साय सरकार जल्द ही चरण पादुका वितरण योजना और सरस्वती सायकल योजना फिर से शुरू करने जा रही है। सीएम विष्णुदेव साय ने इसकी घोषणा की है। बता दें कि ये दोनों योजनायें रमन राज में 15 सालों तक चल चुकी हैं, जिसे साय सरकार दोबारा शुरू करने जा रही है।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि केन्द्र सरकार की भांति छत्तीसगढ़ की सरकार भी गरीबों के कल्याण, विकास और खुशहाली के लिए समर्पित है। मोदी की गांरटी के तहत गांव गरीब, किसान, महिला, युवा आदिवासी पिछड़े सभी वर्ग के विकास के लिए योजना चलायी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने कार्यभार संभालते ही कैबिनट की पहली बैठक में 18 लाख से अधिक आवासहीन परिवारों को पक्का मकान बनाने की स्वीकृति दी थी। तेन्दूपत्ता तोड़ने वालों को फायदा पहुंचाने के लिए इस बार साढ़े पांच हजार रूपए मानक बोरा की दर से पत्ता खरीदी की गई और पूरे सीजन पत्ता खरीदा गया।

साय ने कहा कि अब तेन्दूपत्ते को बेचने के बाद होने वाले

फायदे को भी बोनस के रूप में संग्राहकों को दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने 21 क्विंटल धान प्रति एकड़ खरीदने की गारंटी पूरी की है। 3100 रूपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी की गई। मोदी की इस गारंटी के पूरे होने से छत्तीसगढ़ के किसानों को अच्छा फायदा हुआ है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि प्रदेश के किसानों को 3716 करोड़ रूपए दो साल के बकाया धान का बोनस के रूप में भी भुगतान कर दिया गया है।

सीएम साय ने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने दोनों योजनाओं को बंद कर दिया था। भाजपा की सरकार बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ के उद्देश्य को पूरा करते हुए बालिकाओं को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने साइकिल देने योजना की शुरुआत करने जा रही है। पूर्व में डेढ़ दशक तक भाजपा की सरकार ने तेंदूपत्ता संग्राहकों और बालिकाओं के हित को देखते हुए दोनों योजनाएं शुरू की थी।

छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग, कार्यालय मुख्य अभियंता
महानदी गोदावरी कछार, रायपुर (छ.ग.)

इ-प्रोक्यूरमेंट निविदा सूचना

eprocurement Portal : https://eproc.cgstate.gov.in

निम्नलिखित कार्यों के लिए दिनांक 21.08.2024, 17:30 तक ऑन लाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती है-

स. क्र.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत	सिस्टम निविदा क्र.	निविदा सूचना क्र. एवं दिनांक	आमंत्रण क्रमांक
1,	बालोद जिले के विकासखण्ड डौण्डी की कोटागांव व्यपवर्तन योजना की मुख्य नहर आर.डी. 0 मी. से 3750 मी. तक रिमाडलिंग एवं सी. सी. लाईनिंग कार्य, 01 नग डी.सी. 03 नग व्ही.आर.बी., 01 नग फाल, 01 नग ओपनिंग चैनल, 02 नग इनलेट का निर्माण एवं 10 नग कोलाबा फिक्सिंग तथा 06 नग निर्मित पक्के कार्यों के मरम्मत कार्य	रु. 220.65 लाख (दिनांक 01.08.2010 के एस.ओर. आर. तथा संशोधित 01.08.2014 के अनुसार)	156761	निविदा सूचना क्र. 02/बैलेली/2024-25, बालोद दिनांक 31.07.2024	प्रथम
2	बालोद जिले के विकासखण्ड डौण्डी की कुंआगोंदी व्यपवर्तन का मुख्य नहर का जीर्णोद्धार एवं नहर लाईनिंग कार्य आर.डी. 0 मी. से 5720 मी., 02 नग सुपर पैसेज, 04 नग व्ही.आर.बी., 03 नग फाल एवं 28 नग आउटलेट का निर्माण कार्य	रू. 222.09 लाख (दिनांक 01.08.2010 के एस.ओर. आर. तथा संशोधित 01.08.2014 के अनुसार)	156762	निविदा सूचना क्र. 03/बैलेली/2024-25, बालोद दिनांक 31.07.2024	प्रथम
3	बालोद जिले के विकासखण्ड डौण्डी की भर्रीटोला व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर के आर.डी. 0 से आर. डी. 5825 मी. तक रिमाडलिंग एवं लाईनिंग कार्य, 06 नग पूर्व निर्मित पक्के कार्यों का मरम्मत, 10 नग नये पक्के कार्यों का निर्माण एवं 18 नग कोलाबा लगाने का कार्य	रु. 235.91 लाख (दिनांक 01.08.2010 के एस.ओर. आर. तथा संशोधित 01.08.2014 के अनुसार)	156764	निविदा सूचना क्र. 04/बैलेली/2024-25, बालोद दिनांक 31.07.2024	प्रथम

अन्य विवरण एवं विस्तृत निविदा छत्तीसगढ़ शासन की ई-प्रोक्योरमेंट वेब साइट https://eproc.cgstate.gov.in पर दिनांक 07.08.2024 समय 17.31 बजे से देखे तथा डाउनलोड़ किये जा सकते हैं।

नोट- निविदा में भाग लेने हेतु ठेकेदारों को ई-प्रोक्योरमेंट वेबसाईट https://eproc.cgstate.gov.in पर नामांकित / पंजीयन तथा लोक निर्माण विभाग की एकीकृत पंजीयन प्रणाली के अंतर्गत ठेकेदार को उपयुक्त श्रेणी में पंजीयन कराना अनिवार्य है।

कार्यपालन अभियंता
जल संसाधन संभाग, बालोद
कृते, मुख्य अभियंता, महानदी गोदावरी कछार
जल संसाधन विभाग, रायपुर (छ.ग.)

जी- 242501539/9

पश्चिम एशिया में संकट और गहरायेगा

अनिल त्रिगुणायत

ईरान की राजधानी तेहरान में हमास के नेता और फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री रह चुके इस्माइल हानिये की मिसाइल हमले में हत्या से पश्चिम एशिया में तनाव एवं संघर्ष में बढ़ोतरी ही होगी। हालांकि इस्राइल ने अभी तक इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, पर ईरान, हमास, फिलिस्तीनी अथॉरिटी और फिलिस्तीन से सहानुभूति रखने वाले विभिन्न देश एवं समूह इस्राइल को ही दोषी ठहरा रहे हैं। हानिये और हमास के अनेक नेताओं पर पहले भी हमले हो चुके हैं। इनका नाम इस्राइल की हिट लिस्ट में था क्योंकि इस्राइल ने हमास को खत्म करने को अपना प्रमुख एजेंडा बनाया हुआ है। पिछले साल सात अक्तूबर को जब हमास ने इस्राइल पर हमला किया था, तब उस हमले को इस्राइली इंटेलिजेंस एवं सुरक्षा व्यवस्था में बड़ी सेंध माना गया था। तेहरान में जिस तरह से बिल्कुल निशाना लगाकर हमला हुआ है, उससे इस्रायली सुरक्षा व्यवस्था की साख में सुधार होगा। इस घटना से इस्राइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की राजनीतिक छवि को भी मदद मिलेगी, जिसमें कुछ समय से ह्रास आया है। इस्राइल ने हमास और हिज्बुल्लाह के कुछ बड़े कमांडरों को भी मारा है। इन कार्रवाइयों के आधार पर नेतन्याहू को राजनीतिक लाभ मिल सकता है। वे अपने देश में यह दावा कर सकते हैं कि जो लोग सात अक्तूबर और बाद में इस्राइल पर हमलों के लिए जिम्मेदार थे, उन्हें मार दिया गया है। लेकिन इस हमले से गाजा में युद्धविराम के लिए हो रही कोशिशों को बड़ा धक्का लगा है। हमास की ओर से इस्माइल हानिये मुख्य वार्ताकार थे। इस हमले का तेहरान में होना ईरान की संप्रभुता का सीधा उल्लंघन है। इस पहलू से भी इस कार्रवाई की जटिलता बढ़ जाती है। अब ईरान इसका बदला किस तरह से लेगा, इसे लेकर अनुमान ही लगाया जा सकता है। वह कुछ समय प्रतीक्षा करेगा और फिर हमला करेगा, या फिर हमास, हिज्बुल्लाह, हूथी और इराकी समूहों के जरिये हमले करायेगा, यह कहना मुश्किल है। ईरान के सामने अनेक विकल्प हैं, जिनमें से वह कुछ का इस्तेमाल कर सकता है। ईरान के सर्वोच्च नेता और राष्ट्रपति ने अपने बयानों में कार्रवाई की बात की है। कुछ खबरों में बताया गया है कि ऐसे हमलों के लिए शायद आदेश भी जारी कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में मेरा मानना है कि पश्चिम एशिया में स्थिति और अधिक बिगड़ेगी। अब देखना यह है कि बड़ी वैश्विक शक्तियां- अमेरिका, चीन, रूस, यूरोपीय संघ- ऐसी स्थिति में क्या हस्तक्षेप करती हैं। अगर उन्होंने कोई कारगर कदम नहीं उठाया, तो लड़ाई बढ़ने के पूरे आसार हैं। कुछ दिन पहले ही चीन ने हमास और फतह समेत 14 फिलिस्तीनी समूहों के बीच एक समझौता कराया है। हालांकि अमेरिका और चीन दोनों ही दो देश बनाने के समाधान का समर्थन करने का दावा करते हैं, पर उनके व्यवहार से यह इंगित होता है कि ये दोनों अलग-अलग छोर पर खड़े हैं। जब चीन में फिलिस्तीन समूहों की बैठक हो रही थी, उसी समय इस्राइली प्रधानमंत्री अमेरिका के दौरे पर थे। ये दोनों घटनाएं महत्वपूर्ण हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन चुनावी जिम्मेदारियों से मुक्त हो चुके हैं। वे दोनों युद्धों- यूक्रेन और गाजा- पर अधिक ध्यान दे सकते हैं। ये युद्ध नयी विश्व व्यवस्था को परिभाषित करने की क्षमता रखते हैं, अगर ऐसी कोई विश्व व्यवस्था बनती है तो। फिलिस्तीन के लिए संघर्ष में एक बड़ी बाधा फिलिस्तीनी समूहों की आपसी प्रतिस्पर्धा और प्रतिद्वंद्विता रही है, जिसका फायदा इस्राइल ने भी उठाया है। नेतन्याहू पर भी हमास को समर्थन देने के आरोप लगते रहे हैं। सात अक्तूबर के हमले के बाद ही उन्होंने हमास को पूरी तरह खत्म करने की बात कही है। चीन की इस कोशिश का स्वागत अरब के देशों समेत कई देशों ने किया है। नेतन्याहू का कहना है कि वे गाजा को हमास या फतह के हाथ में नहीं जाने देंगे। अब देखना है कि फिलिस्तीनी समूहों की एकता का भविष्य कैसा होता है। हानिये की हत्या से हमास के मनोबल पर कुछ असर पड़ सकता है और शायद फतह के लिए प्रतिस्पर्धा कुछ आसान हो सकती है, पर मुझे नहीं लगता है कि इस घटना से समूहों की एकता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। यदि वे चाहते हैं कि फिलिस्तीन स्वतंत्र राष्ट्र बने, तो उन्हें एकजुट रहना ही होगा क्योंकि उनकी आपसी फूट का फायदा इस्राइल उठाता रहा है। हानिये की जगह खालेद मशाल या कोई और नेता आ जायेगा। फिलहाल सबसे बड़ी चिंता पश्चिम एशिया में अशांति बढ़ने को लेकर है।

उत्तर पूर्व के साथ एकीकरण!

हर्षवर्धन श्रृंगला

उत्तर-पूर्वी परिषद में उत्तर बंगाल के एकीकरण को लेकर हालिया चर्चा कोई नई बात नहीं है। दरअसल, इस धारणा ने हाल के दिनों में नए सिरे से लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। वास्तव में, उत्तर पूर्व के साथ उत्तर बंगाल एकीकरण एक व्यवहारिक समाधान है, जो उत्तरी बंगाल के लोगों के सामने आने वाली विभिन्न चुनौतियों का समाधान करता है। निश्चित ही, इस क्षेत्र को लंबे समय से उपेक्षित रखा गया है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में विकास कोलकाता-केंद्रित है, जिसका लाभ केवल दक्षिण बंगाल को मिल रहा है।

दरअसल, सम्प्रदायों द्वारा ध्यान नहीं दिए जाने की वजह से उत्तर बंगाल को राज्य के बाकी हिस्सों से अलग करना क्षेत्र के लोगों का पसंदीदा विकल्प रहा है। परिणामस्वरूप, उत्तर बंगाल में पश्चिम बंगाल से अलग होने की मांग को लेकर कई राजनीतिक आंदोलन देखने को मिलते रहे हैं। गोरखाओं, राजवंशियों और कामतापुरी द्वारा अलग राज्य की मांग पश्चिम बंगाल के कुछ उपेक्षित समुदायों की हताशा को दर्शाती है, जबकि अलग राज्य की मांग उत्तरी बंगाल के विभिन्न समुदायों की प्रबल इच्छा है, हालांकि यह एक जटिल मुद्दा है, क्योंकि प्रत्येक समुदाय पहचान और आत्म-स्वायत्तता की अलग-अलग भावनाएं रखता है। इसलिए, वर्तमान परिपेक्ष्य में उत्तर-पूर्वी परिषद में उत्तर बंगाल के एकीकरण को वहां के लोगों के सामने आने वाली आर्थिक चुनौतियों के लिए एक आशाजनक समाधान के रूप में देखा जाना चाहिए।

गंगा के उत्तर में स्थित राज्य के आठ जिलों- दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार, मालदा, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर और अलीपुरद्वार को अक्सर सामूहिक रूप से उत्तर बंगाल कहा जाता है। ऐतिहासिक दृष्टि से, यह क्षेत्र पूर्वी भारत और पवित्र गंगा के मैदान के बीच एक संक्रमणकालीन क्षेत्र था। विभाजन के साथ, पूर्वी भारत कई तरह की चुनौतियों वाला क्षेत्र बन गया। दूरी और कई अन्य चुनौतियों की वजह से यहां कई तरह के प्रतिकूल आर्थिक परिणाम देखने को मिले, हालांकि उत्तरी बंगाल के इन जिलों पर विभाजन के प्रभाव का असर दिखा और ये अपनी भौगोलिक सीमाओं से दूर हो गए। ये जिले पश्चिम बंगाल के सबसे उपेक्षित हिस्सों में शामिल हैं,

हालांकि यह क्षेत्र रणनीतिक और देश की सुरक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है।

उत्तर बंगाल का एक बड़ा हिस्सा सिलीगुड़ी कॉरिडोर द्वारा परिभाषित किया गया है, जो पश्चिम बंगाल में एक प्रमुख शहरी केंद्र है, जो %चिकन नेक% के पास स्थित होने के कारण रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह उत्तर-पूर्वी राज्यों को शेष भारत से जोड़ता है। इस स्थिति की वजह से एक महत्वपूर्ण व्यापार और पारगमन बिंदु के रूप सिलीगुड़ी कॉरिडोर प्रसिद्ध है, जो आर्थिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है, हालांकि सुगम परिवहन, पर्याप्त लॉजिस्टिक बुनियादी ढांचे, नियामक बाधाओं और क्षेत्रीय आर्थिक असमानताओं की कमी के कारण यह क्षेत्र अपनी पूरी क्षमता से विकसित नहीं हो पाया है। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और चीन के पड़ोसी देश सिलीगुड़ी कॉरिडोर, भारत को म्यांमार के माध्यम से दक्षिण पूर्व एशिया और पूर्वी एशिया से जोड़ता है, जो देश के लिए रणनीतिक महत्व रखता है, लेकिन केंद्र और राज्य में समन्वय में कमी की वजह से प्रभावित रहता है। उत्तर पूर्व भारत में बुनियादी ढांचे में बड़े पैमाने पर सुधार सभी के सामने है। बुनियादी ढांचे को बढ़ाकर और इसे उभरते ट्रांस-एशियाई कनेक्टिविटी नेटवर्क से जोड़कर दक्षिण पूर्व एशिया के लिए एक पुल के रूप में सिलीगुड़ी कॉरिडोर का विकास समय की मांग है, लेकिन यह तभी संभव हो सकता है, जब उत्तर बंगाल स्वतंत्र रूप से संसाधनयुक्त होगा।

दुनिया भर में राजनीतिक सीमाओं से विभाजित उप-क्षेत्रों के भीतर आर्थिक तालमेल पुनर्जीवित हो रहा है। सामान्य बुनियादी ढांचा और आर्थिक स्थान, जो इस निकटता को स्वीकार करते हैं, निश्चित ही, यह बेहतर व्यवस्था की नींव हैं। समग्र उत्तर पूर्व की अवधारणा इसी तर्क की स्वीकृति है। इस परिप्रेक्ष्य से देखने पर, उत्तर बंगाल को उत्तर-पूर्वी भारत से जोड़ने के लिए जिस सामंजस्य का लाभ लिया जा सकता है, उसका तर्क स्पष्ट है, लेकिन यह समझना मुश्किल है कि उत्तर पूर्व को कूच बिहार की पूर्वी सीमा से क्यों, बल्कि इसकी निर्भरता दार्जिलिंग और डुआर्स के माध्यम से सिक्किम पार करने के बाद फिर से शुरू की जानी चाहिए।

ऐसी व्यवस्थाओं का लाभ उनके उपकेंद्रों के इतर भी देखने को मिलता है। बंगाल हमेशा से एक समुद्री राज्य रहा है। उत्तर पूर्व के साथ भूमि संबंधों को मजबूत किए जाने के बाद पूरे पश्चिम बंगाल के लिए बंगाल की खाड़ी के बड़े क्षेत्र के प्रवेश द्वार के रूप में अपनी ऐतिहासिक भूमिका का विस्तार करने का अवसर पैदा होगा। अंदरूनी इलाके का आर्थिक भार, जिसने कोलकाता और कलकत्ता बंदरगाह को अपने समय के महान आर्थिक केंद्रों में से एक बना दिया था, अब उत्तर पूर्व के साथ इस जैविक संबंध को पुनर्जीवित करके उसे उत्तरी बंगाल के माध्यम से फिर से जागृत करने में मदद मिलेगी। उत्तर पूर्व में बुनियादी ढांचे का विकास और विदेश नीति के नेबरहुड फर्स्ट और एक्ट ईस्ट स्तंभों पर प्रधानमंत्री मोदी का ध्यान उत्तर बंगाल को ऐतिहासिक अवसर प्रदान करता है। उत्तर-पूर्वी परिषद (एनईसी) भारत के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए नोडल एजेंसी है, जिसे भारत के उत्तर-पूर्व के विकास के रास्ते में आने वाली बुनियादी बाधाओं को दूर करने के इरादे से बनाया गया है।

सभी केंद्रीय मंत्रालयों के वार्षिक बजट का लगभग 10 प्रतिशत उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के विकास के लिए आवंटित किया जाता है। उत्तर-पूर्वी राज्यों में विकास की सामान्य बाधाएं उत्तर बंगाल पर भी लागू होती हैं, लेकिन एनईसी का लाभ उत्तर बंगाल और उसके लोगों तक नहीं पहुंचता है। उत्तर बंगाल, जो हिमालय की तलहटी में स्थित है, शेष उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के समान चुनौतियों के बावजूद एनईसी के तहत किसी भी योजना या कार्यक्रम का लाभार्थी नहीं है। उत्तर बंगाल के पहाड़ी क्षेत्रों में पश्चिम बंगाल की तुलना में उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के साथ अधिक समानता है, विशेष रूप से संस्कृति और इलाके में समानता के अलावा सामाजिक और विकासात्मक चुनौतियों के मामले में। सभी उत्तर-पूर्वी राज्यों की तरह, उत्तरी बंगाल एक सीमावर्ती क्षेत्र है, जिसके कारण इसे समान विकास और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में, उत्तर-पूर्वी परिषद के तहत कार्यक्रमों में इसका शामिल होना तार्किक और स्वाभाविक रूप से उचित है।

इसके अलावा, उत्तर-पूर्वी राज्यों को अन्य देशों से भी विकासात्मक सहायता मिलती है, लेकिन ये लाभ केवल उत्तर-पूर्व भारत को परिभाषित करने के कारण उत्तर बंगाल तक नहीं पहुंचता है। उदाहरण के लिए, जापान ने %एक्ट ईस्ट फोरम% के तहत उत्तर पूर्व में बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए लगभग 2 बिलियन डॉलर का निवेश किया है। भारत के उत्तर पूर्व में जापान द्वारा वित्तपोषित कुछ प्रमुख विकासात्मक परियोजनाओं में गुवाहाटी जल आपूर्ति परियोजना, असम में सीवेज परियोजना, असम-मेघालय में उत्तर-पूर्व सड़क नेटवर्क कनेक्टिविटी परियोजना, मेघालय में एक पनबिजली स्टेशन का नवीनीकरण और आधुनिकीकरण, जैव विविधता संरक्षण शामिल हैं। इसके साथ ही, सिक्किम में वन प्रबंधन और नागालैंड में वन संरक्षण आजीविका जैसी परियोजनाएं भी शामिल हैं, जबकि जापान ने ऐसे कार्यक्रमों को पड़ोसी क्षेत्रों में विस्तारित करने की इच्छा व्यक्त की है। दुर्भाग्य से ऐसी सहायता उत्तर-पूर्वी परिषद द्वारा प्रशासित क्षेत्रों तक ही सीमित है, इसलिए उत्तर बंगाल को एनईसी के दायरे में लाना इस क्षेत्र के लिए आवश्यक विकासात्मक सहायता में बाधा बनने वाली कुछ अड़चनों को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

पश्चिम में सिक्किम से लेकर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक उत्तर-पूर्वी राज्यों का क्षेत्र पूर्वी हिमालय श्रृंखला में स्थित है और इस तरह इन क्षेत्रों में जातीय समूह महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और जातीय समानताएं साझा करते हैं। दार्जिलिंग और सिक्किम की आबादी में मुख्य रूप से लेप्चा, भूटिया और नेपाली (गोरखा) जैसे जातीय समूह शामिल हैं। उनकी साझा शारीरिक विशेषताएं उनके सामान्य वंश का प्रमाण हैं। दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में लोगों की जीवनशैली उनके पहाड़ी वातावरण ये गहराई से जुड़ी हुई हैं।

पुराण दिग्दर्शन .... परिचयाध्याय

अष्टादश-संख्या-विज्ञान (भाग-9)

गतांक से आगे...

दशम पुराण स्कन्द- शिव भगवान् के नाना अवतारों के चरित्रों का आदेश करता हुवा विद्याकामस्तु गिरिशम के अनुसार ब्रह्मविद्या एवं ज्ञान के अधिकारी पुरुषों को शिव-उपासना की शिक्षा देता है।

ग्यारहवां भविष्य- पुराण धर्मार्थ काम मोक्ष के प्रथम साधन आरोग्य की प्राप्ति के लिए आरोग्यं भास्करादिच्छेत के अनुसार सूर्य भगवान् की उपासना का महत्त्व बतलाता है।

बारहवां ब्रह्म वैवर्त पुराण गणेश आदि देत्रों के चरित्रों का विधायक है। तेरहवाँ मार्कण्डेय पुराण शक्ति चरित्रों का खजाना है। ये दोनों पुराण साधनशक्तिशून्य एवं नानाविघ्न-संकुल कलिकाल के प्राणियों को कलौ चण्डीविनायकौ के अनुसार शक्ति और विघ्नराज की उपासना का आदेश करते हैं।

चौदहाँ वामन, पन्द्रहवाँ वाराह, सोलहवा मत्स्य, और सत्रहवां कूर्म ये चारों पुराण विष्णु भगवान् के सृष्टि क्रम से सम्बन्ध रखने वाले मुख्य चारों अवतारों का प्रधानतया निरूपण करते हुए मोक्षाभिलाषी अधिकारी को श्रीमन्नारायणमुकुन्द विष्णु भगवान् की शरणागति का आदेश करते हैं। इस प्रकार जीवों के कल्याणार्थ यज्ञ और शिव, सूर्य गणेश, दुर्गा तथा विष्णु श्रादि की पञ्चोपासना क्रमशः छहों पुराणों द्वारा बतलाई गई है।

अन्त में अठारहवां ब्रह्माण्डपुराण इस समस्त सृष्टि-प्रक्रिया का उपसंहार करता हुआ अपने मूल तत्त्व ब्रह्म की ओर संकेत करता है कि आकाशात्पतितं तोयं यथा गच्छति सागरम के सिद्धांतानुसार यह विविध प्रकार की उपासना एक ब्रह्मोपासना में परिणत हो जाती है। यही पुराणों के विशिष्ट-क्रम का वैज्ञानिक रहस्य है।

क्रमशः ...

यूँ ही राष्ट्र कवि नहीं कहा गया मैथिलीशरण गुप्त को

ललित गर्ग

मैथिलीशरण गुप्त का जन्म झाँसी के समीप चिरगाँव में 3 अगस्त, 1886 को हुआ। बचपन में स्कूल जाने में रूचि न होने के कारण इनके पिता सेठ रामचरण गुप्त ने इनकी शिक्षा का प्रबंध घर पर ही किया था और इसी तरह उन्होंने संस्कृत, अंग्रेजी और बांग्ला का ज्ञान प्राप्त किया। काव्य-लेखन की शुरुआत उन्होंने पत्र-पत्रिकाओं में अपनी कवितायें प्रकाशित कर की। इन्हीं पत्रिकाओं में से एक सरस्वती आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी के संपादन में निकलती थी। युवक मैथिली ने आचार्यजी की प्रेरणा से खड़ी बोली में लिखना शुरू किया। 1910 में उनकी पहला प्रबंधकाव्य रंग में भंग प्रकाशित हुआ। भारत-भारती के प्रकाशन के साथ ही वे एक लोकप्रिय कवि के रूप में स्थापित हो गये। उनकी भाषा एवं सृजन से हिन्दी की साहित्यिक भाषा का विकास हुआ। उन्होंने पराधीनता काल में मुंह खोलने का साहस न करने वाली जनता का नैराश्य-निवारण करके आत्मविश्वास भरी ऊर्जामयी वाणी दी, इससे भारत-भारती जन-जन का कंठहार बन गयी थी। इस कृति ने स्वाधीनता के लिये जन-जागरण का शंखनाद किया। हिन्दी साहित्य में गद्य को चरम तक पहुंचाने में जहां प्रेमचंद्र का विशेष योगदान माना जाता है वहीं पद्य और कविता में राष्ट्र कवि मैथिलीशरण गुप्त को सबसे आगे माना जाता है।

पर्वतों की ढलान पर हल्का हरा और गहरा हरा रंग एक-दूसरे से मिले बिना फैले पड़े हैं....। कैसा सही वर्णन किया है किसी साहित्यकार ने। लगता है कि हमारे मन की बात को किसी ने शब्द दे दिये। ठीक इसी प्रकार अगर हम ऊपर उठकर देखें तो दुनिया में अच्छाई और बुराई अलग-अलग दिखाई देगी। भ्रष्टाचार के भयानक विस्तार में भी नैतिकता स्पष्ट अलग दिखाई देगी। आवश्यकता है कि नैतिकता एवं राष्ट्रीयता की धवलता अपना प्रभाव उत्पन्न करे और उसे कोई दूषित न कर पाये। इस आवाज को उठाने और राष्ट्रजीवन की चेतना को मन्त्र-स्वर देने वाले राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय कवि थे। उन्होंने आम-जन के बीच प्रचलित देशी भाषा को मांजकर जनता के मन की बात, जनता के लिये, जनता की भाषा में कही इसीलिये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्रकवि का सम्मान देते हुये कहा था, मैं तो मैथिलीशरणजी को इसलिये बड़ा मानता हूं कि वे हम लोगों के कवि हैं और राष्ट्रभर की आवश्यकता को समझकर लिखने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी रचनाओं में देशभक्ति, बंधुत्व भावना, राष्ट्रीयता, गांधीवाद, मानवता तथा नारी के प्रति करुणा और सहानुभूति के स्वर मुखर हुए। इनके काव्य का मुख्य स्वर राष्ट्र-प्रेम, आजादी एवं भारतीयता है। वे भारतीय संस्कृति के गायक थे। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के मार्गदर्शन में जिन कवियों ने ब्रज-भाषा के स्थान पर खड़ी बोली हिन्दी को अपनी काव्य-भाषा बनाकर उसकी क्षमता से विश्व को परिचित कराया, उनमें गुप्तजी का नाम सबसे प्रमुख है। उनकी काव्य-प्रतिभा का सम्मान करते हुये साहित्य-जगत उन्हें राष्ट्रकवि के रूप में याद करता रहा है। देश एवं समाज में क्रांति पैदा करने का उनका दृढ़ संकल्प समय-समय पर मुखरित होता रहा है।

क्या भाजपा के लिए चुनौती बनेगा राहुल और अखिलेश?

अजय कुमार

लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नई दिशा दी है। इस सियासी गठबंधन ने बीजेपी को बहुमत का आंकड़ा प्राप्त करने से रोका, और मोदी सरकार को सहयोगी दलों के समर्थन पर निर्भर रहने पर मजबूर कर दिया। चुनाव परिणामों के बाद से, बीजेपी के बड़े नेता लगातार कांग्रेस और सपा गठबंधन के विघटन की भविष्यवाणी कर रहे हैं। हालांकि, यह जोड़ी न केवल चुनाव के दौरान बल्कि अब संसद में भी एक साथ नजर आ रही है। लोकसभा में राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच की केमिस्ट्री यह दर्शाती है कि यह साझेदारी लंबी चलने वाली है और बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकती है।

लोकसभा में बजट पर चर्चा के दौरान, राहुल गांधी ने बजट बनाने वाले 20 अधिकारियों में केवल एक अल्पसंख्यक और एक ओबीसी अधिकारी की उपस्थिति की ओर इशारा किया। इसके साथ ही, उन्होंने जातिगत जनगणना की मांग उठाई। राहुल गांधी के सवाल उठाने के अगले दिन, संसद में जाति के मुद्दे पर बीजेपी और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि जातिगत जनगणना की बात वे कर रहे हैं जिनकी अपनी जाति का पता नहीं है। यह टिप्पणियां राहुल गांधी की तरफ इशारा करती थीं। राहुल गांधी ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जो भी दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों की बात करता है, उसे गालियाँ ही मिलती हैं। उन्होंने महाभारत के अर्जुन की उपमा देते हुए कहा कि उन्हें जातिगत जनगणना का लक्ष्य स्पष्ट है और वे इसके लिए आलोचनाएँ खुशी से स्वीकार करेंगे।

अखिलेश यादव ने इस बहस में आक्रमक तरीके से दखल दिया। उन्होंने अनुराग ठाकुर पर चिल्लाते हुए

पूछा कि आप किसी की जाति कैसे पूछ सकते हैं। अखिलेश ने कहा कि जब आप बड़े नेता और मंत्री हैं, तो जाति पूछने का अधिकार किसने दिया? उनकी यह आक्रमक प्रतिक्रिया और राहुल गांधी के समर्थन ने सियासी परिदृश्य को गरमा दिया। दोनों नेताओं की यह सियासी केमिस्ट्री चुनाव के दौरान और संसद में भी साफ नजर आ रही है। वे एक साथ बैठते हैं और हर मुद्दे पर सरकार को घेरते हैं, जिससे उनकी साझेदारी की मजबूती स्पष्ट होती है।

अखिलेश यादव ने 18वीं लोकसभा सत्र के पहले दिन अपने अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद को महत्व दिया, जबकि राहुल गांधी ने भी पूरे सत्र के दौरान अवधेश प्रसाद को मान्यता दी। राहुल गांधी के जन्मदिन पर अखिलेश यादव ने उन्हें बधाई दी, जिसे राहुल ने धन्यवाद के साथ स्वीकार किया। यह सियासी दोस्ती की गहराई को दर्शाता है और संकेत करता है कि यूपी के दो नेताओं की यह जोड़ी हिंदुस्तान की राजनीति में नई दिशा देने के लिए तैयार है।

2024 के लोकसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस के बीच गठबंधन ने केवल चुनावी सहयोग ही नहीं किया, बल्कि दोनों दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच एक बेहतर तालमेल भी स्थापित किया। अखिलेश यादव ने राहुल गांधी के समर्थन में कन्नौज में वोट मांगे, और राहुल गांधी ने रायबरेली में अखिलेश के लिए जनसभा की। 2017 में भले ही सपा-कांग्रेस का गठबंधन सफल नहीं रहा था, लेकिन 2024 में यह जोड़ी बीजेपी को कड़ी टक्कर देने में सफल रही।

उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से बीजेपी केवल 33 सीटें ही जीत सकी, जबकि सपा ने 37 और कांग्रेस ने 6 सीटें जीतीं। यह 2019 के लोकसभा चुनावों के विपरीत है, जहां बीजेपी 62 सीटों पर विजयी हुई थी। राहुल गांधी का संविधान और आरक्षण पर आधारित नैरेटिव और अखिलेश यादव का पीडीए फॉर्मूला बीजेपी के सारे मंसूबों पर पानी फेरने में सफल रहा। राहुल और अखिलेश की केमिस्ट्री केवल चुनाव तक सीमित नहीं रही, बल्कि अब संसद में भी दिखाई दे रही है। वे एकजुट होकर मोदी सरकार को घेरने के साथ-साथ एक-दूसरे के लिए सियासी ढाल भी बन गए हैं।

राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच तालमेल को पीएम मोदी और बीजेपी के कई बड़े नेता महसूस कर रहे हैं। पीएम मोदी ने पिछले संसद सत्र के दौरान कांग्रेस को निशाने पर रखा था, जिससे यह अंदाजा लगाया गया कि इंडिया गठबंधन के घटक दलों के बीच दरार डालने की रणनीति के तहत दांव चल रहे हैं। मोदी ने कहा था कि कांग्रेस जिस पार्टी के साथ गठबंधन करती है, उसी के वोट खा जाती है। उन्होंने राम गोपाल यादव से कहा था कि वह अपने भतीजे (अखिलेश) को समझाएं और उन्हें याद दिलाएं कि राजनीति में कदम रखते ही भतीजे के पीछे सीबीआई का फंदा लगाने वाले कौन थे। बीजेपी की बैठक में भूपेंद्र चौधरी ने भी कहा था कि सपा के वोटबैंक पर कांग्रेस की नजर है।

राजनीतिक विश्लेषकों की मानें तो इंडिया गठबंधन की एकजुटता को तोड़ने की रणनीति के तहत ही पीएम मोदी ने यह टिप्पणियां कीं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के सियासी आधार पर ही सपा की ताकत बनी है, जो कभी कांग्रेस का हुआ करता था। 90 के दशक के बाद कांग्रेस के कमजोर होने के कारण सपा मजबूत हुई। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सबसे बड़ा झटका उत्तर प्रदेश में लगा है। यूपी में कांग्रेस को सियासी संजीवनी मिली है और सपा को ताकत। अगर सपा और कांग्रेस इसी तरह 2027 के विधानसभा चुनाव में उतरती हैं, तो बीजेपी के लिए सियासी टेंशन बढ़ना लाजमी है।

अखिलेश यादव ने कई सियासी प्रयोग किए हैं, लेकिन 2024 के चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन से उन्हें सफलता मिली है। राहुल गांधी ने संविधान और आरक्षण बचाने वाले नैरेटिव के साथ-साथ जातिगत जनगणना को मुद्दा बनाकर दलित, मुस्लिम और ओबीसी समाज के लोगों पर अपनी पकड़ मजबूत की है। इस प्रकार, गठबंधन कर चुनाव लड़ने का लाभ सपा और कांग्रेस दोनों को मिला है। अखिलेश यादव की रणनीति और कांग्रेस की मंशा अभी भी एक साथ चल रही हैं।

कांग्रेस का समर्थन लेकर, अखिलेश यादव 2027 में यूपी की सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं। इसके साथ ही, अखिलेश का लक्ष्य अपनी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार देना है। यूपी में सपा सबसे बड़ी पार्टी है और मुस्लिम वोट उनके पक्ष में लामबंद हैं, लेकिन महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में मुसलमानों का झुकाव कांग्रेस की तरफ है। यूपी में भी मुस्लिम वोट कांग्रेस की तरफ लौट रहा है। इस स्थिति में, कांग्रेस के साथ मिलकर अखिलेश यादव यूपी में बीजेपी से मुकाबला कर सकते हैं और अपनी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर ले जा सकते हैं। यदि सपा और कांग्रेस इसी तरह 2027 के विधानसभा चुनाव में साथ आती हैं, तो बीजेपी के लिए सियासी टेंशन बढ़ना निश्चित है।

आज का इतिहास

1938 एडुआर्डो सैंटोस कोलंबिया के राष्ट्रपति बने।
1940 द्वितीय विश्व युद्ध-इटली ने ब्रिटिश सोमालीलैंड पर अपना आक्रमण शुरू किया।
1948 यूनाइटेडस्टेट्स हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की हाउस अन-अमेरिकन एक्टिविटीज कमेटी से पहले, पूर्व जासूस ने सरकार के मुखबिर बने। चिट्टर्स ने अमेरिकी विदेश विभाग के अधिकारी अल्जीरिया हिस पर कम्युनिस्ट और सोवियत जासूस का आरोप लगाया।
1949 अमेरिका की बास्केटबॉल एसोसिएशन ने नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन बनाने के लिए नेशनल बास्केटबॉल लीग के साथ विलय करने पर सहमति व्यक्त की।
1957 अब्दुल रहमान को मलेशिया का नया नेता चुना गया था जिनके नेतृत्व में मलेशिया ने ब्रिटेन से स्वतंत्रता हासिल की. ब्रिटेन में शिक्षा पाने वाले अब्दुल रहमान वैसे तो राज परिवार से आते थे लेकिन उन्हें हमेशा आम आदमी का नेता कहा जाता था।
1977 संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट की सुनवाई परियोजना एमकेल्ट्रा पर आयोजित की गयी।
1984 अमेरिकी तैराक और ओलंपिक विजेता रियान लोक?टे का हुआ था।
2000 ब्रिटेन की क्वीन मदर द्वारा अपनी 100वीं वर्षगांठ मनायी गई।
2001 ऐनी हैथवे अभिनीत द प्रिंसेस डायरीज पहली फिल्म जारी किया गया।
2003 अमेरीका के एंग्लिकन चर्च ने एक समलैंगिक को बिशप नियुक्त करने का फ़ैसला किया था. न्यू हैंम्पशायर के जेन रॉबिंसन को एपिस्कोपल चर्च के हाउस ऑफ डेपुटीज ने भारी बहुमत से बिशप चुना था।
2004 अमेरिकी अंतरिक्ष यान मैसेंजर बुध ग्रह के लिए रवाना हुआ।
2004 स्टैच्यू ऑफ़ लिबर्टी 11 सितंबर की घटना के बाद पहली बार सार्वजनिक रूप से खुला है।
2005 बीबीसी ने दस्तावेजों पर ठोकर खाई है, जिसमें कहा गया है कि 1958 में ब्रिटिश सरकार ने इजरायल को परमाणु हथियार प्राप्त करने में मदद की थी।
2005 तेहरान के पूर्व मेयर महमूद अहमदीनेजाद ने ईरान के छठे राष्ट्रपति के रूप में अपना कार्यकाल शुरू किया।
2006 श्रीलंकाई सेना और लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम के बीच विवाद उस समय के लिए सबसे बुरी हिंसा है, जब वे 2002 में संघर्ष विराम पर सहमत हुए थे।

कौन 'लिख' रहा है केशव प्रसाद मौर्य के लिये 'स्क्रिप्ट'

संजय सक्सेना

उत्तर प्रदेश की राजनीति भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और अब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आजकल सबके आकर्षण का केन्द्र बने हुए हैं। पिछड़े समाज से आने वाले केशव प्रसाद मौर्य राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के एक पुराने और समर्पित कार्यकर्ता हैं। 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव के समय केशव पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे और बीजेपी की जीत के बाद उनके सीएम बनने की चर्चा काफी जोरों से चली थीं, लेकिन ऐन मौके पर वह सीएम की रेस से बाहर कर दिये गये, जो कारण सामने आये उसमें उनके ऊपर चल रहे आपराधिक मुकदमें अहम थे। मोदी और शाह की जोड़ी नहीं चाहती थी कि केशव प्रसाद को सीएम बनाकर वह विपक्ष को हमलावर होने का मौका दें, इसके बाद बीजेपी आलाकमान की पोटली से अप्रत्याशित रूप से योगी आदित्यनाथ का नाम सामने आया और उन्हें सीएम की कुर्सी पर बैठा दिया गया। उस समय तक योगी की पहचान एक कट्टर हिन्दूवादी नेता की होती थी और हिन्दू वाहिनी नाम से वह एक संगठन भी चलाते थे, जो काफी एग्रेसिव होकर हिन्दुत्व को प्रखरता प्रदान करता था।

केशव प्रसाद मौर्य के नीचे से सीएम की कुर्सी खिसक गई, इसका उनमें गुस्सा था, केशव की इसी गुस्से को शांत करने और पिछड़ा समाज की नाराजगी को दूर करने के लिये बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें समझा बुझा कर डिप्टी सीएम बना दिया। ओहदे के अनुसार उन्हें कुछ प्रमुख विभाग भी दिये गये। इसके साथ-साथ लखनऊ में केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ पड़ोसी भी बन गये। पांच कालीदास मार्ग योगी का पता था तो 7 कालीदास मार्ग में केशव रहते थे। दोनों के आवास के बीच में बस एक बंगला आता था, लेकिन योगी और केशव का एक-दूसरे के घर जाना नहीं होता था, यहां तक की केशव प्रसाद मौर्य के पिता की मौत के बाद योगी ने केशव के आवास पर जाकर संवेदना जताने में भी काफी समय लगा दिया। वह तब संवेदना व्यक्त करने पहुंचे जब आलाकमान ने उन्हें इसके लिये 'मजबूर' किया। यह और बात थी कि इतना सब होने के बाद भी केशव ने कभी अपनी नाराजगी को सार्वजनिक नहीं किया था, लेकिन लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद वे खुलकर सामने आ गए हैं। वह मुख्यमंत्री से दूरी बनाकर चलने लगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकसभा चुनाव के बाद हुई किसी भी कैबिनेट बैठक में केशव शामिल नहीं हुए। चुनाव परिणाम आने के बाद से केशव मुख्यमंत्री की मौजूदगी में होने वाली किसी बैठक में नहीं जा रहे है। वह कैबिनेट बैठकों से भी दूरी बनाए हैं। इसे लेकर तरह-तरह की चर्चाएं हैं। योगी ने जब मंडलवार अपने सांसदों और विधायको से हार के लिय फीड बैक लिया तो 25 जुलाई को प्रयागराज मंडल के सांसदों और विधायकों के साथ हुई बैठक में भी केशव मौजूद नहीं रहे। जबकि वह सीएम आवास के बगल में स्थित अपने सरकारी आवास पर मौजूद थे और कई पूर्व व वर्तमान मंत्रियों से मुलाकात कर रहे थे। उनके बैठक में नहीं पहुंचने पर प्रदेश की सियासत गरमा गई। प्रयागराज मंडल की बैठक में भाजपा के साथ अपना दल (एस) के विधायक भी पहुंचे थे। बैठक में पूर्व मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह, नंद गोपाल गुप्त समेत सभी विधायक थे। मुख्यमंत्री ने सभी विधायकों से विधानसभावार चर्चा की इसी प्रकार केशव

सीएम की बैठक में भले ही नहीं गए, पर पूरे दिन अपने आवास पर जनप्रतिनिधियों से मिलते रहे। केशव से पूर्व मंत्री राजेन्द्र प्रताप सिंह, पूर्व मंत्री उपेन्द्र तिवारी और राज्यमंत्री दिनेश खटीक समेत कई लोगों ने मुलाकात की। इसकी जानकारी खुद केशव ने अपने एक्स हैंडल से देते हुए फोटो भी शेयर किया है। बहरहाल, केशव भले योगी की समीक्षा बैठक में नहीं गये थे, लेकिन अपना दल (कमेरावादी) की नेता और अखिलेश से नाराज चल रहीं सपा विधायक पल्लवी पटेल ने जरूर उसी समय सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर प्रदेश की सियासी मौहाल को गरमा दिया। सूत्रों के मुताबिक पल्लवी सीएम आवास पर करीब 25-30 मिनट रही। सीएम से हुई बात को लेकर पल्लवी कुछ बताने को तैयार नहीं दिखी। हॉ, उनके करीबी सूत्रों का जरूर कहना था कि वह अपने क्षेत्र के विकास के मुद्दे पर मुख्यमंत्री से मिलने गई थीं। बता दें कि पल्लवी ने पिछले विधानसभा चुनाव के केशव प्रसाद को शिकस्त दी थी। वहीं, भाजपा की सहयोगी अपना दल (एस) की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने मुख्यमंत्री को ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर पत्र लिखा था, जिसे लेकर सियासी तूफान उठा था।

एक बात और केशव प्रसाद मौर्य पार्टी के भीतर तो विरोध की चिंगारी भड़काये हुए हैं, लेकिन विपक्ष के हाथ का खिलौना वह नहीं बनना चाहते हैं, इसीलिऐ जैसे ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव नाराज केशव प्रसाद मौर्य को कोई ऑफर देते हैं तो केशव उनको करारा जवाब देकर चुप करा देते हैं। केशव की बातें योगी खेमें को काफी चुभती हैं जब केशव संगठन को सरकार से बड़ा बताते हैं तो इसमें राजनीति के जानकार सियासी रंग तलाशने लगते हैं, अब तक केशव कम से कम दो बार कह चुके हैं कि संगठन सरकार से भी बड़ा है। केशव इस समय किस-किस से मिल रहे हैं, इसको लेकर सभी में जिज्ञासा बनी रहती है। दिल्ली में पार्टी के बड़े नेताओं से उनकी मुलाकात और बातचीत को लेकर भी सुर्खियां बनी रहती है। वहीं केशव से मिलने वालों में भाजपा की सहयोगी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर भी शामिल हैं। मौर्य के एक अन्य ओबीसी नेता, निषाद पार्टी के संजय निषाद से भी मुलाकात की चर्चा गरम है। केशव के राजभर और निषाद से मुलाकात के कई मायने हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद संजय निषाद ने ही पहला बयान दिया था कि बुलडोजर के दुरुपयोग ने हमें हरा दिया। इन्हीं लाइनों पर ओमप्रकाश राजभर ने भी बुलडोजर राजनीति की आलोचना की थी। दोनों ओबीसी नेताओं के बयान साफ तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ है, जो खुद को बुलडोजर बाबा कहलवाना पसंद करते हैं। विपक्ष का आरोप है कि योगी ने ही सबसे पहले बुलडोजर से मुस्लिमों के घर-दुकान आदि गिराने की शुरुआत की थी। ओमप्रकाश राजभर तो अब योगी कैबिनेट में मंत्री भी हैं। लेकिन वो मुखर योगी विरोधी हैं। ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य का योगी के दो कट्टर विरोधियों से मिलने का मतलब आसानी से निकाला जा सकता है।यह मुद्दा इसलिए गंभीर है, क्योंकि एक अन्य ओबीसी नेता और अपना दल (एस) की अनुप्रिया पटेल भी योगी के खिलाफ मुखर नजर आ रही हैं। केशव और अनुप्रिया के सुर भी मिल रहे हैं।

बहरहाल, इस बात की संभावना नहीं है कि केशव पार्टी के खिलाफ बगावत भी कर सकते हैं। डिप्टी सीएम केशव लंबे समय से भाजपा के वफादार हैं। वो एक गैर-राजनीतिक पृष्ठभूमि से आते हैं, जिन्होंने विश्व हिन्दू परिषद में कार्य किया तो अपने दम पर आरएसएस में जगह बनाई। उन्होंने राम मंदिर आंदोलन में भाग लिया, जिसने यूपी में बीजेपी की किस्मत बदल दी। वह यूपी के सिराथू से एक बार के विधायक और एक बार के सांसद हैं। उन्होंने प्रदेश भाजपा में विभिन्न संगठनात्मक पदों पर काम किया है और 2017 में जब भाजपा को सत्ता मिली तो वो प्रदेश भाजपा अध्यक्ष थे।

केशव प्रसाद मौर्य इतने गुस्से में क्यों हैं, यह तो समझ में आता है, लेकिन केशव के गुस्से को आलाकमान शांत क्यों नहीं करा रहा, यह समझ से परे बात है। कहा तो यह भी जाता है कि ओबीसी नेता होने की वजह से भाजपा आलाकमान (मोदी-शाह) केशव की तरफ से मुंह मोड़े हुए है। केशव प्रसाद मौर्य 2022 का विधानसभा चुनाव सिराथू से महज 7337 वोटों से हार गए। मौर्य ने इसके लिए योगी को जिम्मेदार ठहराया। मौर्य ने आलाकमान तक से शिकायत की कि उन्हें अपनी ही सरकार ने हरा दिया। भाजपा आलाकमान ने योगी को संदेश देने के लिए केशव प्रसाद मौर्य को डिप्टी सीएम बनवा दिया। योगी आलाकमान के फैसले से अभी तक नाराज हैं। केशव प्रसाद मौर्य लगातार चुनौतियों पेश कर रहे हैं और पार्टी आलाकमान उन्हें चेतावनी तक नहीं दे रहा है। इससे यूपी की जनता में योगी को लेकर गलत संदेश जा रहा है लेकिन आलाकमान ने मौर्य को कुछ नहीं कहा। पिछले दिनों जब लखनऊ में प्रदेश भाजपा कार्यकारिणी की बैठक हुई तो मौर्य के तेवर सख्त थे। जिसमें उन्होंने वो जुमला कहा था कि संगठन सरकार से बड़ा होता है। बाद में मौर्य ने इस जुमले को एक्स पर पोस्ट भी किया था। मौर्य की गतिविधियां बता रही हैं कि उन्हें भाजपा आलाकमान का संरक्षण मिला हुआ है और पार्टी अब योगी से छुटकारा पाना चाहती है। लेकिन योगी अपनी आखिरी कोशिश जारी रखे हुए हैं। कहा जा रहा है कि 10 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव के बाद योगी को हटा दिया जाएगा। उधर, यूपी बीजेपी का झगड़ा सुलझाने के लिए कोशिशें तो आरएसएस की तरफ से भी हो रही हैं, लेकिन अभी तक उसका कोई असर तो नहीं ही नजर आ रहा है, लेकिन लगता है ये झगड़ा उपचुनावों में ही भारी पड़ने वाला है। लोकसभा चुनाव में बुरी शिकस्त मिलने के बाद बीजेपी के लिए यूपी में ये नई और बड़ी चुनौती है। लब्बोलुआब यह है कि केशव को कहां से योगी के खिलाफ बैकअप मिल रहा है। कहीं आलाकमान ही तो नहीं योगी को हटाने के लिये ही तो केशव के माध्यम से स्क्रिप्ट नहीं लिख रहा है।

रेलवे का खर्च बढ़ा, पर सेवाएं हुईं और खराब

कल्लोल चक्रवर्ती

रेल दुर्घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रहीं। हाल ही में झारखंड के सरायकेला-खरसावां जिले में हावड़ा-मुंबई मेल के 18 डब्बे पटरी से उतर गए, जिससे दो लोगों की मौत हुई और करीब 30 लोग घायल हो गए। जिस लाइन पर हावड़ा-मुंबई मेल बेपटरी हुई, उसके बगल वाली लाइन पर एक मालगाड़ी पहले से ही बेपटरी हुई पड़ी थी! विगत 18 जुलाई को उत्तर प्रदेश के गोंडा में चंडीगढ़-डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस हादसे में चार लोग मारे गए थे, तो 17 जून को पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में कंचनजंघा एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त हुई थी, जिसमें 17 लोग मारे गए थे। इस साल के शुरुआती छह महीनों में सात बड़े रेल हादसे हुए हैं, जिनमें से चार ट्रेनों के बेपटरी होने से हुए। पिछले साल के भी खासकर दो रेल हादसों को भूला नहीं जा सकता। ओडिशा के बालासोर में हुई तीन ट्रेनों की भीषण टक्कर में 290 लोग मारे गए थे और लगभग एक हजार लोग घायल हुए थे। पिछले ही वर्ष मदुरै के पास लखनऊ-रामेश्वरम भारत गौरव ट्रेन में आग लगने से हुआ हादसा तो चरम लापरवाही का नतीजा था। उस ट्रेन के अंदर तीर्थयात्री गैरकानूनी रूप से गैस सिलिंडर ले जा रहे थे। उस पर खाना बनाने के दौरान हादसा हुआ था। रेल दुर्घटनाएं पहले भी होती रही हैं। सच यह है कि दुर्घटनाओं में पहले की तुलना में कमी आई है। पिछली लोकसभा में सरकार ने बताया था कि वर्ष 2014 से 2023 के बीच सालाना औसतन 72 रेल हादसे हुए, जबकि 2004 से 2014 के बीच सालाना औसतन 171 रेल हादसे होते थे। हाल के वर्षों में रेलवे की सुरक्षा और पटरियों के सुधार और मरम्मत पर खर्च बढ़ा है। मानवरहित रेलवे क्रॉसिंग खत्म करने और मालगाड़ियों के लिए अलग से डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाए जाने से तस्वीर बदली है। इसके बावजूद सिग्नलिंग प्रणाली के काम न करने, ट्रेनों की रफ्तार ज्यादा होने और ड्राइवरों के पास समय पर सूचना न पहुंचने के कारण हो रहे रेल हादसे बेहद गंभीर हैं। पहले और आज का एक फर्क यह है कि रेलवे से जुड़ी सूचनाएं और जानकारियां अब सार्वजनिक और पारदर्शी नहीं हैं। अलग से होने वाले रेल बजट को खत्म करने से रेलवे के प्रति आम लोगों की उत्सुकता कम रह गई है। यह ठीक है कि रेल बजट को खत्म कर रेलवे के जरिये की जाने वाली वाली राजनीति पर अंकुश लगाया गया है। अतीत में रेल मंत्रालय के जरिये अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करते एकाधिक रेल मंत्रियों को इस देश ने देखा ही है। लेकिन तब रेल बजट में नई ट्रेनें शुरू की जाती थीं, जिससे रेल डब्बों और इंजनों के निर्माण का काम चलता था, और जो अर्थव्यवस्था को गति देता था। नई ट्रेनें हालांकि अब भी चलाई जाती हैं, लेकिन इस मामले में कोई तय पैटर्न और पारदर्शिता नहीं है। बढ़ते रेल हादसों का एक कारण ट्रेनों की रफ्तार को बताया जा रहा है। ट्रेनों की स्पीड बढ़ाने को रेलवे की प्रगति का पैमाना मान लिया गया, जबकि गति के अनुरूप रेल पटरियों, सिग्नलिंग सिस्टम आदि को तैयार नहीं किया गया। लोको स्टाफ सहित दूसरे कर्मचारियों पर काम का बोझ बढ़ने से भी हादसे हो रहे हैं। रेल सुरक्षा से जुड़े लगभग डेढ़ लाख पद फिलहाल खाली पड़े हैं। रेल पटरियों की जर्जर हालत भी बढ़ते हादसों का कारण है। देश के लगभग सभी रेल रूटों पर पटरियां अपनी क्षमता से ज्यादा बोझ ढो रही हैं। बढ़ती रेल दुर्घटनाओं पर संसद की लोकलेखा समिति ने जो हालिया रिपोर्ट पेश की है, उसमें बताया गया है कि ऑपरेटिंग विभाग की गड़बड़ी, रेलवे के इंजीनियरिंग विभाग द्वारा रेलवे ट्रैक के रख-रखाव में गड़बड़ी और ड्राइवरों की गलतियों के कारण सबसे अधिक रेल दुर्घटनाएं हुई हैं।

संघीय भावना की रक्षा किए जाने की जरूरत

अभिलाष खांडेकर

भारतीय राजनीति की संघीय प्रकृति, जो हमारे संविधान में निहित है, को संविधान निर्माताओं ने प्रशंसनीय दूरदर्शिता और राजनीतिक दृष्टि से आकार दिया था। उन्होंने उन जटिल समस्याओं का बेहतर पूर्वानुमान लगाया था जो तब सामने आएंगी जब अलग-अलग राजनीतिक दल दिल्ली और राज्यों की राजधानियों को चलाएंगे। 75 वर्षों के बाद आज हम देख रहे हैं कि विपक्षी दलों, मुख्यत: गैर-भाजपा शासित राज्यों के साथ केंद्र सरकार द्वारा किए जाने वाले कथित भेदभाव पर संसद में बार-बार चर्चा होती है, आरोप-प्रत्यारोप लगते हैं।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा फिर से यह स्पष्ट किया जाना कि उनके बजट में किसी भी राज्य को धन देने से मना नहीं किया गया है, इसका स्पष्ट उदाहरण है। ताजा विवाद एनडीए के नए राजनीतिक सहयोगियों बिहार और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों को खुले हाथों बजटीय सहायता दिए जाने के बाद शुरू हुआ है। इनके बिना भाजपा लगातार तीसरी बार सरकार नहीं बना पाती। वित्त मंत्री ने न केवल संसद में विपक्ष के सभी आरोपों का खंडन किया बल्कि यह भी कहा कि अतीत में यूपीए के वित्त मंत्रियों ने भी बजट भाषणों में कई राज्यों का नाम नहीं लिया था।

जानकारी के लिए बता दें कि संविधान के लगभग 10 अनुच्छेद केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों के बारे में बताते हैं, जिनकी शुरुआत अनुच्छेद 245 से होती है लेकिन वे मूलत: विधायी दायित्वों के बारे में बात करते हैं। केंद्र सरकार और राज्यों के बीच तनावपूर्ण संबंध निश्चित रूप से मोदी सरकार की देन नहीं है। न्यायमूर्ति आरएस सरकारिया आयोग की नियुक्ति 1983 में इंदिरा गांधी की कांग्रेस सरकार ने इन मुद्दों को सुलझाने हेतु की थी। उसके बाद 2007 में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एम.एम. पुंछी के नेतृत्व में एक और आयोग बनाया गया।

उस समय भी केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और

मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। पुंछी पैनल ने सरकारिया आयोग की सिफारिशों पर फिर से विचार किया। इसने ऐसी कमियों को पाया जिनके लिए केंद्र-राज्य संबंधों को मजबूत करने और प्रशासनिक व विधायी सामंजस्य में सुधार की आवश्यकता थी। भारत को स्वतंत्रता मिलने के तुरंत बाद, अधिकांश राज्य सरकारों पर कांग्रेस पार्टी का शासन था और राज्यों और केंद्र के बीच कोई तनाव नहीं था क्योंकि प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने ऊंचे कद और करिश्माई नेतृत्व के साथ शासन कर रहे थे।

हालांकि, एक दशक के भीतर ही केरल में ईएमएस नंबूदरीपाद के नेतृत्व में पहली गैर-कांग्रेसी सरकार चुनी गई, जिसने भारत में साम्यवाद को आगे बढ़ाया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) के उदय ने भारत के राजनीतिक ताने-बाने को बदल दिया। कांग्रेस ने 1977 में दिल्ली पर अपना राजनीतिक नियंत्रण खो दिया, हालांकि इंदिरा गांधी के नेतृत्व में ही इसने 1980 में फिर से सत्ता हासिल कर ली। इस बीच, कई राज्यों पर गैर-कांग्रेसी गठबंधनों ने कब्जा कर लिया और इस तरह संघीय ढांचे में दरारें पड़ने लगीं, जिससे राजनीतिक तनाव पैदा होने लगा। एक अजीबोगरीब स्थिति तब उत्पन्न हुई जब भाजपा के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यूपीए शासन के विरोध में मध्यप्रदेश के लिए न्याय की मांग करते हुए भोपाल में धरने पर बैठ गए। हालांकि मोदी सरकार पर विपक्ष द्वारा वर्तमान में किए जा रहे हमले बजट में सौतेले व्यवहार के लिए हैं, लेकिन अक्सर ही दिल्ली (आप), बंगाल (तृणमूल), कर्नाटक (कांग्रेस) या केरल (सीपीएम/एलडीएफ) जैसी राज्य सरकारें केंद्र पर करों का हिस्सा जारी न करके या उन्हें 'ठीक' करने के लिए जांच एजेंसियों को भेजकर उनके राज्यों में समस्याएं पैदा करने का आरोप लगाती रही हैं। आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन को भ्रष्टाचार के 'आरोपों' में जेल भेजा गया, लेकिन कहीं अधिक गंभीर मामलों में शामिल भाजपा नेताओं को छुआ तक नहीं गया। इससे जनता में नाराजगी है।

हमारे संघीय ढांचे को कमजोर करने वाला दूसरा कारक गैर-भाजपा सरकारों में राज्यपालों की भूमिका से संबंधित है, जिस पर सरकारिया आयोग ने कई दशक पहले अनुशंसाएं कर दी थीं। राज्यपालों या उपराज्यपालों से पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहीं करने की अपेक्षा की जाती है, लेकिन ऐसे कई उदाहरण हैं जब संवैधानिक कर्तव्यों का निर्वहन करने के बजाय, मौजूदा राज्यपालों ने अपने आकाओं के राजनीतिक रुझान का अनुसरण किया है।

वित्त मंत्री ने अपने जवाब में सही कहा है कि विपक्षी नेता ऐसे मुद्दे उठाकर नकारात्मकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और इससे विदेशों से आने वाले निवेश पर भी विपरीत असर पड़ेगा। उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधा जिन्होंने बजट के बहाने सरकर पर कई आरोप लगाए थे। करदाताओं की कीमत पर यह राजनीतिक झगड़े जारी रहेंगे, लेकिन संघीय ढांचे और संविधान की भावना को हर कीमत पर हमें बचाना होगा। इसकी जिम्मेदारी सीधे संघीय सरकार के संरक्षक की है। संक्षेप में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा को अधिक जिम्मेदारी से काम करना चाहिए, उदार होना चाहिए और दरियादिली दिखानी चाहिए। यह इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ऐसा न होना दोनों तरफ से नुकसानदेह है। आज भाजपा कई राज्यों में भारी बहुमत में है, जिसमें पहली बार ओडिशा भी शामिल है।

कौन होगा भाजपा का नया अध्यक्ष?

अमित शर्मा

देश की सत्ताधारी पार्टी भाजपा का अगला अध्यक्ष कौन होगा, इसे लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। भाजपा के पास कई ऐसे बड़े नेता मौजूद हैं, जिन्हें इस पद की दौड़ में शामिल बताया जा रहा है। इनमें धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव, विनोद तावड़े और केशव प्रसाद मौर्य तक का नाम शामिल है। 28 जुलाई के बाद इस दौड़ में देवेंद्र फडणवीस का नाम भी शामिल हो गया है और कहा जा रहा है कि वे पार्टी के नए अध्यक्ष हो सकते हैं। विशेषकर महाराष्ट्र में यह चर्चा सबसे अधिक हो रही है। उन सभी समीकरणों पर भी विचार किया जा रहा है, जिसके आधार पर नए अध्यक्ष को लाने पर विचार किया जा सकता है। इसमें ओबीसी कार्ड, आगामी चुनाव और भाजपा-आरएसएस के केंद्रीय नेताओं से नजदीकी के आधार पर भी अगले अध्यक्ष के बारे में अनुमान लगाया जा रहा है।

क्या देवेंद्र फडणवीस भाजपा के अगले अध्यक्ष हो सकते हैं, इस प्रश्न पर महाराष्ट्र के एक नेता ने अमर उजाला से कहा कि वे बहुत प्रतिभाशाली और मिलनसार नेता हैं। पार्टी के संगठन से लेकर महाराष्ट्र सरकार में महत्वपूर्ण दायित्व संभाल चुके हैं। पार्टी और संघ के शीर्ष नेताओं से उनके संबंध भी बहुत अच्छे हैं। महाराष्ट्र में सरकार बनाने में भी उनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही है। बिहार के प्रभारी रहते हुए और कई राज्यों में उनका सांगठनिक नेतृत्व कौशल भी दिख चुका है। ऐसे में अध्यक्ष पद के लिए उनकी योग्यता पर कोई संदेह नहीं है।

नेता के अनुसार, लेकिन भाजपा ने उन्हें महाराष्ट्र की राजनीति के लिए विशेष तौर पर आगे बढ़ाया था। आज भी महाराष्ट्र में भाजपा के पास देवेंद्र फडणवीस के अलावा दूसरा कोई बड़ा और लोकप्रिय चेहरा नहीं है, जो पार्टी को आगामी विधानसभा चुनावों में जीत दिला सके। पीयूष गोयल, विनोद तावड़े जैसे नेता भाजपा के पास हैं, लेकिन वे केंद्र की राजनीति में व्यस्त हैं। केंद्र की आवश्यकताओं को देखते हुए उन्हें प्रदेश में भेजने की संभावना भी कम ही

है। ऐसे में देवेंद्र फडणवीस पार्टी के लिए महाराष्ट्र में अधिक उपयोगी साबित हो सकते हैं। आगामी चुनाव को ध्यान में रखकर पार्टी उनका उपयोग महाराष्ट्र में ही कर सकती है।

चूंकि, भाजपा के वर्तमान अध्यक्ष जेपी नड्डा ब्राह्मण समुदाय से हैं, लिहाजा पार्टी लगातार दूसरा अध्यक्ष भी ब्राह्मण समुदाय से ही देने से परहेज कर सकती है। इंडिया गठबंधन ने जिस तरह जातिगत जनगणना, ओबीसी और दलित कार्ड का दांव खेला है, उसे देखते हुए इस बात की अटकलें लगाई जा रही हैं कि भाजपा अगला अध्यक्ष ओबीसी या दलित समुदाय से दे सकती है। यदि ऐसा होता है तो धर्मेंद्र प्रधान या भूपेंद्र यादव पार्टी के खांचे में फिट बैठ सकते हैं। पार्टी के केंद्रीय संगठन में कार्य करने का लंबा अनुभव, केंद्रीय मंत्री के रूप में कार्य करने का अनुभव और केंद्रीय नेताओं से उनकी नजदीकी भी उन्हें इस पद के योग्य बनाती है।

इन समीकरणों में केशव प्रसाद मौर्य भी बिल्कुल फिट बैठते हैं। ओबीसी समुदाय से आने वाले मौर्य उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष के साथ-साथ उत्तर प्रदेश सरकार में उपमुख्यमंत्री के महत्वपूर्ण पद पर भी बने हुए हैं। संगठन में रहने और हिंदुत्व के चेहरे के रुप में भी देखा जाता है। संघ को भी उनके नाम पर कोई आपत्ति नहीं होगी। पार्टी उन्हें केंद्र में भेजकर उत्तर प्रदेश में चल रहे राजनीतिक तनाव का भी पटाक्षेप करने की रणनीति अपना सकती है। हालांकि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में भाजपा के पास ओबीसी समुदाय का सर्वोच्च चेहरा उसके पास पहले से मौजूद है। ऐसे में माना यह भी जा रहा है कि पार्टी एक साथ दोनों सर्वोच्च पदों पर एक ही समुदाय के व्यक्ति को बिठाने से परहेज कर सकती है। ऐसे में इस पद पर किसी दूसरे समुदाय के व्यक्ति को जगह मिल सकती है।

राष्ट्रपति के रूप में आदिवासी द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में ओबीसी समुदाय को सरकार में बड़ा प्रतिनिधित्व मिला हुआ है, ऐसे में अटकलें इसी बात की लगाई जा रही हैं कि पार्टी के अध्यक्ष पद पर किसी दलित चेहरे को उतारने पर भी विचार किया जा सकता है। यह चेहरा कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के सामने मजबूती से पार्टी का पक्ष रख सकता है। विपक्ष ने जिस तरह लोकसभा चुनावों में संविधान और जातिगत जनगणना का विमर्श पैदा किया है और आगे भी वह इसी मुद्दे पर हमलावर होने का रुख दिखा रहा है, पार्टी को दलित चेहरा सूट कर सकता है। ऐसा चेहरा कौन हो सकता है, इस पर भी अटकलें लगाई जा रही हैं। अध्यक्ष पद के लिए अटकलों के बीच यह तय माना जा रहा है कि पार्टी बहुत जल्द नए कार्यकारी अध्यक्ष की घोषणा कर सकती है। इसके बाद पार्टी सदस्यता अभियान चलाएगी और कुछ प्रदेश अध्यक्षों की जिम्मेदारी भी बदली जा सकती है। इसके बाद दिसंबर माह के अंत तक पार्टी को पूर्णकालिक अध्यक्ष मिल सकता है।

दहकता पश्चिम एशिया हिंसा के नए भयावह दौर के मुहाने पर?

शोभना जैन

हमास के शीर्ष नेता इस्माइल हानिये के ईरान की राजधानी तेहरान में एक हमले में मारे जाने और उसके बाद के घटनाक्रम से पश्चिम एशिया में चल रहे घमासान में एक नया भयावह अध्याय शुरू होने की आशंका है। एक ओर हमास के नेता इस्माइल हानिये की मौत हुई, दूसरी तरफ हिज्बुल्लाह के टॉप कमांडर फौद शुकुर की लेबनान में हुए हमले में मौत से संकट और गंभीर हो गया है। पिछले कुछ समय से एक तरफ जहां हमास और इजराइल के बीच संघर्ष विराम की कोशिशें की जा रही थीं वहीं इन हत्याओं से हालात बेहद बिगड़ते नजर आ रहे हैं।

इस बात का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि हानिये के अंतिम संस्कार में न केवल ईरान बल्कि पश्चिम एशिया, ट्यूनीशिया, मलेशिया, मोरक्को सहित सभी देशों में लोग संवेदना प्रगट करने के लिए सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने खुद हानिये के अंतिम समारोह में शामिल होकर साफ संकेत दिया कि ईरान का इस हत्याकांड के बाद इजराइल के खिलाफ और आक्रामक रूप होने वाला है और ईरान ने अब इजराइल के खिलाफ बदला लेने के लिए युद्ध का ऐलान भी कर दिया है। दूसरी तरफ अमेरिका ने भी चेतावनी दी है कि इस संघर्ष को और खूनी बनने से रोका जाए। इस तमाम नए घटनाक्रम के चलते घमासान के और भयावह होने की आशंकाओं के बीच सवाल है कि युद्ध विराम का क्या होगा। हानिये इजराइल के साथ अहम युद्ध विराम वार्ता में हमास की तरफ से मुख्य वार्ताकार थे। साथ ही युद्ध बंदियों की रिहाई वार्ता में भी उनकी अहम भूमिका रही है। युद्ध बंदियों के मामले पर अब कैसे निपटा जाएगा और सबसे अहम बात यह कि क्या यह युद्ध इस समूचे क्षेत्र में फैलेगा? दरअसल हानिये की हत्या सामरिक और प्रतीकात्मक दोनों रूप में ही हमास के लिए बड़ा झटका है। वे विदेशों में रहकर मुख्य तौर पर हमास की राजनीतिक गतिविधियों को संभाल रहे थे। इस क्षेत्र की भारत के लिए खास अहमियत है, इस मामले से जुड़े सभी पक्ष भारत के लिए अहम हैं। भारत इस क्षेत्र में तात्कालिक शांति और स्थिरता का पक्षधर रहा है। लगभग 90 लाख भारतीय वहां काम करते हैं। भारत इस मामले की संवेदनशीलता के मद्देनजर स्थिति पर सतर्कता से नजर रखे हुए है। भारत को अपनी जरूरत का दो तिहाई खनिज तेल इसी क्षेत्र से मिलता है। बहरहाल, दोनों पक्षों की आक्रामकता देखते हुए यह आशंका घनी होती जा रही है कि कहीं यह युद्ध समूचे क्षेत्र में न फैल जाए। इसीलिए दुनिया भर की ताकतें वहां इस भयावह स्थिति को रोकने के लिए प्रयासरत हैं।

मेंटल हेल्थ को बूस्ट करने में मददगार है अरोमाथेरेपी

आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में फिजिकल हेल्थ खराब होने के साथ ही मेंटल हेल्थ पर भी काफी असर पड़ रहा है। हर दूसरा बंदा काम के बोझ के तले इतना दब गया है कि उसे अपने लिए टाइम ही नहीं है। तनाव के कारण एंग्जाइटी और डिप्रेशन जैसी दिक्कत होने लगी है। लोगों की नींद प्रभावित हो रही है, फोकस करने में परेशानी आती है। अगर आप भी इस तरह की परेशानी होती है तो आप मेंटल हेल्थ को बूस्ट करने के लिए अरोमाथेरेपी का सहारा ले सकते हैं।

क्या होती है अरोमाथेरेपी

अरोमाथेरेपी जैसा की इसके नाम से मालूम चल रहा है अरोमा मतलब खुशबू और थेरेपी मतलब इलाज,खुशबू की मदद से इलाज करने को ही हम अरोमाथेरेपी कहते हैं । यह मानसिक तनाव का इलाज करने का सबसे कारगर तरीका है। एसेंशियल ऑयल्स इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं,यह तेल पौधों,जड़ी बूटियों फूलों,पंखुड़ियों जैसी चीजों से निकाले जाते हैं।

मेंटल हेल्थ को कैसे बूस्ट करता है अरोमाथेरेपी

एक्सपर्ट के मुताबिक लैवेंडर कैमोमाइल जैसे एसेंशियल ऑयल्स में शांत करने वाले गुण होते हैं जो तनाव और चिंता को कम करने में मदद करते हैं,इससे बेहतर नींद को बढ़ावा मिलता है और जब आप सुकून भरी नींद सोते हैं तो इससे मस्तिष्क के सेल्स रिपेयर होते हैं । एसेंशियल ऑयल्स की खुशबू लेने से कोर्टिसोल का स्तर कम हो सकता है,जो तनाव के लिए जिम्मेदार हार्मोन होता है,जब आपका कोर्टिसोल हार्मोनकम होता है तो आपको सुकून भरी नींद आती है इससे मेंटल हेल्थ बूस्ट होता है। एसेंशियल ऑयल्स मूड पर पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं,अवसाद की भावनाओं को कम कर देवदार की लकड़ी और चंदन जैसी सुगंध गहरी, अधिक आरामदायक नींद चक्र को बढ़ावा देकर नींद की गुणवत्ता को बढ़ा सकती है। क्लैरी सेज जैसे एसेंशियल ऑयल नींद को नियंत्रित करने वाले हार्मोन को संतुलित करने में मदद कर सकते हैं जिससे नींद का पैटर्न सही हो जाता है। अच्छी खुशबू वाला कमरा एक शांत और आरामदायक वातावरण बनाता है जिससे आराम करना और नींद आना आसान हो जाता है।

किडनी की बीमारी में आपका शरीर आपको देता है ये संकेत

स्किन और नाखूनों से ये दिखाई देता है कि हमारी किडनी में किस तरह की बीमारी होने जा रही है। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि किडनी के लक्षण काफी गंभीर हो सकते हैं।

हमारा शरीर आने वाले हर खतरे का संकेत पहले से ही देने लगता है। शरीर में अगर कोई बड़ी समस्या होने वाली है तो उससे पहले छोटी-छोटी चीजों से हमें कुछ न कुछ संकेत मिलते रहते हैं। शरीर का कोई भी बड़ा ऑर्गेन खराब हो रहा हो तो कई बार हमें स्किन और बालों के जरिए भी उसके संकेत मिलने लगते हैं। ऐसा ही किडनी की बीमारी के साथ भी होता है। किडनी की बीमारी होने से पहले स्किन पर कई तरह के बदलाव देखने को मिलते हैं। यहां सिर्फ बालों का झड़ना या फिर हेयर लाइन शुरू होते ही फ्लेकी स्किन नहीं बल्कि नाखूनों, पैरों, हाथों आदि पर भी असर दिखता है और आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर ऐसे कोई लक्षण दिख रहे हैं तो आपको एक्सपर्ट की सलाह लेनी चाहिए। पर आखिर कौन से संकेत हैं जो साफ दिखाई देते हैं।

किडनी की बीमारी के समय शरीर में होती है ये समस्या

स्किन, बाल और नाखून हमारी सेहत को लेकर बहुत ही जरूरी संकेत देते हैं। कोई भी छुपी हुई बीमारी जैसे मालन्यूट्रीशन, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का ओवरडोज, दवाओं का असर या बीमारी आदि के संकेत इन दोनों से मिल जाते हैं। जिन लोगों को किडनी की बीमारी या किडनी फेलियर का रिस्क होता है उन्हें जिंक, कैल्शियम, आयरन, विटामिन क्र जैसे मिनरल्स दिए जाते हैं। जिन मरीज़ों को डायलेसिस की जररूत होती है उन्हें इन मिनरल्स की कमी के लिए रीनल विटामिन्स दिए जाते हैं जिनमें विटामिन क्र कॉम्प्लेक्स के हाई लेवल होते हैं। कैल्शियम और आयरन को बल्ड लेवल में मॉनिटर किया जाता है और अगर ये लेवल कम होते हैं तो सप्लिमेंट्स उसी हिसाब से दिए जाते हैं।

किडनी की बीमारी के कारण स्किन पर दिखते हैं ये असर

किडनी की बीमारी के कारण शरीर में टॉक्सिन्स काफी बढ़ जाते हैं और इसके कारण स्किन में नाइट्रोजन भी बढ़ जाता है। स्किन बहुत ड्राई, खुजली वाली हो जाती है। इसी के साथ, स्किन में क्रैक्स, स्केल्स आदि बनने लगते हैं। स्किन काफी पतली हो जाती है और बहुत आसानी से स्ट्रेच मार्क्स भी आ जाते हैं जो कच्चे होते हैं और खुजली वाले भी होते हैं। इनमें आसानी से ब्लीडिंग होने लगती है। स्किन ज्यादा सफेद दिखने लगती है और इसका रंग भी ग्रे, ब्लू, पर्पल या येलो शेड का हो जाता है। सिस्ट्स और स्पॉट्स भी दिख सकते हैं।

हाथ और पैरों में आ जाती है बहुत ज्यादा सूजन

हाथों और पैरों में सूजन, चेहरे में सूजन, ऐड़ियों में सूजन आना बहुत ही आम लक्षण है जिसे लेकर आपको तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। शरीर से टॉक्सिन्स ठीक तरह से बाहर न निकल पाने के कारण ये होता है और आपको इस बात का ध्यान भी रखना चाहिए कि ऐसा लक्षण गंभीर समस्या की तरफ इशारा करता है इसलिए डॉक्टर से सलाह लें।

किडनी की बीमारी के कारण नाखूनों पर दिखते हैं ये असर

नाखूनों पर भी किडनी की बीमारी का असर साफ दिखाई देता है। सफेद बैंड्स या स्पॉट्स नाखूनों पर बनने लगते हैं और ये कमजोर, कच्चे और पलेकी हो जाते हैं। अक्सर ऐसे नाखूनों के बीच में लाइन बनने लगती है। हमारे नाखून कई और बीमारियों के संकेत भी देते हैं और ऐसे में हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम ऐसे कोई भी लक्षण के दिखने पर डॉक्टर से बात करनी चाहिए।

स्किन पर दाने और रैशेज

जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि किडनी की बीमारी के कारण शरीर में टॉक्सिन बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाता है और ये रैशेज, बंप्स, ब्लीडिंग वाली स्ट्रेचमार्क्स आदि का कारण बनता है ऐसे में आप शरीर में कई तरह के मिनरल्स आदि का टेस्ट करवा सकते हैं। ये सारे लक्षण किसी अन्य वजह से भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये सिर्फ और सिर्फ किडनी के कारण हों। आपको ये ध्यान रखना होगा कि अगर आपको कोई समस्या हो रही है तो एक्सपर्ट की सलाह लेना ही किसी गंभीर रोग से मुक्ति का अच्छा कारण हो सकता है। अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न दिखाएं और डॉक्टर से सलाह लेते रहें।

थायराइड कैसे करता है हार्ट हेल्थ को प्रभावित

आजकल थायराइड की बीमारी काफी आम हो चुकी है। थायराइड रोग वह स्थिति है जिसमें थायराइड ग्लैंड शरीर की जरूरत से कम या अधिक हार्मोन का निर्माण करने लगता है जिसके कारण कई सारी समस्याएं पैदा होती है। थायराइड के कारण जहां मोटापा हेयर फॉल , जोड़ों में दर्द जैसी समस्या होती है वहीं यह दिल की सेहत को भी बुरी तरह से प्रभावित करता है। इसको लेकर हमने एक्सपर्ट से बात की है। आइए जानते हैं थायराइड कैसे दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ा देता है।

कैसे करता है हार्ट हेल्थ को प्रभावित

एक्सपर्ट बताती हैं की दोनों ही थायराइड हार्ट हेल्थ को प्रभावित करता है। हाइपोथायरायडिज्म की बात करें तो इसमें थायराइड हार्मोन का लेवल शरीर में कम हो जाता है,इससे थायराइड ग्लैंड का फंक्शन कम होने लगता है,इससे मेटाबॉलिज्म खराब हो जाता है,इससे दिल को नुकसान हो सकता है जैसे इससे हार्ट रेट स्लो हो जाता है,इससे आपको ब्रेडीकार्डिया की स्थिति पैदा हो जाती है। इससे कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ सकता है,इसके कारण हृदय का फैलाव हो सकता है। इससे दिल का दौरा पड़ सकता है।थायराइड बढ़ने से हार्ट की धमनियां संकरी होने लगती है,इससे ब्लड का सर्कुलेशन ठीक ढंग से नहीं हो पाता है,लंबे समय तक यह स्थिति बनी रहने पर हार्ट अटैक आने का खतरा बना रहता है। हाइपरथायरायडिज्म में आपका थायराइड ग्लैंड ओवर एक्टिव हो जाता है इससे हाइपर मेटाबॉलिज्म होता है जिससे हार्ट रेट बढ़ सकता है,इससे ट्रैकी कार्डिया की स्थिति पैदा हो सकती है। इस स्थिति में भी हार्ट का फैलाव हो जाता है। ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और इस तरह से हार्ट को नुकसान पहुंचता है।

क्या आपको भी बार-बार बर्फ खाने का मन करता है हो सकता है इस बीमारी का संकेत

क्या आपको भी हर वक्त कच्चा बर्फ चबाने का दिल करता है। अगर हां तो आपको फौरन डॉक्टर से मिलना चाहिए क्योंकि यह एक गंभीर डिसऑर्डर की तरफ इशारा करता है।

गर्मियों के मौसम में हर किसी को कुछ ना कुछ ठंडा खाने का मन करता है। ठंडा पानी तो हर कोई पीता है, लेकिन आइसक्रीम मिल जाए तो सोने पर सुहागा हो जाता है। गर्मी से राहत पाने के लिए कुछ लोग तो घर में रखे आइस क्यूब भी खाते हैं। लेकिन अगर आप बार-बार कच्ची बर्फ चबाते हैं तो इसे इग्नोर ना करें। दरअसल आपकी यह आदत किसी बीमारी की तरफ इशारा करती है। आइए जानते हैं बार-बार बर्फ खाने का मन क्यों करता है।

क्या आपको भी बार-बार बर्फ खाने का मन करता है आपको भी बार-बार बर्फ खाने की क्रेविंग होती है तो शायद आप पिका डिसऑर्डर से पीड़ित हैं। वैसे तो यह बच्चों या गर्भवती महिलाओं में होता है,लेकिन अगर आप में आयरन की कमी हो तो भी आपको इसकी क्रेविंग हो सकती है। एक्सपर्ट बताते हैं कि एनीमिया से पीड़ित लोगों में रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है ऐसे में लोगों को बर्फ खाने की इच्छा बढ़ जाती है। वहीं जो लोग मानसिक तनाव से गुजर रहे होते हैं उन्हें भी बर्फ खाने की क्रेविंग होती है। अगर यह क्रेविंग लंबे समय तक बनी हुई है तो आपको तुरंत डॉक्टर से मिलकर इसका इलाज करवाना चाहिए।

क्या हैं इसके नुकसान

- दांतों में दर्द, बर्फ आपके दांत की इनेमल की परत को डैमेज कर सकती है।
- एनीमिया की गंभीर समस्या,इसके कारण हार्ट हेल्थ को नुकसान पहुंचता है।
- पेट में इंफेक्शन और कब्ज की समस्या

छींक क्यों नहीं रोकनी चाहिए

छींक आना नॉर्मल है। लेकिन, अगर आपको बहुत अधिक छींक आती है, तो इसे नजरअंदाज करें। इसके अलावा, अगर आप छींक आते वक्त इसे रोकती हैं, तो इससे भी सेहत को नुकसान हो सकता है।

हमारा शरीर सेहतमंद रहने के लिए कई नेचुरल प्रोसेस को फॉलो करता है। पेट साफ होना, गैस बाहर निकलना, डकार आना और छींक आना समेत कई ऐसी चीजें हैं, जिनका हमारी सेहत से गहरा कनेक्शन है। कई बार, नाक के अंदर डस्ट और पाउडर जैसे पार्टिकल्स चले जाते हैं। इन्हें बाहर निकालने के लिए, छींक आती है। वहीं, सर्दी-जुकाम होने पर भी छींक आती है। हालांकि, अगर आपको अक्सर बहुत अधिक छींक आती हैं, तो इसके पीछे कुछ हेल्थ कंडीशन्स हो सकती हैं। आमतौर पर छींक आना काफी नॉर्मल होता है। कई लोग, छींक आने पर इसे रोक लेते हैं। लेकिन, सेहत के लिहाज से ऐसा करना गलत है। एक्सपर्ट के मुताबिक, अगर आप छींक रोकती हैं, तो इससे स्वास्थ्य से जुड़ी कई समस्याएं हो सकती हैं। इस बारे में डॉक्टर नीतिका कोहली जानकारी दे रही हैं। वह आयुर्वेद में एमडी हैं। उन्हें इस फील्ड मे लगभग 17 सालों का अनुभव है।

छींक रोकने से सेहत को हो सकता है नुकसान

- दरअसल, हमारी नाक में एक म्यूकस नाम की झिल्ली होती है। इसके टिश्यू या सेल्स पर जब कोई डस्ट पार्टिकल आकर चिपकता है, तो इसे बाहर निकालने के लिए छींक आती है।
- आयुर्वेद में छींक को श्वतु कहा जाता है। इसे अधारणीय वेग कहा जाता है। इसकी गिनती उन वेगों में होती हैं, जिन्हें रोका नहीं जा सकता है और रोकना भी नहीं चाहिए।
- छींक के जरिए, बैक्टीरिया और वायरस नाक से बाहर निकल जाते हैं। इसलिए, यह फायदेमंद होती है।
- छींक रोकना सेहत के लिहाज से सही नहीं है। इससे गर्दन अकड़ सकती है और साइनस की दिक्कत भी हो सकती है।
- अगर आप छींक आने पर इसे रोकने की कोशिश करते हैं, तो इससे फेस की नर्व्स और मसल्स कमजोर हो सकती हैं।
- यह शरीर की सफाई का एक नेचुरल प्रोसेस है। इसलिए, इसे होल्ड नहीं करना चाहिए।
- एक्सपर्ट के मुताबिक, कई बार सोशल एटिकेट्स या अन्य कई वजहों से लोग छींक को रोक लेते हैं। लेकिन, छींक रोकने से फेफड़ों पर दबाव पड़ता है। इससे श्वसन तंत्र पर बुरा असर हो सकता है।
- छींक के जरिए, बाहर निकलने वाली हवा का प्रेशर काफी तेज होता है। इसे रोकने से, आंख, नाक और कान के ब्लड वेसल्स पर असर पड़ सकता है।
- छींक आने पर उसे रोकने की कोशिश न करें। एक्सपर्ट की सलाह पर जरूर ध्यान दें। अगर आपको स्वास्थ्य से जुड़ी कोई समस्या है, तो हमें आर्टिकल के ऊपर दिए गए कमेंट बॉक्स में बताएं। हम अपने आर्टिकल्स के जरिए आपकी समस्या को हल करने की कोशिश करेंगे।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

खरगे ने की केंद्र से अतिरिक्त आपदा प्रबंधन निधि देने की मांग

नई दिल्ली। देश के विभिन्न क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदाओं के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार से एक मांग की। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार को बिना किसी भेदभाव के राज्यों को तुरंत अतिरिक्त आपदा प्रबंधन निधि प्रदान करनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए ठोस नीति बनाने की भी अपील की। उन्होंने यह टिप्पणी उत्तराखंड में बादल फटने और भारी बारिश से हुई नुकसान पर शोक व्यक्त करने के बाद की। खरगे ने इसे लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हिंदी में पोस्ट किया। उन्होंने कहा, उत्तराखंड में बादल फटने, बेहद भारी वर्षा व भूस्खलन से कई लोगों की मृत्यु का समाचार बेहद दु:खद है। जानकारी के मुताबिक, बहुत सारे लोग लापता हैं। इस मुश्किल घड़ी में हम उत्तराखंड के लोगों के साथ हैं।

ईडी ने टीएमसी नेता को राशन घोटाले में गिरफ्तार किया

कोलकाता। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के देगंगा से तृणमूल कांग्रेस के एक नेता को करोड़ों रुपये के राशन वितरण घोटाले से कथित संबंधों को लेकर गिरफ्तार किया है। एक अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि केंद्रीय जांच एजेंसी ने तृणमूल कांग्रेस के डेगंगा ब्लॉक के अध्यक्ष अनीसुर रहमान और उनके बड़े भाई को उनके कोलकाता कार्यालय में करीब 14 घंटे पूछताछ करने के बाद गुरुवार देर रात गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने कहा, रहमान और उनके भाई को राशन वितरण घोटाले के संबंध में गिरफ्तार किया गया है। हम चिकित्सकीय जांच के बाद उन्हें शहर की अदालत में पेश करेंगे। रहमान राज्य के पूर्व वन मंत्री ज्योतिप्रियो मलिक के बहुत करीबी माने जाते हैं, जिन्हें घोटाले के सिलसिले में केंद्रीय जांच एजेंसी ने गिरफ्तार किया है। अधिकारी ने बताया कि ईडी अधिकारियों ने चावल मिल मालिक और पूर्व मंत्री के एक अन्य करीबी सहयोगी बारिक बिस्वास को पूछताछ के लिए शहर के अपने कार्यालय में पेश होने के लिए समन जारी किया है।

आरक्षण पर सुको का फैसला मायावती ने उठाए सवाल

लखनऊ। बसपा सुप्रीमो मायावती ने आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के दिए गए फैसले पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि क्या दलितों व आदिवासियों का जीवन द्वेष व भेदभाव-मुक्त हो गया है? ऐसे में आरक्षण का बंटवारा कितना उचित है? उन्होंने भाजपा-कांग्रेस को भी निशाने पर लिया और कहा कि एससी-एसटी व ओबीसी लेकर दोनों दलों का रवैया उदारवादी रहा है सुधारवादी नहीं। उन्होंने सोशल साइट एक्स पर कहा कि सामाजिक उत्पीड़न की तुलना में राजनीतिक उत्पीड़न कुछ भी नहीं। क्या देश के खासकर करोड़ों दलितों व आदिवासियों का जीवन द्वेष व भेदभाव-मुक्त आत्म-सम्मान व स्वाभिमान पूर्ण का हो पाया है। अगर नहीं तो फिर जाति के आधार पर तोड़े व पछाड़े गए इन वर्गों के बीच आरक्षण का बंटवारा कितना उचित? देश के एससी, एसटी व ओबीसी बहुजनों के प्रति कांग्रेस व भाजपा दोनों ही पार्टियों और सरकारों का रवैया उदारवादी रहा है सुधारवादी नहीं।

मुदा घोटाले में राजभवन के नोटिस पर भड़के सिद्धारमैया

बेंगलुरु। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शुक्रवार को कारण बताओ नोटिस जारी करने के लिए राज्यपाल थावरचंद गहलोत की आलोचना की और उन पर केंद्र सरकार और भाजपा-जद (एस) द्वारा हेरफेर करने का आरोप लगाया। यह नोटिस मैसूरु शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए) साइट वितरण में कथित अनियमितताओं से संबंधित है। बेंगलुरु में पत्रकारों को संबोधित करते हुए सिद्धारमैया ने मुदा घोटाले में किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार किया। इसके साथ ही उन्होंन कहा कि मेरी भूमिका वहां नहीं है। मेरी भूमिका कहां है? सिद्धारमैया ने बताया कि निर्णय लेने के बाद मंत्री परिषद द्वारा राज्यपाल को मुझे दिए गए कारण बताओ नोटिस को वापस लेने और टीजे अब्राहम द्वारा दायर शिकायत को खारिज करने की सलाह देने के बाद विवरण पहले ही दिया जा चुका है। उन्होंने आगे केंद्र सरकार पर राजभवन का दुरुपयोग करने और लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को अस्थिर करने का प्रयास करने का आरोप लगाया।

दिल्ली सरकार पर स्वाति मालीवाल ने साधा निशाना

नईदिल्ली। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने शुक्रवार को दिल्ली सरकार द्वारा संचालित मानसिक स्वास्थ्य सुविधा आशा किरण आश्रय गृह में हाल ही में हुई मौतों के संबंध में कार्रवाई की कथित कमी के लिए दिल्ली सरकार को फटकार लगाई। कथित तौर पर कैदियों की मौत स्वास्थ्य समस्याओं और कुपोषण के कारण हुई। मालीवाल ने कहा कि पिछले 20 दिनों में दिल्ली सरकार द्वारा संचालित आशा किरण आश्रय गृह में 13 मौतें हुई हैं। कारण अभी तक ज्ञात नहीं हैं। जब मैं डीसीडब्ल्यू में थी, तो मैंने यहां की स्थिति का निरीक्षण किया था। यहां स्थिति बहुत खराब है क्योंकि यहां न तो उचित स्टाफ है और न ही उचित डॉक्टर हैं। मालीवाल ने यह भी आरोप लगाया कि उन्होंने पहले एक रिपोर्ट दायर की थी जो दिल्ली सरकार को सौंपी गई थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।

विपक्ष के नेता का एक और दावा, कहा-

ईडी जल्दी करने वाली है मेरे घर रेड: राहुल

नईदिल्ली। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बड़ा बयान दे दिया है। शुक्रवार को उन्होंने एक बड़ा दावा करते हुए कहा कि उनके घर पर जल्द ही प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की रेड होने वाली है।

गौरतलब है कि 29 जुलाई को ही राहुल गांधी ने संसद में चक्रव्यूह को लेकर एक भाषण दिया था। इस भाषण के बाद उन्होंने दावा किया है कि प्रवर्तन निदेशालय की टीम उनके घर पर रेड करने की तैयारी में जुट गई है। उन्होंने कहा कि मैं अपने घर पर ईडी के कर्मचारियों और अधिकारियों का इंतजार कर रहा हूं। उन्होंने बताया कि ईडी के सूत्रों ने उन्हें ये जानकारी दी है। इस संबंध में राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर भी पोस्ट शेयर किया है। इस पोस्ट में राहुल गांधी ने लिखा कि जाहिर है, 2 में से 1 को मेरा चक्रव्यूह वाला भाषण अच्छा नहीं लगा। ईडी के अंदरूनी सूत्रों ने मुझे बताया है कि छापेमारी की तैयारी हो रही है। मैं ईडी का खुली बांहों से इंतजार कर रहा हूं। चाय और बिस्कुट मैं खिलाऊंगा। इस पोस्ट में राहुल गांधी ने प्रवर्तन निदेशालय के आधिकारिक ट्विटर हैंडल को भी टैग किया है।

राहुल के बयान पर आया उद्धव सेना का रिएक्शन

राहुल गांधी के इस दावे पर उनके साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) उन पर छापा मारने की योजना बना रही है, शिवसेना (यूबीटी) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने शुक्रवार को कहा कि अगर एजेंसी दरवाजे खटखटाती है तो विपक्षी भारत गुट के सभी साथी कड़ा विरोध करेंगे। चतुर्वेदी ने कहा कि सत्तारूढ़ भाजपा ने हाल के लोकसभा चुनाव परिणामों से कोई सबक नहीं सीखा है और चेतावनी दी है कि लोग केंद्रीय एजेंसियों की गतिविधियों पर करीब से नजर रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोग देख रहे हैं कि कैसे विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने के लिए सभी एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। आज, हमारी सभी केंद्रीय एजेंसियां केंद्र सरकार के सामने झुक गई हैं। एलओपी होने के नाते, राहुल गांधी लोगों से संबंधित मुद्दे उठा रहे हैं। अगर ईडी राहुल गांधी के दरवाजे पर दस्तक देती है तो भारतीय गठबंधन के सभी साथी इसका कड़ा विरोध करेंगे। उनकी टिप्पणी राहुल गांधी के उस दावे के मद्देनजर आई है कि केंद्रीय बजट पर चर्चा के दौरान उनके आलोचनात्मक चक्रव्यूह भाषण के बाद ईडी उन पर छापेमारी की योजना बना रही थी।

राहुल गांधी के दावे पर भाजपा का पलटवार

विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शुक्रवार को दावा किया कि 29 जुलाई को संसद में उनके चक्रव्यूह भाषण के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) उन पर छापेमारी की योजना बना रहा था। हालांकि, राहुल के दावों के बाद भाजपा की ओर से पलटवार किया जा रहा है। भाजपा ने राहुल के दावों को फेक बताया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि मेरा मानना है कि यह देश का दुर्भाग्य है कि राहुल गांधी एलओपी हैं। संसद के अंदर झूठ बोलने के साथ-साथ वह बाहर भी दुष्प्रचार कर रहे हैं। उन्हें शर्म आती है, वह पूरी दुनिया की जाति पूछते हैं। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने कहा कि वह (राहुल गांधी) इन दिनों बेचैन हैं, उन्होंने बहुत झूठ बोला है, इतनी अफवाहें फैलाई हैं, इसलिए वह बेचैन हैं। उन्होंने कहा कि 3-4 दिन तक वो वायनाड नहीं पहुंच पाए, अब जब वो वहां पहुंच गए हैं तो उनका बेचैन होना स्वाभाविक है। वो पापी हैं इसलिए जो मन में आता है ट्वीट कर देते हैं। जनता उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेती।

किसान विरोधी होना कांग्रेस के डीएनए में है: शिवराज

नई दिल्ली। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पार्टी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि किसान विरोधी होना कांग्रेस के डीएनए में है। विपक्षी पार्टियों द्वारा केंद्र की मोदी सरकार पर कृषि क्षेत्र के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया जा रहा है। विपक्ष के आरोपों के जवाब में केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस पार्टी को ही किसान विरोधी कह दिया।

शुक्रवार को राज्यसभा में चर्चा के दौरान शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार ने बीते 10 वर्षों में कृषि क्षेत्र के बजट में अच्छी खासी बढ़ोतरी की है।

किसानों को सब्सिडी पर फर्टिलाइजर्स मिल रहे हैं और आगे भी मिलते रहेंगे। कृषि मंत्री ने कहा कि किसान विरोधी होना कांग्रेस के डीएनए में है। कांग्रेस की प्राथमिकताएं शुरुआत से ही गड़बड़ रही हैं। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र की मौजूदा सरकार ने कृषि क्षेत्र के लिए कुछ प्राथमिकताएं तय की हैं, जिनमें फसल उत्पादन को बढ़ाना, कृषि लागत को कम करना, किसानों को फसल की अच्छी कीमत देना और प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में किसानों को पर्याप्त राहत देना शामिल है।

विपक्ष ने सरकार पर किसानों के लिए कुछ न करने का आरोप लगाया

मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि केंद्र सरकार विपक्ष के अच्छे सुझावों का स्वागत करेगी। चौहान ने कहा कि उनकी सरकार किसानों को भगवान मानती है न कि वोटबैंक।

उन्होंने विपक्ष के उन आरोपों को खारिज कर दिया, जिनमें किसानों को पर्याप्त एमएसपी न देने का आरोप लगाया गया।

राज्यसभा में चर्चा के दौरान विपक्षी पार्टियों ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने कृषि क्षेत्र और किसानों के लिए बीते 10 वर्षों में कुछ नहीं किया है और हालिया बजट भी उम्मीदों के अनुरूप नहीं है।

दो दिवसीय राज्यपाल सम्मेलन का राष्ट्रपति मुर्मू ने किया उद्घाटन

नईदिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में राज्यपालों के दो दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन में अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में, राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि सम्मेलन के एजेंडे में सावधानीपूर्वक चुने गए मुद्दे शामिल हैं जो हमारे राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि सम्मेलन का विचार-विमर्श सभी प्रतिभागियों के लिए एक समृद्ध अनुभव होगा और उन्हें अपने कामकाज में मदद मिलेगी।

सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी संबोधित किया, जिन्होंने राज्यपालों की शपथ का उल्लेख किया और उनसे लोगों को सामाजिक कल्याण योजनाओं और पिछले दशक के दौरान हुए विकास के बारे में जागरूक करने की अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करने का आग्रह किया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यपालों से केंद्र और राज्य के बीच एक प्रभावी पुल की भूमिका निभाने और वंचित लोगों को सहयोजित करने के लिए लोगों और

सामाजिक संगठनों के साथ बातचीत करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि राज्यपाल का पद एक महत्वपूर्ण संस्था है जो संविधान के दायरे में राज्य के लोगों के कल्याण में, विशेषकर आदिवासी क्षेत्रों के संदर्भ में, महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।सम्मेलन में अमित शाह ने राज्यपालों से लोगों में विश्वास पैदा करने के लिए गांवों और जिलों का दौरा करने का आग्रह किया। सम्मेलन की शुरुआत करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि आपराधिक न्याय से संबंधित तीन नए कानूनों के लागू होने से देश में न्याय प्रणाली का एक नया युग शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि हमारी सोच में बदलाव कानूनों के नामों से स्पष्ट है-भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम।

महाभारत सुनाने का किस्सा चल रहा है ज्यादा : ओम बिरला

नईदिल्ली। लोकसभा की कार्यवाही का शुक्रवार को 10वां दिन है. विपक्ष सदन में मोदी सरकार पर ज्यादा हमलावर नजर आ रहा है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सदन में चक्रव्यूह वाला भाषण दिया जिसपर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने तंज कसा है, हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। बिरला ने सदन में किसी का नाम लिए बगैर तंज कसते हुए कहा कि आजकल यहां महाभारत सुनाने का किस्सा ज्यादा चलता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने की ओर से यह टिप्पणी उस वक्त की गई जब सदन में प्रश्नकाल के दौरान बीजेपी के सांसद प्रदीप पुरोहित ने आयुष मंत्रालय से संबंधित प्रश्न पूछने के दौरान रामायण के एक प्रसंग का उल्लेख किया। इस पर बिरला ने कहा कि आप महाभारत मत सुनाइए, प्रश्न पूछिए। आजकल महाभारत सुनाने का किस्सा ज्यादा चलता है यहां पर। लोकसभा अध्यक्ष ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन गत सोमवार को सदन में बजट पर चर्चा में भाग लेते हुए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इसी तरह के वाकया का जिक्र किया था। उन्होंने अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाए जाने संबंधी महाभारत के प्रसंग का उल्लेख करते हुए केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा था। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हिंदुस्तान को अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में फंसाने का आरोप लगाया था, साथ ही कहा था कि विपक्षी गठबंधन 'इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस' (इंडिया) इस चक्रव्यूह को तोड़ देगा।

खेल
प्रमुख समाचार

मनु भाकर ने 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा के फाइनल में

पेरिस। मनु भाकर महिलाओं की 25 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा जीतकर इस ओलंपिक में पदक की हैट्रिक लगाना चाहेंगी। वह फाइनल में पहुंच गई हैं। आज क्वालिफिकेशन राउंड में दूसरे स्थान पर रहीं।

भारत की स्टार शूटर मनु भाकर ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। वह क्वालिफिकेशन राउंड में दूसरे स्थान पर रहीं। उन्होंने प्रिसीजन राउंड में 294 और रैपिड राउंड में 296 का स्कोर बनाया। कुल स्कोर मनु का 590 का रहा और उन्होंने 24 एक्स लगाए। पहले स्थान पर हंगरी की मेजर वेरोनिका रहीं। उन्होंने प्रिसीजन राउंड में 294 और रैपिड राउंड में 298 का स्कोर बनाया। वेरोनिका का कुल स्कोर 592 का रहा और उन्होंने 27 एक्स यानी परफेक्ट 10 लगाए। मनु ने अपने लगातार तीसरे इवेंट के फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। इससे पहले वह महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा और सरबजोत सिंह के साथ 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा के फाइनल में पहुंची थीं। दोनों में उन्होंने कांस्य पदक जीता था। मनु के पास पदकों की हैट्रिक लगाने का मौका है। वह एक ओलंपिक में दो पदक जीतने वाली पहली भारतीय भी हैं। मनु कल यानी शनिवार को 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा का फाइनल खेलेंगी। मनु प्रिसीजन राउंड के बाद तीसरे स्थान पर थीं। वहीं, इसी स्पर्धा में भारत की एक और शूटर ईशा सिंह 581 के स्कोर के साथ 18वें स्थान पर रहीं। उन्होंने प्रिसीजन राउंड में 291 का स्कोर बनाया, जबकि रैपिड राउंड में ईशा का स्कोर 290 रहा। मनु का फाइनल मुकाबला शनिवार को दोपहर एक बजे से खेला जाएगा। ईशा का रैपिड राउंड खत्म हो चुका है। उन्होंने इस राउंड की तीन सीरीज में 290 का स्कोर किया। पहली सीरीज में ईशा ने 97, दूसरी सीरीज में 96 और तीसरी सीरज में 97 का स्कोर बनाया। वह फिलहाल 15वें स्थान पर चल रही हैं। अब मनु भाकर रैपिड राउंड में उतरेंगी।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

सेंसेक्स 886 अंक गिरा निफ्टी 24,800 से नीचे

नईदिल्ली। शेयर बाजार में आज जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। 30 शेयरों वाले सेंसेक्स और निफ्टी लगातार पांच दिनों की तेजी के बाद आज धड़ाम हो गए। कमजोर अमेरिकी जॉब डेटा आने के बाद विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने जबरदस्त बिकवाली की और उसका असर मेटल, ऑटो और आईटी जैसे सेक्टर के स्टॉक्स में देखने को मिला। विदेशी निवेशकों की इस जबरदस्त बिकवाली के बीच, सेंसेक्स 885.60 अंक यानी 1.08 फीसदी गिरकर 80,981.95 के लेवल पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान, सेंसेक्स 998.64 अंक या 1.21 फीसदी की गिरावट के साथ इंट्रा-डे के निचले स्तर 80,868.91 पर पहुंच गया था। वहीं, अगर एनएसई के 50 शेयरों वाले निफ्टी-50 की बात की जाए तो यह 293.20 अंक यानी 1.17 फीसदी लुढ़ककर 24,717.70 के लेवल पर बंद हुआ।

एयर इंडिया ने इस्राइल के लिए उड़ान सेवाएं बर्खास्त की

नई दिल्ली। हमास के शीर्ष नेता इस्माइल हानिया की ईरान में हत्या के बाद से पश्चिम एशिया में तनाव चरम पर है। ईरान ने हानिया की मौत का बदला लेने के लिए इस्राइल पर हमले की धमकी दी है। इस्राइल हाई अलर्ट पर है। ऐसे हालात को देखते हुए भारतीय एयरलाइंस कंपनी एयर इंडिया ने भारत और इस्राइल की राजधानी तेल अवीव के बीच संचालित होने वाली उड़ान सेवाओं को बर्खास्त करने का फैसला किया है। एयर इंडिया ने एक बयान जारी कर बताया कि पश्चिम एशिया के हालात को देखते हुए हमने तेल अवीव के लिए प्रस्तावित संचालन को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त करने का फैसला किया है। तेल अवीव से यहां आने वाली और यहां से तेल अवीव जाने वाली विमानन सेवाएं फिलहाल 8 अगस्त 2024 तक बर्खास्त की गई हैं। हम लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं।

दस्तावेज जमा करने के बाद जल्द मंजूर होंगे कंपनियों के आईपीओ

नईदिल्ली। सेबी की चेयरपर्सन माधबी पुरी बुच ने शुक्रवार को कहा कि कैपिटल मार्केट रेगुलेटर 'आईपीओ मंजूरी' में तेजी लाने के लिए एक तंत्र पर काम कर रहा है। बुच ने फिक्की के 'कैपम' कार्यक्रम में कहा कि इसके अलावा सेबी तेजी से मंजूरी के लिए कंपनियों द्वारा दाखिल किए जा रहे आईपीओ दस्तावेजों की जांच के लिए एक आर्टिफिशल इंटेलिजेंस टूल तैयार कर रहा है। यह टूल दिसंबर तक उपलब्ध हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आईपीओ प्रक्रिया के इर्द-गिर्द एक जटिलता कायम है जैसे कि एक जटिल 'ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस' दाखिल करना। अब इस प्रक्रिया को इससे मुक्त करने का प्रयास किया जा रहा है। विस्तार से बताते हुए बुच ने कहा कि सेबी एक ऐसी प्रक्रिया पर काम कर रहा है, जिसमें एक 'टेम्पलेट' होगा, जहां कंपनियां आईपीओ दस्तावेज तैयार करने के लिए रिक्त स्थान भर सकेंगी।

अडानी सुपर ऐप अब देगा डिजिटल लोन

नईदिल्ली। अडानी समूह द्वारा विकसित 'सुपर ऐप' अडानी वन ने प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऋण प्रदान करने की शुरुआत की है। इस संबंध में डिजिटल ऋण देने वाली फर्मों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के साथ पायलट प्रोजेक्ट शुरू की है। अदानी वन का संचालन अदानी एंटरप्राइज लिमिटेड की डिजिटल शाखा अदानी डिजिटल लैब्स लिमिटेड के तहत किया जाता है। मनीकंट्रोल की एक रिपोर्ट के अनुसार, इसने व्यक्तिगत ऋण देने के लिए फिनटेक कंपनी क्रेडिटबी की एनबीएफसी सहायक कंपनी क्रेजीबी सर्विसेज के साथ साझेदारी की है। अडानी का सुपर ऐप पहले यात्रा और हवाईअड्डा सेवाओं पर केंद्रित था। सूत्रों का हवाला देते हुए रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अडानी वन अपने क्रेडिट उत्पाद पेशकश का विस्तार करने के लिए अन्य एनबीएफसी और फिनटेक कंपनियों के साथ भी चर्चा कर रही है।

जीत की जिद ने मनु को सफलता के मुकाम तक पहुंचाया

मनोज चतुर्वेदी

देश में इस समय कोई सबसे चर्चित नाम है, तो वह महिला निशानेबाज मनु भाकर का है। वे स्वतंत्र भारत की पहली खिलाड़ी हैं, जिन्होंने एक ही ओलिंपिक में दो पदक जीतने का गौरव हासिल किया है। मनु ने पहले महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक पर निशाना साधा और फिर सरबजोत के साथ इसकी मिक्स स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। निशानेबाजी ऐसा खेल है, जिसमें पिछले दो ओलिंपिक खेलों- 2016 में रियो और 2021 में टोक्यो- से भारत खाली हाथ लौटा था। पर इस बार शुरू में ही आये दो पदकों ने भारतीय निशानेबाजी ही नहीं, बल्कि पूरे भारतीय दल का मनोबल बढ़ा दिया है।

किसी भी खिलाड़ी की सफलता में उसकी मेहनत और कौशल का तो अहम योगदान होता ही है, साथ ही उसके अभियान में कई लोगों की भूमिका होती है। मनु भाकर जब टोक्यो ओलिंपिक से निराश होकर लौटी थीं, तब वे इस खेल को छोड़ने के बारे में सोचने लगी थीं। इस स्थिति में घर वालों, खासतौर पर मां सुमेधा ने उन्हें हताशा से बाहर निकालने में जो भूमिका निभायी, उसका दो पदक जीतने में कम योगदान नहीं है। मां बताती हैं कि हम लोग मनु के घर आने पर कभी उससे शूटिंग की बात कर उसे तनाव में नहीं लाना चाहते हैं। हम घर में हल्का-फुल्का माहौल रखकर कोशिश करते हैं कि वह खुश रहे। इसी तरह भाई लगातार गिफ्ट लाता रहा, ताकि बहन का मूड अच्छा बना रहे।

टोक्यो ओलिंपिक में पिस्टल खराब हो जाने पर मनु भाकर पदक तो दूर, फाइनल तक भी नहीं पहुंच सकी थीं। यही नहीं, टोक्यो की हताशा ने उनके साथ 2014 से जुड़े कोच जसपाल राणा तक से संबंध खराब बना दिये थे। दोनों एक-दूसरे के सामने आने से तो बचते ही थे और कहीं आमना-सामना हो जाए, तो एक-दूसरे की अनदेखी कर देते थे। हमारे देश में गुरु-शिष्य परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है और मनु की मौजूदा सफलता में इस परंपरा का भी प्रमुख हाथ है। टोक्यो ओलिंपिक के बाद मनु भाकर ने कोच जसपाल राणा से संबंध विच्छेद कर लिये थे।

मनु ने दोबारा शूटिंग रेंज में लौटने पर अलग कोच के साथ अभ्यास शुरू किया, पर अपेक्षित परिणाम नहीं निकलने पर उन्होंने कुल चार कोचों के साथ काम किया। उनकी समझ में जल्दी ही आ गया कि जसपाल राणा के कोच रहते ही वे अपना सर्वश्रेष्ठ दे पाती हैं। इस पर उन्होंने जसपाल राणा से संपर्क करने की बात की, पर उनके करीबियों ने ऐसा नहीं करने को कहा। मनु जानती थीं कि कोच जसपाल की उनके लिए क्या अहमियत है और उन्होंने इन खेलों से करीब सालभर पहले जसपाल को फोन कर दिया और वे मनु को फिर से कोचिंग देने को राजी हो गये। सही मायनों में जसपाल ने यदि गुरु के दायित्व को नहीं निभाया होता, तो शायद यह परिणाम देखने को नहीं मिलता।

जसपाल राणा कहते हैं कि मनु के लिए शूटिंग सबसे पहले है और वे अजेय योद्धा की तरह हैं। टोक्यो की हताशा के बाद दोबारा शूटिंग रेंज में लौटने के बाद पदक जीतने वाला प्रदर्शन नहीं कर पाने पर भी उन्होंने आत्मविश्वास को डगमगाने नहीं दिया। वे कहते हैं कि मनु की जीत की जिद ने ही उसे यहां तक पहुंचाया है। मनु की मेहनत का यह परिणाम है। जब तक परफेक्ट शॉट नहीं मिल जाता था, तब तक वे शूटिंग रेंज में अभ्यास करती रहती थीं, भले ही कितनी भी देर हो जाए। हम भारतीय ओलिंपिक इतिहास की बात करें, तो लंबे समय तक हॉकी की सफलता के अलावा हमारे खाते में कुछ भी नहीं था। सही मायनों में अभिनव बिंद्रा ने 2008 की बीजिंग ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतकर भारतीयों में यह भरोसा बनाया कि वे भी जीत सकते हैं। इसके बाद सुशील पहलवान ने लगातार दो ओलिंपिक में पदक जीतकर दिखाया कि ऐसा किया जाना भी संभव है। सुशील वाले प्रदर्शन को बाद में पीवी सिंधु ने लगातार दो बार पदक जीतकर दोहराया। अब मनु भाकर ने देशवासियों को सिखाया है कि एक ही ओलिंपिक में दो पदक भी जीते जा सकते हैं। मनु की इन सफलताओं ने भारतीय दल को बेहतर प्रदर्शन की प्रेरणा दी है।

वृक्षारोपण की शर्त का पूरी तरह से पालन कराएं : ओपी चौधरी

रायपुर। आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने आज यहां अटल नगर नवा रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के कार्यालय में राज्य के सभी क्षेत्रीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। उन्होनें अधिकारियों से कहा स्व-प्रेरित होकर पर्यावरण संरक्षण से जुडे कार्यों में अपना योगदान दे। उनके द्वारा कार्यों में पारदर्शिता एवं तत्परता हेतु प्रदेश एवं जिला स्तरीय कार्यालयों में बायोमैट्रिक उपस्थिति, सी.सी.टी.वी. कैमरा लगाने एवं डैश बोर्ड तैयार करने के निर्देश दिये गये ताकि डैश बोर्ड के माध्यम से अधिकारियों द्वारा प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा की जा सके। श्री चौधरी ने सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को मिलने का समय भी निर्धारित कर इसकी सूचना कार्यालय के सूचना पटल पर लगाने कहा। श्री चौधरी द्वारा उद्योगों द्वारा फ्लाई ऐश के परिवहन एवं निपटारे हेतु नियमों के पालन कड़ाई से कराने हेतु निर्देश दिया गया। फ्लाई ऐश लाने ले जाने के लिये उपयोग किये जा रहे वाहनों में जी.पी.एस. सिस्टम व जियो टेगिंग के उपयोग के निर्देश दिये, जिससे कि फ्लाई ऐश इधर-उधर न फेका जा सके। श्री चौधरी ने क्षेत्रीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि उद्योगों को प्रदान किये गये पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों में शामिल वृक्षारोपण की शर्त का पूरी तरह से पालन सुनिश्चित कराये तथा उद्योगों केवल वृक्षारोपण करने तक सीमित ना रहें अपितु लगाये गये पौधों के संवर्धन हेतु भी निरीक्षण का एक सिस्टम तैयार किया जाये।

सभी क्षेत्रीय अधिकारियों की यह जिम्मेदारी है कि वें अपने-अपने क्षेत्रों में सघन वृक्षारोपण करायें एवं इन पेड़ों में पीपल, नीम आदि पेड़ शामिल किये जाए। श्री चौधरी ने वाहन प्रदूषण नियंत्रण पर जोर देते हुये निर्देशित किया कि सभी क्षेत्रीय अधिकारी वाहन प्रदूषण मापन प्रदूषण जाँच सिस्टम को शक्तिशाली बनाये एवं वाहन प्रदूषण मापन केन्द्रो की समय-समय पर बैठक आयोजित करें। श्री चौधरी ने अधिकारियों से चर्चा में कहा कि पर्यावरण संरक्षण में उठाये गये कदमों को और कैसे प्रभावी बनाया जा सकता है तथा आने वाली चुनौतियों से कैसे निपटा जा सकता है, इस पर भी विचार करें। उन्होनें जल एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत किये जा रहे कार्यों की समीक्षा की।

चौधरी ने परिसंकटमय एवं अन्य अपशिष्ट नियम के प्रावधानों का पालन, जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं नियम, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन एवं नियम, ई अपशिष्ट प्रबंधन एवं नियम, निर्माण विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन एवं नियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, उद्योगों, खदानों, संस्थानों के चिमनी उत्सर्जन, परिवेशीय वायु मापन, उपचारित दूषित जल गुणवत्ता का मापन कार्य, राष्ट्रीय जल गुणवत्ता मापन कार्यकम के अंतर्गत प्राकृतिक जल स्त्रोतों, परिवेशीय वायु गुणवत्ता के मापन कार्यों की भी समीक्षा की।

श्री चौधरी ने कहा की शीघ्र ही सभी स्टेक होल्डर्स की बैठक ली जायेगी एवं प्रदूषण नियंत्रण सुधार कार्यों में बुद्ध जीवी वर्ग की मदद ली जायेगी।

चौधरी ने मंडल की पद संरचना की समीक्षा करते हुये मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में पुनः पदसंरचना निर्धारित करने के निर्देश दिये। उनके द्वारा सभी कर्मचारियों के डेटा को एच.आर. एम.एस. सिस्टम में एक माह के भीतर अपलोड करते हुये ऑनलाईन कार्यवाही के निर्देश दिये गये। बैठक में मंडल की अध्यक्ष एवं सचिव, आवास एवं पर्यावरण विभाग सुश्री आर. शंगीता एवं मंडल के सदस्य सचिव पी. अरूण प्रसाद भी उपस्थित थे।

विश्व शांति के लिए विहंगम योग संत-समाज की राष्ट्रव्यापी संकल्प यात्रा होगी लाभदायी : साय

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय आज राजधानी रायपुर के पं. दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में विहंगम योग संत-समाज द्वारा आयोजित स्वर्वेद कथा में शामिल हुए। उन्होंने संत प्रवर श्री विज्ञानदेव जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त किया और उनके पावन सानिध्य में जय स्वर्वेद कथामृत का श्रवण किया। इस अवसर पर कोंडागांव विधायक सुश्री लता उसेंडी भी उपस्थित थीं। गौरतलब है कि विहंगम योग संत समाज द्वारा स्थापना के शताब्दी समारोह के पावन अवसर के निमित्त कन्याकुमारी से कश्मीर तक की राष्ट्रव्यापी संकल्प यात्रा आयोजित की जा रही है। इसी कड़ी में राजधानी रायपुर में जय स्वर्वेद कथा आयोजित की गई थी।

मुख्यमंत्री श्री साय ने इस अवसर पर कहा कि यह परम सौभाग्य की बात है कि माता कौशल्या की धरती और भगवान राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ में हमें संत प्रवर श्री विज्ञान देव जी महाराज के पावन सानिध्य का सुअवसर मिला है। उन्होंने कहा कि पूज्य संतों का आशीर्वाद सदैव प्रदेश पर बना रहे और लोगों के जीवन में खुशहाली और समृद्धि आए। उन्होंने कहा कि संत जी विहंगम योग संत समाज की स्थापना के शताब्दी वर्ष के अवसर पर कन्याकुमारी से कश्मीर की यात्रा कर रहे हैं। संत श्री विज्ञान देव जी ने 15 दिवस में छत्तीसगढ़ के 13 जिलों की यात्राएं की। श्री साय ने कहा कि विश्व शांति एवं कल्याण के लिए यह यात्रा निश्चित ही लाभदायी होगा। मुख्यमंत्री ने समाज कल्याण के लिए विहंगम योग संत समाज के प्रयासों की प्रशंसा की।

विधायक श्रीमती लता उसेंडी ने कहा कि विहंगम योग संत समाज के पूज्य संतों का आशीर्वाद हमेशा से छत्तीसगढ़ को मिलता रहा है इनके पावन प्रवास की हम सभी प्रतीक्षा कर रहे थे। छत्तीसगढ़ के सुदूर अंचलों में समाज के पूज्य संतों ने आध्यात्मिक अलख जगाने के लिए अनेक प्रयास किए हैं। विहंगम योग संत समाज के संत प्रवर श्री विज्ञान देव जी महाराज ने राष्ट्रव्यापी संकल्प यात्रा के उद्देश्य की जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि कन्याकुमारी से प्रारंभ हुई यह यात्रा कश्मीर तक अपने पावन संकल्पों के साथ पूरी होगी। उन्होंने कहा कि इसी पड़ाव में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से इस संकल्प यात्रा को गति देने का कार्य किया गया है।

हरेली की खुशियां बिखरेंगी मुख्यमंत्री निवास में

रायपुर। हरेली के उल्लास को संजोने मुख्यमंत्री निवास परंपरागत तरीके से सजाया जा रहा है। हरेली के दिन 4 अगस्त को यहां किसान भाइयों के हल खुरपी नजर आयेंगे। गेड़ी में लोगों का उत्साह नजर आयेगा। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय एवं उनके मंत्रिमंडल सहयोगी तथा अतिथिगण इस अवसर पर हरेली का आनंद लेंगे और परंपरागत तरीके से पूजा अर्चना करेंगे। हरेली तिहार के मौके पर मुख्यमंत्री सबसे पहले विधिविधान से कृषि उपकरणों की पूजा करेंगे। हरेली के अवसर पर पूरे छत्तीसगढ़ अंचल में लोग अपने अपने लोकगीत गाते हैं और नृत्य करते हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को अंचल के सभी नृत्य एवं लोकगीतों का आयोजन करने कहा है ताकि पूरा छत्तीसगढ़ समवेत रूप में मुख्यमंत्री निवास में अपने पूरे सांस्कृतिक वैविध्य में नजर आये।

सांसद पांडेय में रेल सुविधाओं को लेकर कांग्रेस पर दागे सवाल

नई दिल्ली/रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के सांसद संतोष पांडेय ने रेल सुविधाओं के विस्तार की दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों को ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि रेल और यात्री सुविधाओं के विस्तार के जितने काम पिछले 10 वर्षों में भाजपानीत राजग सरकार के कार्यकाल में हुए हैं, वे बेमिसाल हैं। सांसद पांडेय ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि उनके लोग अपने शासनकाल के नाकारापन से शर्मिंदा होकर अब तथ्यहीन बातें करके देश में भ्रम और अराजकता फैलाने में लगे हैं। सांसद पांडेय ने कहा कि मोदी सरकार और रेल मंत्रालय रेल और यात्रियों की सुविधा बढ़ाने और रेल दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए गंभीरता से काम कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस कुंठा, शर्म और बौखलाहट में मिथ्या प्रलाप करके देश को गुमराह करने में लगी है।

उन्होंने कांग्रेस से सवाल पूछते हुए चुनौती दी है-

- कांग्रेस को यह बताना चाहिए कि उनके 60-65 साल के कार्यकाल में उन्होंने कितने नए रेलवे ट्रैक बिछाए और प्रति वर्ष कितने किलोमीटर रेलवे ट्रैक बनाए?
- कितने रेलवे ट्रैक्स का इलेक्ट्रिफिकेशन किया?
- कांग्रेस और कांग्रेसनीत गठबंधन की सरकारों के कार्यकाल में कितने स्टेशनों को मॉडर्न बनाया?
- कितनी रेलगाड़ियों की स्पीड बढ़ाई? कितनी नई रेलगाड़ियाँ चलाई?
- यात्रियों की सुविधाओं में क्या विस्तार किया?
- बजट का कितना प्रतिशत हिस्सा रेल और यात्री सुविधाओं के विस्तार के लिए रेलवे को दिया?
- केंद्र में दशकों शासन करने वाली कांग्रेस ने रेलवे के लिए छत्तीसगढ़ को कितना बजट दिया?

सांसद पांडेय ने कहा कि कांग्रेस को इस बारे में सत्य और तथ्य के साथ आँकड़े जारी करने की हिम्मत होनी चाहिए। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस ने रेलवे में भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं किया और आज जब प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार और रेल मंत्रालय तेजी से सुविधाओं के विस्तार और विकास के काम कर रहे हैं.

ननि जनसमस्या निवारण शिविरः 6 दिनों में मिले साढ़े 26 हजार आवेदन

रायपुर। प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में विगत 27 जुलाई से प्रारंभ जनसमस्या निवारण पखवाड़ा का बेहतर प्रतिसाद नागरिकों को मिल रहा है। पखवाड़ा के पहले छह दिनों (27 जुलाई से 1 अगस्त तक) में प्रदेश भर में कुल 26 हजार 513 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 4442 आवेदनों का मौके पर ही निराकरण कर लोगों की समस्याएं दूर की गई हैं। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जनसमस्या निवारण पखवाड़ा की समीक्षा कर सभी आयुक्तों, मुख्य नगर पालिका अधिकारियों तथा क्षेत्रीय संयुक्त संचालकों को

यथासंभव ज्यादा से ज्यादा आवेदनों को मौके पर ही निराकृत करने के निर्देश दिए हैं। उप मुख्यमंत्री श्री साव ने प्रदेश के सभी 184 नगरीय निकायों में वार्डवार आयोजित जनसमस्या निवारण शिविरों में नागरिकों को जनकल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित करने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने शिविरों में प्राप्त आवेदनों का डॉटा-बेस तैयार करने को कहा है, ताकि इनकी निरंतर मॉनीटरिंग सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों और सभी क्षेत्रीय संयुक्त संचालकों को शिविर स्थलों का औचक निरीक्षण कर वहां नागरिकों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं और व्यवस्थाओं की गुणवत्ता की जांच के निर्देश दिए हैं।

छत्तीसगढ़/राजधानी
प्रमुख समाचार

रायपुर से हैदराबाद के लिए शुरू होगी सीधी उड़ान

रायपुर। हवाई यात्रियों को नई उड़ानों की सौगात मिलनी शुरू हो गई है। इसके तहत इंडिगो एयरलाइंस ने रायपुर से हैदराबाद के लिए नई उड़ान शुरू करने की घोषणा की है। यह नई उड़ान 23 सितंबर से शुरू होगी। इसके साथ ही रायपुर से प्रयागराज के लिए भी इंडिगो एयरलाइंस की नानस्?टॉप फ्लाइट 16 अगस्त से शुरू हो रही है। विमानन अधिकारियों के अनुसार फ्लाइट क्रमांक 6ई 6263 हैदराबाद से रायपुर के लिए दोपहर 2.20 बजे बजे उड़ान भरेगी और 3.56 बजे रायपुर पहुंचेगी। इसके बाद फ्लाइट क्रमांक 6ई6327 रायपुर से हैदराबाद के लिए शाम 4.25 बजे उड़ान भरेगी और 5.50 बजे हैदराबाद पहुंचेगी। ट्रैवल्स संचालकों का कहना है कि त्योहारी सीजन में और भी कई शहरों के लिए रायपुर से उड़ान शुरू हो सकती है। इनमें सबसे पहले रायपुर से जयपुर उड़ान और रायपुर से राजकोट के लिए भी उड़ान शुरू हो सकती है। इन दिनों रायपुर विमानतल से हवाई यात्रियों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसके चलते वहां नई से नई सुविधाएं भी की जा रही है।

नियद नेल्लानार योजना, सुदूरवर्ती ग्रामों के विकास के लिए वरदान

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की पहल पर माओवाद से प्रभावित इलाकों में नागरिकों को मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने तथा समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए शुरू की गई नियद नेल्लानार योजना आपका आदर्श ग्राम से लोगों को काफी सहूलियत मिल रही है। प्रदेश के पांच जिलें सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर और कांकेर में स्थापित सुरक्षा कैम्पों के आसपास के पांच किलोमीटर की परिधि में ग्रामीणों को राज्य और केन्द्र शासन द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ दिलाया जा रहा है। आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक विकास मंत्री श्री रामविचार नेताम ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय सरकार की महत्वकांक्षी नियद नेल्लानार योजना का शत्-प्रतिशत क्रियान्वयन करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। मंत्री श्री नेताम ने कहा है कि प्रदेश के सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत जनसंख्या को सभी मूलभूत सुविधाएं दिलाने एवं उन्हें राष्ट्र की मुख्यधारा में जोड़ने में नियद नेल्लानार योजना एक वरदान साबित होगी। नियद नेल्लानार से तात्पर्य आपका आदर्श ग्राम है अर्थात् ऐसा ग्राम जहां पर निवासरत जनसंख्या को सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा चुकी हैं और अब वह अन्य क्षेत्रों की तरह विकास के पथ पर आगे बढ़ने को अग्रसर है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा भी था ''कि यदि देश का विकास करना है

रोका-छेका बंद होने से गायें मर रहीं है, किसान परेशान हो रहे है

रायपुर। बलौदा बाजार के निकट मरदा गांव में दम घुटने से 20 गौवंशीयों की मृत्यु पर कड़ी प्रतिक्रिया वक्त करते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा कहा है कि मरदा गांव में गायो की हत्या के लिये गांव वाले नहीं बल्कि भाजपा सरकार जिम्मेदार है। जब से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से रोका-छेका का बंद कर दिया गया है, गोठानो को भी दुर्भावना पूर्वक बंद कर दिया गया, किसान खुली चराई से परेशान हैं, राहगीर सड़कों पर बैठे मवेशियों के झुंड से दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं और गाएं भी सड़कों पर भारी वाहनों से रौंदे जानें से बेमौत मरने मजबूर हैं। बलौदा बाजार की घटना भाजपा सरकार के निकम्मेपन का परिणाम है। भारतीय जनता पार्टी की साय सरकार की ना कोई नीति है, ना नियत, दुर्भावना और पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर गोठान योजना तो बंद कर दिए लेकिन विकल्प के तौर पर साय सरकार के गौ अभ्यारण का जुमला केवल कागजी है, धरातल पर अव्यवस्था सर्वविदित है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि भाजपा की सरकार गौ हत्यारी सरकार है। गाय के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के नेता केवल राजनीति करते हैं, काम नहीं करते बल्कि उल्टे बीफ कंपनियों से चंदा खाते हैं।

बाड़े में हुई 14 पशुओं की मौत, हिरासत में चार ग्रामीण

बलौदाबाजार. जिले के तहसील लवन क्षेत्र ग्राम पंचायत मरदा में एक बाड़ा के अंदर 14 पशु मृत हालत में मिली है, जिसमें 10 बछड़ा एवं 04 गाय शामिल हैं. इसकी पुष्टि कलेक्टर दीपक सोनी के निर्देश पर बनी जांच दल ने की है. इस मामले में पुलिस ने लापरवाही बरतने वाले चार लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर चारों को हिरासत में लिया है. जांच दल ने बताया कि आज सुबह सूचना मिली कि थाना लवन क्षेत्र के ग्राम मरदा के एक बाड़ा में कुछ मवेशियों की मौत हो गई है, जिससे तेज दुर्गंध आ रही है. इस सूचना पर जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम घटना स्थल ग्राम मरदा पहुंचा. घटना स्थल के एक कमरे में मवेशी मृत हालत में थे, जिसमें से तेज दुर्गंध आ रही थी. साथ ही मवेशियों के दो-तीन दिन पहले मृत होने की संभावना जताई गई. घटना के संबंध में ग्रामवासियों से पूछताछ पर पाया गया कि ग्राम में फसलों की सुरक्षा के लिए घुमंतू मवेशियों को रखने एक मकान को चिन्हित किया गया था, जिसमें घुमंतू मवेशियों को पकड़कर रखा जाता था. इनकी देखरेख के लिए ग्राम स्तर पर ही एक निजी समिति बनाई गई थी.

कृषि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 437 सीटें आबंटित

रायपुर. इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत विभिन्न महाविद्यालयों में संचालित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की 458 सीटों में से 437 सीटें काउंसलिंग से चयनित अभ्यर्थियों को आबंटित कर दी गई है. संयुक्त प्रवेश परीक्षा-2024 की प्रावीण्य सूची के आधार पर अभ्यर्थियों को प्रोविजनल सीट एवं महाविद्यालय का आबंटन किया जा चुका है. चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का परीक्षण कृषि महाविद्यालय, रायपुर में किया जा रहा है. आबंटित प्रोविजनल सीट को सुरक्षित करने अभ्यर्थियों को 01 से 03 अगस्त के मध्य ऑनलाइन फीस जमा करना अनिवार्य होगा. सीट सुरक्षित करने के पश्चात अभ्यर्थी सीट निरस्त करना चाहता है और आगे किसी भी प्रक्रिया में भाग नहीं लेना चाहता तो इसके लिए 01 से 04 अगस्त के मध्य सीट निरस्त करना होगा. रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए 6 एवं 7 अगस्त को स्पॉट काउंसलिंग और 8 अगस्त को कन्वर्सन काउंसलिंग की जाएगी

चरण पादुका योजना को लेकर ओपी चौधरी ने कहा- ये माफिया राज वाले लोग हैं

रायपुर. छत्तीसगढ़ की साय सरकार चरणपादुका योजना फिर से शुरू करने जा रही है. इसे लेकर प्रदेश में सियासत तेज है. एक तरफ कांग्रेस इस योजना का विरोध कर रही है. वहीं वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने योजना को लेकर प्रदेश की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर पलटवार करते हुए पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर माफिया राज का आरोप लगाया है. वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में तेंदूपत्ता हरा सोना है. हमारी सरकार ने तेंदूपत्ता के प्रति मानक बोरा की दर को 4 हजार से 5500 करने का काम कर आदिवासी भाई-बहनों को सशक्त बनाया. कांग्रेस शासन में तेंदूपत्ता संग्राहकों को न बीमा का लाभ मिला और न बोनस का. चरण पादुका योजना फिर से शुरू कर रहे हैं, तो कांग्रेस को तकलीफ हो रही है. वित्त मंत्री ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि यह कांग्रेस के लोग तेंदूपत्ता की खरीदी मात्र दिखावे के लिए करते थे. बीमा की योजना, स्कॉलरशिप की योजना, चरण पादुका की योजना, यह सब इन्होंने बंद कर दिया था. आदिवासी भाई बहनों के पैर में कांटे ना गड़े, इसके लिए विष्णुदेव साय की सरकार अगर चरण पादुका बांटने का निर्णय लेती है, तो जिस कांग्रेस ने ना बीमा दिया, न स्कॉलरशिप दिया, ना चरण पादुका दिया ना कोई योजना का लाभ दिया और ना ही कोई बोनस दिया ऐसे लोगों को क्यों आज पेट में दर्द हो रहा है? इसका जवाब दें आज.

उन्होंने कहा कि जो भी नियम कानून है, उसके तहत ही हमारी सरकार काम करती है. यह वो लोग हैं (कांग्रेस) जो जैम पोर्टल, जिसमें पूरी पारदर्शिता के साथ खरीदी होती है, उसे बंद करके भाई भतीजावाद करने के लिए गलत लोगों को शामिल करते हैं.

गुणवत्ताहीन सामान खरीदने के लिए जिन्होंने सिस्टम बनाया, वह लोग आज सवाल उठाएंज यह किसी को हजम नहीं होता है. यह लोग माफिया राज चलने वाले लोग थे.

छत्तीसगढ़ में हरियाली के त्यौहार को हरेली तिहार कहते हैं. इसे लेकर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि हरियाली का त्योहार हम सभी के लिए बहुत ही खुशी और हर्ष का त्यौहार है. यह फसल (किसानी) से बहुत ही गहराई से जुड़ा हुआ त्यौहार है. बचपन से लेकर आज तक हम हरियाली का त्योहार बहुत ही हर्षोल्लास के साथ धूमधाम से मनाते आ रहे हैं इस साल भी मैं 4 अगस्त को हरेली का त्यौहार जोरदार तरीके से मनाऊंगा.

उपमुख्यमंत्री शर्मा ने दिव्यांगजनों को बैटरी चलित मोटराइज्ड ट्रायसायकल और व्हील चेयर का किया वितरण

रायपुर। उपमुख्यमंत्री कार्यालय परिसर, कवर्धा में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम के दौरान छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने 14 दिव्यांगजनों को बैटरी चलित मोटराइज्ड ट्रायसायकल, दो दिव्यांगजनों को ट्रायसायकल, और एक दिव्यांगजन को व्हील चेयर का वितरण किया।

इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने कहा, प्रदेश की विष्णुदेव साय सरकार समावेशी विकास को प्राथमिकता दे रही है। हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि दिव्यांगजनों का जीवन सुगम और सशक्त बने। इस पहल के माध्यम से, न केवल उनकी दैनिक गतिविधियों में सुविधा होगी, बल्कि वे सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों में भी अधिक सक्रिय भागीदारी कर सकेंगे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय जनप्रतिनिधि और अधिकारीगण उपस्थित थे। उपमुख्यमंत्री ने इस अवसर पर दिव्यांगजनों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया और उनके लिए चलाए जा रहे विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.